खण्ड-272, अंक-3
मंगलवार, 30 ज्येष्ठ, शक संवत् 1889
(20 जून, 1967 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 272 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६७

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	१–५
प्रश्नोत्तर	५–३५
सर्वश्री लोटनराम, रामेश्वर सहाय, जगदीशसिंह तथा माधोनारायण मुद्गल के निधन पर शोकोद्गार	३५–३७
सदन के अवशिष्ट कार्य-क्रम को कार्य सूची में सम्मिलित न करने तथा सरकार के कथित वैधानिक रूप से गठित न होने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न ..	३७–४३
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् परिषद् तथा न्यायाधिकरण के समक्ष अपीलों के लिये अवधि) नियमावली, १९६६ (सदन के पटल पर रखी गयी)	४३
उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार और निपातन) नियमावली, १९६६ (सदन के पटल पर रखी गयी)	४३–४४
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (द्वितीय संशोधन) नियमावली, १९६६ (सदन के पटल पर रखी गयी)	४४
उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, १९६७ (सदन के पटल पर रखी गयी)	४४
उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (पांचवां संशोधन) नियमावली, १९६७ (सदन के पटल पर रखी गयी)	४४–४५
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (आवास आयुक्त की सेवा की शर्तें) नियमावली, १९६६ (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	४५
उत्तर प्रदेश नगर महापालिका सेवा (संशोधन) नियमावली, १९६६ (सदन के पटल पर रखी गयी)	४५
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (वेतन या मजदूरियों से कटौती करके किराये की वसूली के लिये अनुबन्ध) नियमावली, १९६७ (सदन के पटल पर रखी गयी)	४५
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (परिषद् के अधिकारियों तथा सेवकों पर आवास आयुक्त द्वारा पर्यवेक्षण तथा नियन्त्रण) नियमावली, १९६६ (सदन के पटल पर रखी गयी)	४५-४६
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (संविधाओं और हस्तान्तरण–पत्रों का निष्पादन) नियमावली, १९६६ (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	४६
उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९६७ (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	४६
सदन के परिसर में कांग्रेस के अवंटित कमरे को यू० पी० सेक्रेटेरियट मिनिस्टीरियल) आफिसर्स एसोसियेशन की बैठक के लिये दिये जाने के संबंध में श्री चन्द्रभानु गुप्त के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	४६-४८

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, २० जून, १९६७

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ, में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री जगदीश शरण अग्रवाल की अध्यक्षता म आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य--३९४

अंगनेलाल, श्री
अख्तर अली खाँ, श्री
अजीतप्रताप, श्री
अठई राम, श्री
अतीकुरहमान, श्री
अनन्तराम, श्री
अब्दुल खालिक, श्री
अब्दुल मुईज खाँ, श्री
अयोध्या प्रसाद, श्री (झाँसी)
अयोध्या प्रसाद, श्री (मिजापुर)
अयोध्या प्रसाद आर्य, श्री
अर्जुन, श्री
अवधेशप्रताप मल, श्री
अवेद्यनाथ, श्री
अश्वनी कुमार, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी "राकेश", श्री
अहमदउल्ला खाँ, श्री
आत्मा, श्री
आनन्द सिंह, कुंवर
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रपालसिंह, श्री
इन्द्रमणी श्री
इन्द्र मोहिनी, श्रीमती
इन्द्रलाल, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयप्रताप, श्री
उदयवीरसिंह, श्री
उदितनारायण, श्री
उमादत्त, श्री
ऊदल, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकार सरन, श्री
ओम्प्रकाश, श्री
ओम्प्रकाश सिंह, श्री
कन्धईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री (इटावा)
कन्हैयालाल, श्री (झाँसी)
कन्हैयालाल बाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलाप्रसाद, श्री (जौनपुर)
कमलाप्रसाद, श्री (बहराइच)
करनसिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणसिंह, श्री
कामतासिंह, श्री
कालीचरण, श्री
काशीनाथ, श्री
किशनलाल, श्री
किशनसिंह, श्री
किशुनलाल, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री

केदार राज जंगबहादुर राणा, श्री
केशरीलाल, श्री
केशवदेव, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमा, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (एटा)
गंगा राम, श्री
गंगास्वरूप भटनागर, श्री
गजाधर, श्री
गया प्रसाद, श्री (उपनाम मास्टर साहब)
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाशंकर, श्री
गिरधारीलाल चौधरी
गिरिराजसिंह, श्री
गिरीशचन्द्र तिवारी, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोपालदत्त ओझा, श्री
गोपाल राम दास, श्री
गोविन्दनारायण तिवारी, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
गौरीराम, श्री
गौरीशंकर सराफ, श्री
गौरीसिंह राठौर, श्री
घनश्याम गिरि, महन्त
घनश्यामदास, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्र किशोर, श्री
चन्द्र कुमार श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रशेखर, श्री
चन्द्रशेखरसिंह, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चरणसिंह, श्री
चेतराम पचपेड़ा, श्री
चेतराम वर्मा, श्री
जंगबहादुर , श्री
जगतसिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीशनारायण त्रिपाठी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगपतसिंह, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुरहमान, श्री
जयनारायणसिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह, श्री
जवाहरलाल, डाक्टर
जवाहरलाल जाटव, श्री
जवाहिरलाल, श्री
जसोदानन्द, श्री
जानकीप्रसाद, श्री
जितेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
जियाउरहमान, श्री
जी० एस० चौधरी, श्री
जुगलकिशोर, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
जैदत्तसिंह, श्री
जैनराम, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकमसिंह, श्री
तिलक सिंह, श्री
त्रिवेणी, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दलबहादुरसिंह, श्री
दलसिंह, श्री
दशरथ, श्री
दीपंकर, आचार्य
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
दृगराजसिंह, श्री
देवराम, श्री
देवीचरण अग्निहोत्री, श्री
देवीदयाल सेन, श्री
देवीसहाय बाजपेयी, श्री
देवी सेवक, श्री
देवेन्द्रसिंह, कुंवर
देशराजसिंह, श्री
धनराज यादव, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मगजसिंह, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीरसिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री

ध्रुवकुमार, श्री
नन्हेलाल, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरवदेश्वर, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेमपालसिंह, श्री
नौनिहालसिंह, श्री
पब्बरराम, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पीतमसिंह, श्री
प्यारेलाल, श्री (अलीगढ़)
प्यारेलाल, श्री (मेरठ)
प्रतापनारायण तिवारी, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमदत्त, श्री
फारुक चिश्ती, श्री
फूलसिंह, श्री
बंशीधर, श्री
बजरंगबली, ब्रह्मचारी
बदनसिंह, श्री
बदलराम श्री
बद्रीप्रसाद अवस्थी, श्री
बनारसीदास, श्री
बलवीरसिंह, श्री (मेरठ)
बलवीरसिंह, श्री (फतेहगढ़)
बसन्तलाल, श्री (जालौन)
बसन्तलाल, श्री (लखनऊ)
बसन्तसिंह, श्री
बाबू बदरे श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल, श्री
बिशनलाल, श्री
बुधिराम, श्री
बृजकिशोर, श्री
बृजमोहन दास अग्रवाल, श्री
बेचनराम, श्री (मिर्जापुर)
बेचनराम, श्री (वाराणसी)
बेनीबाई, श्रीमती
बेनीसिंह अवस्थी, श्री
बैजनाथ, श्री (बलिया)
बैजनाथ, श्री (वाराणसी)
ब्रह्म श्रमरवमी
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वमं, श्री
भग्गूराम, श्री (उपनाम भुगुनाथ)
भारतसिंह चौहान, श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेशभूषण, श्री
भुगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भैरवदत्त धूलिया, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलाप्रसाद तिवारी, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मकसूद हुसैन, श्री
मदन मोहन मिश्र, श्री
मदनमोहनसिंह, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्नालाल, श्री
मन्नीलाल, श्री
मन्सादीन, श्री
मलिखानसिंह, श्री
महरमसिंह, श्री
महिपालसिंह, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्रप्रतापसिंह, कुंवर
महेशकुमार, श्री
माताप्रसाद, श्री
मारकण्डे, श्री
मुन्शीलाल चमार, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुरलीधर, श्री
मुलायमसिंह, श्री
मुल्कीराज, श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद महमूद अली खाँ, श्री
मुहम्मद रऊफ, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रसिंह, श्री (उपनाम लल्लन जी)

योगेश्वरप्रसाद, श्री
रईसउद्दीन, श्री
रघुनाथसिंह, श्री (आगरा)
रघुनाथसिंह, श्री (कानपुर)
रघुनाथसिंह, श्री (झाँसी)
रघुनाथसिंह वर्मा, श्री
रघुराज, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रफी मुहम्मद खाँ, श्री
रमाकान्त, श्री
रमाबल्लभ मिश्र, श्री
रमाशंकर अग्रवाल, श्री
रवीन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राज किशोर, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथ, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबली, श्री
राजबहादुर, श्री (जौनपुर)
राजबहादुर, श्री (सीतापुर)
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबहादुर द्विवेदी, श्री
राज राजेश्वर, श्री
राजाराम, श्री (आगरा)
राजाराम, श्री (देवरिया)
राजाराम, श्री (बलिया)
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम कपूर, श्री
राम अंजोर, श्री
रामआधार, श्री
रामआधीनसिंह, श्री
रामकरन, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर, श्री
रामकुमार, श्री
रामचन्द्र आजाद, श्री
रामचन्द्र जोशी, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरन दोहरे, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामदत्त, श्री
रामदास, श्री

रामदुलारे पटेल, श्री
रामदुलारे, श्री (रायबरेली)
रामदेव, श्री (गोंडा)
रामदेव, श्री (प्रतापगढ़)
रामनरेश पांडेय, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनाथ, श्री (मिर्जापुर)
रामनाथ, श्री (शाहजहांपुर)
रामनारायण, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
रामप्रसाद, श्री (आगरा)
रामप्रसाद, श्री (गढ़वाल)
रामप्रसाद, श्री (रायबरेली)
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री
रामबली मिश्र, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति "अंचल", श्री
रामरतन, श्री
रामलखन सिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामश्री राजपूत, श्री
रामसजीवन, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसेवक, श्री
रामस्वरूप, श्री (देहरादून)
रामस्वरूप, श्री (प्रतापगढ़)
रामस रूप वर्मा, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वरसिंह, श्री
रुस्तम सैटिन, श्री
रूप नाथ, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर, श्री
लटूरीसिंह, श्री
लाखन, श्री
लालकृष्ण कुमार पाल, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालबहादुर, श्री
वरमेश्वर पांडेय, श्री
वसी नकवी, श्री
विजय कुमार त्रिपाठी, श्री

विजयशंकरसिंह, श्री
विपिन बिहारी तिवारी, श्री
विशुनप्रतापसिंह, श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री (उपनाम झींगन साहू)
विश्वनाथसिंह, श्री
विष्णुस्वरूप, श्री
वीरबहादुर, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेश्वर त्यागी, श्री
शंकरसिंह, चौधरी
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शफकतजंग, श्री
शब्बीर हसन, श्री
शमीम आलम, श्री
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शीतलादीन, श्री
शीतलाप्रसाद सिंह, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्यामसिंह, श्री
श्रीनाथ, श्री
श्रीनारायण तिवारी, श्री
श्रीपति मिश्र, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री (वकील)
श्री शंकर शर्मा, श्री (उपनाम लालो शर्मा)
सईद अहमद, श्री
सत्यवीर, कुंवर
सन्तू, श्री
सरजूप्रसाद, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिकराम, श्री
सियाराम, श्री
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेव, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सुशीलकुमार विद्यार्थी, श्री
सोहनलाल, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिहरनाथ अग्रवाल, श्री (उपनाम हरी बाबू)
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीशचन्द्र, श्री
हरीशचन्द्रसिंह, श्री
हरीसिंह, श्री (बुलन्दशहर)
हरीसिंह, श्री (मेरठ)
हिम्मत बहादुर, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट– मन्त्री श्री मान सिंह वर्मा तथा मन्त्री श्री प्रभुनारायण सिंह भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, २० जून, १९६७

तारांकित प्रश्न

परगना खेड़ा-बझेड़ा को बिजली देने का कार्य

*१—श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सिंचाई मन्त्री को पता है कि जिला शाहजहांपुर की तहसील तिलहर के परगना खेड़ा-बझेड़ा में बिजली दिए जाने की स्कीम सरकार द्वारा मंजूर की जा चुकी है? यदि हां, तो कब तक बिजली पहुंच जाएगी और क्या सूखे की स्थिति को देखते हुए मन्त्री जो अविलम्ब बिजली पहुंचाने की कृपा करेंगे, जिससे १५० नलकप शीघ्र चालू हो जायं?

विद्युत् उपमन्त्री (श्री रामप्रसाद देशमुख)--

जिला शाहजहांपुर की तहसील तिलहर के परगना खेड़ा-बझेड़ा का विद्युतीकरण तभी सम्भव हो सकेगा, जबकि विद्युतीकरण के लिए लाइनों तथा सब-स्टेशन के निर्माण का कार्य पूरा हो जाय। यह कार्य इस वर्ष प्रारम्भ होने की सम्भावना है।

उक्त कार्य पूर्ण होने पर नलकूप आदि को भी विद्युत् दी जा सकेगी।

श्री सुरेन्द्र विक्रम--

क्या माननीय मन्त्री ने इस विषय में निश्चित आदेश दे दिए हैं कि कार्य प्रारम्भ कर दिया जाय?

सिंचाई मन्त्री (श्री टम्बरेश्वर प्रसाद)--

एक सब-स्टेशन बनना है, जिसके बाद ही इस क्षेत्र का विद्युतीकरण हो सकता है। उसके लिए सामग्री एकत्रित की जा रही है और शीघ्र निर्माण हो जायगा।

श्री मंगलाप्रसाद तिवारी (जिला इलाहाबाद)--

जहां सब-स्टेशन बन गए हैं क्या वहां मन्त्री जी ऐसी सुविधा देने की कृपा करेंगे कि जल्दी कनेक्शन मिलकर सिंचाई का कार्य आरम्भ हो जाय?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद--

अगर माननीय सदस्य किसी खास जगह का पूछेंगे तो उसकी जानकारी उनको करा दी जायगी।

श्री चन्द्रशेखर (जिला वाराणसी)--

सामग्री कब तक उपलब्ध हो जायगी और वह कब तक बन जायगा?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद--

इस वित्तीय वर्ष में सामग्री उपलब्ध करने का काम प्रारम्भ होगा।

फरीदपुर ब्रांच का बझेड़ा रजवहा

*२--श्री सुरेन्द्र विक्रम--

क्या सिंचाई मन्त्री को यह पता है कि जिला बरेली की फरीदपुर ब्रांच से जो बझेड़ा रजबहा निकला है वह राज्य सरकार द्वारा एक्टेंशन और रिमाडलिंग के लिए मंजूर किया जा चुका है? यदि हां, तो कब तक बन जायेगा और इससे किन-किन ग्रामों को लाभ होगा?

श्री रामप्रसाद देशमुख--

जी नहीं, बझेड़ा रजबहे के एक्सटेंशन तथा रिमाडलिंग की योजना धनाभाव के कारण चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल में मंजूर नहीं की जा सकी है।

सम्बन्धी प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुरेन्द्र विक्रम--

मैंने यह प्रश्न ६५ के प्रथम सत्र में उस समय के सिंचाई मन्त्री से किया था और यह उत्तर मिला था कि रिमाडलिंग होगा और लाभान्वित होने वाले ग्रामों की सूची भी दी गई थी। क्या वह प्लान काट दिया गया है या कोई दूसरी बात हुई है?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद--

सूचना की आवश्यकता है।

चौथी पंचवर्षीय योजना में नलकूप

*३--श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर) तथा श्री अश्विनी कुमार (जिला गोरखपुर)--

क्या सरकार कृपया बताएगी कि अगले वित्तीय वर्ष सन् १९६७-६८ में प्रदेश के प्रत्येक जिले में कितने नए ट्यूबवेल तैयार किए जायेंगे ?

श्री रामप्रसाद देशमुख--

यह मामला अभी शासन के विचाराधीन है।

श्री अश्विनी कुमार--

वर्ष के ३ महीने तो बीत गए हैं, यह कब तक विचाराधीन रहेगा ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद--

नए वर्ष का ट्यूबवेल का कार्य हम सितम्बर-अक्तूबर से प्रारम्भ करते हैं। तब तक इसका विचार पूर्ण हो जाने की सम्भावना है।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)--

कृपया मन्त्री जी इतना ही बतला दें कि १९६७-६८ में कितने नए ट्यूबवेल लगेंगे या बनाए जावेंगे ?

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद--

इस वर्ष ११० नए ट्यूबवेल बनाने की योजना प्लानिंग कमीशन की टीम से निश्चित हुई है।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)--

प्रदेश में खाद्यान्न की कमी को देखते हुए क्या मन्त्री जी इस बात की कोशिश करेंगे कि इस बीच में जून-जुलाई में ही नए ट्यूबवेल लगाए जावें ताकि आगे अगर सूखा हुआ तो धान और रबी की फसल को पानी दिया जा सके ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद--

ट्यूबवेल बनाने का काम निरन्तर चलता रहता है। इस समय हम उन ट्यूबवेलों पर काम कर रहे हैं जिन पर पुनर्निर्माण होना है। हमारे रिग गैरह सब काम में लगे हुए हैं। जब पुराने ट्यूबवेल तैयार हो जावेंगे तो नए ट्यूबवेलों के कार्य को लिया जायगा।

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)--

जो ट्यूबवेल एप्रूव हो गए हैं और जिनको जून के पहले लगाना चाहिए था उनके न लगाने का क्या कारण है, जैसा कि मैंने मन्त्री जी के पास एक आवेदन-पत्र भी दिया था और उन्होंने आश्वासन भी दिया था ?

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद--

नए ट्यूबवेलों की योजना अभी विचाराधीन है।

श्री राममूर्ति (जिला बरेली)--

क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि पिछले वित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा कितने नलकूप बनाए गए ?

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद--

इसके लिए नोटिस की जरूरत है।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि ११० नलकूपों में से कितने नलकूप अलीगढ़ जिले को देने का विचार है ?

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद--

यह प्रश्न विचाराधीन है।

श्री सोहनलाल धुसिया (जिला बस्ती)--

क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि ट्यूबवेल्स सिंक करते समय सूखाग्रस्त इलाकों को प्रायरिटी दी जायगी, यदि हां, तो किस प्रतिशत में ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद--

प्रदेश के काफी भागों में सूखा है। उनके लिए प्रायरिटी निर्धारित करने का प्रश्न भी सरकार के सामने है।

श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)--

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि ये ११० नलकूप प्राइवेट फर्मों द्वारा लगाए जायेंगे अथवा सरकारी विभाग द्वारा ?

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद--

इनको सरकार अपने कर्मचारियों और अपने साधनों से लगाएगी।

श्री राम मूर्ति--

क्या सिंचाई मन्त्री जी यह बतायेंगे कि चौथी पंचवर्षीय योजना में कुल कितने नलकूप सरकार के द्वारा लगाये जायेंगे, इस वर्ष में जो ११० नलकूप लगाये जायेंगे, उनमें से कितने कितने किस जिले में लगाये जायेंगे तथा मंजूरशुदा नलकूपों का लगाया जाना क्यों बन्द कर दिया गया है ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद--

चौथी पंचवर्षीय योजना में १४० नलकूप लगाने का विचार है। किस जिले में कितने नलकूप लगाये जायेंगे, इस पर अभी विचार हो रहा है।

इलाहाबाद जिले के लिये नलकूप

*४--श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)--

क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि जिलाधीश इलाहाबाद ने कितने नलकूप इलाहाबाद के जिले को शीघ्र दिये जाने की मांग फरवरी, मार्च, १९६७ में की है ? तथा उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री रामप्रसाद देशमुख--

मार्च, १९६७ में जिलाधीश, इलाहाबाद ने चायल और मूरतगंज विकास खंडों में १०० नलकूप लगाये जाने का सुझाव दिया था। इस पर विचार किया जा रहा है।

श्री नाथूराम शिक्षक--

मैं यह बात जानना चाहता हूं कि तहसील मंझनपुर का जो निर्वाचन क्षेत्र है वह हमेशा से छोड़ा गया है, वह कांग्रेस हुकूमत के जमाने में भी बड़े कार्यों से वंचित रहा है तो क्या मन्त्री जी अब वहां नलकूपों की व्यवस्था करने पर विचार करेंगे और उस में मंझनपुर के इलाके को भी शामिल करने की कृपा करेंगे ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

मैंने तो समस्त इलाहाबाद जिले की बात कही है और अभी नलकूपों के लिए कोई स्थान निर्धारण नहीं हुआ है, समस्त जिले में से मांग है जहां शासन जरूरी समझेगा वहां जरूर देगा, उनका स्थान वहां की स्थानीय समिति नियत करेगी, उस में वहां का भी ध्यान रखा जायगा ।

(श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री अध्यक्ष—

मैं सामूहिक रूप में एक क्षमा याचना कर लूं कि अभी कुछ माननीय सदस्यों के नामों से मेरा पूर्ण परिचय नहीं हो पाया है, आवश्यकता होने पर मैं नाम पूछ लूंगा और इस कमी को पूरा करने का मैं प्रयत्न कर रहा हूं ।

श्री भीखा लाल (जिला उन्नाव)—

एक रोज आप श्रीमन्, सब को चाय पर बुला लीजिये, तो यह दिक्कत दूर हो जायगी ।

श्री अध्यक्ष—

एक रोज में तो नहीं कई रोज में बुलाने का प्रयत्न किया जा सकता है ।

श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)—

इस सम्बन्ध में जिलाधीश, इलाहाबाद ने जो योजना प्रस्तुत की है उसमें मेजा तहसील का जो प्रभावित इलाका है, उसके लिए कोई विशेष प्रकार की आयोजना की गयी है ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

इस के लिए तो नोटिस की आवश्यकता है, पूरे प्रदेश के लिए ११० नलकूपों की योजना है, किसी एक स्थान को १०० नलकूप मिलने की कोई सम्भावना नहीं है, । जिलाधीश के सजेशन पर शासन विचार कर रहा है ।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

जिले में जो नलकूपों का स्थान निर्धारण करने के लिए समिति बनी है उस में जनता का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है केवल उस में अधिकारीगण ही बैठते हैं और जनप्रतिनिधित्व उस में न होने पर गलत स्थानों पर नलकूप लग जाते हैं तो क्या मन्त्री जी उसमें जनता के प्रतिनिधि भी रखवायेंगे ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

अभी इस समिति का नवनिर्माण हुआ है, अब इस को फिर से डिस्टर्ब करना उचित न होगा ।

श्री अध्यक्ष—

वह जानना चाहते हैं कि उस में जनप्रतिनिधि भी रहते हैं या नहीं ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

इस समय तो नहीं हैं ।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—

अब मन्त्री जी इधर से बोलते थे तो जोर से बोलते थे लेकिन अब क्या कुर्सी ने उनकी आवाज ढीली कर दी है ?

श्री अध्यक्ष--

उत्तर की जरूरत नहीं है, बिना उत्तर के भी बहुत सी बातें रह सकती हैं।

श्री धर्मवीर--

जिस कमेटी का अभी निर्माण हुआ है उस के कौन-कौन सदस्य हैं ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद--

इस के लिए सूचना की आवश्यकता होगी इस कमेटी का अध्यक्ष जिलाधीश होता है, और नलकूप, उद्योग, सिंचाई व जिला प्लानिंग अफसर आदि अधिकारी उस के सदस्य होते हैं।

गनगरी नाले से फसल को क्षति

*५--श्री कल्पनाथ सिंह--

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गनगरी नाला जो ब्लाक गगहा बरहलगंज तहसील, तहसील बांस गांव, जिला गोरखपुर में है और इस के पट जाने से लगभग ७ हजार एकड़ की फसल को नुकसान होता है ? यदि हां, तो इस नाले को खोदने की क्या व्यवस्था हो रही है ?

श्री रामप्रसाद देशमुख--

गनगरी नाले के पट जाने से ४,६६६ एकड़ भूमि प्रभावित होती है न कि ७ हजार। इस नाले को खोदने की कोई व्यवस्था नहीं हो रही है क्योंकि ऐसा करना आर्थिक एवं तकनीकी दृष्टिकोण से उपयुक्त नहीं है।

श्री कल्पनाथ सिंह--

मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि जब सरकार की जानकारी में यह बात है कि ४,६६६ एकड़ भूमि का नुकसान होता है फसल का तो कौन सा आर्थिक दृष्टिकोण है जिस से सरकार इस नाले की खुदाई कराने में अपनी असमर्थता जाहिर करती है ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद--

यह योजना जब देखी गयी, तो पता चला कि नाले से आगे जिस क्षेत्र में हम को जल डालना है अर्थात् तैराना नाला उस नाले का जो स्तर है वह ऊंचा है और उस के ऊंचे होने के कारण जल की आगे निकासी की कोई सम्भावना नहीं है। प्रतिवर्ष सफाई करने के बाद भी यह सम्भव नहीं था कि जल निकल सके, इसी लिए यहां पर पानी इकट्ठा हो जाता है। अतः इस स्कीम को छोड़ दिया गया।

श्री कल्पनाथ सिंह--

माननीय मन्त्री कह रहे हैं कि तैराने नाले का स्तर कुछ गनगरी नाले से ऊंचा है और मन्त्री जी खुद यह कहते हैं कि यह नाला तैराने नाले में जा कर गिरता है तो जब उस का स्तर ऊंचा होगा, तो इधर दूसरे नाले को उस में गिराने का प्रश्न ही नहीं होता है। मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि मन्त्री जी इस की जांच करायें कि इन दोनों में से किस की सतह ऊंची है जिसकी वजह से यह दिक्कत हो रही है। क्या इस की जांच करा कर पुनः इस बात को देखेंगे ताकि इस पूरे क्षेत्रफल को बाढ़ तथा वाटर लागिंग से बचाया जा सके ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद--

मैं पुनः जांच करा लूंगा और देखूंगा कि इस प्रश्न पर क्या किया जा सकता है।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

क्या सिंचाई मन्त्री जी बतायेंगे कि जो लिखित उत्तर उन्होंने भेजा है और जो उपमन्त्री जी ने जवाब में कहा है कि आर्थिक कारणों से यह सम्भव नहीं है और इसलिए इस योजना को आप नहीं ले सके हैं, जब कि आप ने कहा है कि टेक्निकली और इन्जीनियरिंग कारणों से इस योजना को नहीं लेना चाहते तो आप के और उप मन्त्री जी के उत्तर में जो भेद है इन दोनों में सच कौन है ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

आप ने उत्तर पूरा नहीं पढ़ा है । उस में दोनों कारण हैं, आर्थिक कारण भी है और तकनीकी कारण भी है । वस्तुतः कारण यह है कि आर्थिक कारण इसलिए है कि इस नाले की जो यहां योजना बनी थी उससे कई गुना धन लगने की सम्भावना है । और तकनीकी दृष्टि से जैसा मैंने कहा तैरन नाले का जो स्तर है वह ऊंचा है और पीछे की जमीन को यदि और अधिक खोदा जाय तो उससे कोई लाभ होने की सम्भावना नहीं है । इसलिए आर्थिक दृष्टि से भी बेकार है ।

श्री केशव देव (जिला अलीगढ़)—

मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जो इन्डियन प्लान्ट विद्युत् का आपके पावर हाउस काशीपुर पर चौथा पड़ने वाला है तो वह पड़ेगा या नहीं पड़ेगा ? यदि हां, तो उसका जो सामान पहुंच चुका है वह रुका हुआ क्यों पड़ा है ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

सम्भवतः माननीय सदस्य पिछले प्रश्न के बारे में पूछ रहे हैं । अगर वह मेरे कमरे में आ जायेंगे, और कोई जानकारी चाहेंगे तो मैं दे दूंगा ।

वाराणसी तहसील में नलकूप सर्वेक्षण

*६—श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव इन्दरपुर, गोरी, सालिवाहनपुर व रसूलपूर पूर्वी व हथिवार, कोइरीपुर, नन्दापुर व चक्का अनरखापुर, कृष्णापुर, सुरधवेख पश्चिमी व रामनगर, शाहपुर व बाबतपुर निवाहे गिरधवलपुर व दासेपुर, भगतूपुर, तथा काजी सराय, दुनियापुर व मटौली, करोमा, दुनियापुर तथा रमई पट्टी, पश्चिम पट्टी, परगना अठगांवां, तहसील व जिला वाराणसी, ने ट्यूबवेल लगाने के लिए सर्वे किया है ? यदि हां, तो उपरोक्त स्थानों में कब तक ट्यूब वेल लग जायगा ?

श्री रामप्रसाद देशमुख—

प्रश्न में अंकित ग्रामों का प्रारम्भिक सर्वेक्षण कर लिया गया है । ग्राम दासेपुर व ग्राम करोमा नव निर्मित नलकूप रामसिंहपुर व अवसानपुर में क्रमशः सम्मिलित हैं तथा ग्राम काजी सराय का क्षेत्र नलकूप बार तथा नवनिर्मित नलकूप गदवा के कमान्ड में है । ग्राम रसूलपुर पूर्वी हथिवार, कोरीपुर, नन्दापुर, अनरखापुर (या झनरखापुर), शाहपुर, बाबतपुर, रामनगर, निवाहे । विरधौलपुर में नये नलकूप बनाना सम्भव प्रतीत होता है । इनका निर्माण जिला स्तर पर बनायी गयी परामर्श समिति की स्वीकृति तथा धन उपलब्ध होने पर निर्भर है । सर्वेक्षण भी जिला स्तर समिति की अनुमति पर निर्भर है ।

क्षेत्र ग्रामों के अधिकतर क्षेत्र वर्तमान नलकूपों के कमान्ड में है तथा उनका शेष क्षेत्र या तो असमतल है या इतना पर्याप्त नहीं है कि नया नलकूप प्रस्तावित किया जाय ।

(मन्त्री के प्रश्नोत्तर अटक-अटक कर पढ़ने पर ।)

श्री अध्यक्ष—

माल्नूम ऐसा होता है कि जैसी खराब कापी मेरे पास आयी है वैसी ही खराब कापी आप के पास है । ऐसी व्यवस्था कीजिये कि आप के पास और मेरे पास भी अच्छी कापी आये ।

श्री रामप्रसाद देशमुख—

अच्छी बात है ।

श्री मोहनलाल गौतम (जिला अलीगढ़)—

क्या माननीय मन्त्री बतलायेंगे कि इस सिंचाई का आधार रक्षा करना है अथवा उत्पादन बढ़ाना है ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

उत्पादन बढ़ाना है ।

श्री ऊदल—

सरकार ३०० एकड़ का कमान्ड करने जा रही है तो इसी को दृष्टि में रखते हुए क्या वह कमान्ड एरियाज को पुनः सर्वे कराने की कृपा करेगी ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

उसी दृष्टि से सर्वे किया जा रहा है ।

श्री राम मूर्ति—

अगर माननीय मन्त्री का इन ट्यूबवेलों को लगाना उत्पादन बढ़ाना है तो आजकल जो फसलें पैदा की जा रही हैं, हाई ईल्डिंग वेराइटी की उनके लिए कमान्ड कितना रखा जा रहा है ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

नलकूप का कमान्ड इस पर निर्भर करेगा कि काश्तकार कितनी हाई ईल्डिंग वेरायटी स्वीकार करता है । मैं समझता हूं कि वस्तुतः जो कमान्ड है इस समय उस में जितने घंटे ट्यूबवेल चलना चाहिए उतने घंटे ही नहीं चल रहा है, तो कमान्ड एरिया बढ़ाने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

श्री ऊदल—

अभी माननीय मन्त्री जी ने जो रिपोर्ट पढ़ी है इस में सिर्फ एक ट्यूबवेल सालिवाहनपुर के नाम से है जिसके कमान्ड में कुछ एरिया आता है और दूसरा ट्यूबवेल रसूलपुर के पास है । आस पास कोई ट्यूबवेल नहीं है इस की जानकारी क्या माननीय मन्त्री करेंगे ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

अवश्य करूंगा ।

कोल असला परगना में नाद नदी का उत्तरी नहरी क्षेत्र

*७—श्री ऊदल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि परगना कोल असला तहसील व जिला वाराणसी में नाद नदी के उत्तर जिस को नहरी एरिया बनाया गया है उस को खत्म कर के उस क्षेत्र में

ट्यूबवेल लगान की व्यवस्था की जा रही है और क्या कुछ स्थानों का सर्वे भी किया गया है ? यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं और वहां ट्यूबवेल कब तक लग जायेंगे ?

श्री रामप्रसाद देशमुख—

परगना कोल असला, तहसील व जिला वाराणसी में नाद नदी के उत्तरी क्षेत्र को नहरी कमान्ड से निकाल कर वहां पर नलकूप लगाने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

श्री ऊदल—

क्या माननीय मन्त्री इस बात की जांच करेंगे कि उस इलाके में शारदा सागर योजना बनाने में लाखों रुपये खर्च हो गये, लेकिन आज तक पानी नहीं मिल सका तो क्या सरकार उन के खिलाफ कार्यवाही करने की कृपा करेगी ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

मैं समझता हूं कि यह योजना शासन के विचाराधीन रह कर उसी के निर्देश पर बनायी गयी, इसलिए उन व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करने का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

श्री जगदम्बाप्रसाद—

जिन इंजीनियरों ने यह योजना बनायी जिस से आज तक वहां पानी नहीं आ सका और इस में शासन के बहुत बड़े धन का अपव्यय हुआ तो सरकार उन इन्जीनियरों के खिलाफ क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

अभी उत्तर दिया है कि यह योजनायें चूंकि हमारी स्वीकृति से बनती हैं इस लिए मैं समझता हूं कि उन के खिलाफ कार्यवाही करने का अब कोई प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रघुनाथ सिंह—

क्या माननीय सिंचाई मन्त्री को यह पता है कि छोटे ट्यूबवेल्स, जिन्हें कैपिटी वेल्स भी कहते हैं, टेकनिकल रूप से पम्पिंग सेट्स की भी आवश्यकता पड़ती है या उन के बगैर भी काम चल सकता है ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

इसके लिए सूचना की आवश्यकता है ।

श्री मधुकर दिघे—

क्या माननीय सिंचाई मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन स्थानों पर प्राइवेट ट्यूबवेल्स लगे हुये हैं या सरकारी ट्यूबवेल्स लगे हुये हैं वहां नहर की योजना बनाने के समय इन ट्यूबवेल्स को खत्म न करने का ध्यान रखा जायगा ?

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—

यह ध्यान रखा जाता है । यदि माननीय सदस्य को किसी ऐसे स्थान की सूचना है तो कृपया मुझे देने का कष्ट करें।

श्री ऊदल—

माननीय मन्त्री जी ने कहा कि नहरी इलाके में ट्यूबवेल्स को समाप्त न करने का ध्यान रखा जायगा । मैं यह जानना चाहता हूं कि अभी तक कुछ गांवों का सर्वे करवाया गया या नहीं ? यदि कराया गया है तो किन गांवों का और अगर नहीं कराया गया है तो यह काम कब से शुरू कर दिया जायगा?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद---

यह जो टैल सिस्टम है, जौनपुर के आगे जो नहर बनारस खंड में जाती है उस में ६ हजार एकड़ भूमि नहर कमान्ड से निकाल कर वहां ट्यूबवेल्स लगाने का विचार है।

श्री शराफत हुसैन रिजवी---

मन्त्री जी ने अभी दो-तीन प्रश्नों से पहले यह कहा था कि कमान्ड एरिया अब पहले से घटा कर तीन सौ एकड़ कर दिया गया है। तो जिन कुओं का कमान्ड एरिया पहले आठ सौ एकड़ तथा और अब तीन सौ एकड़ कर दिया गया है तो बाकी पांच सौ एकड़ में सिंचाई कराने के लिए उन के दिमाग में कोई स्कीम है ? यदि है तो वह क्या है ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद---

श्रीमन्, यह प्रश्न उन स्थानों पर उठ रहा है जहां ट्यूबेलों की पूरी क्षमता का उपयोग हो रहा है वहां कमांड एरिया के घटाने बढ़ाने से कोई असर नहीं पड़ रहा है।

गिदही ग्राम में बिजलीघर के लिये जमीन

*६---श्री अश्विनी कुमार---

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बस्ती जिले के गिदही गांव में बिजली घर बनाने के लिए जो जमीन ली जा रही है उस में कितने किसानों के उपजाऊ खेत ले लिये जा रहे हैं ?

श्री रामप्रसाद देशमुख---

बस्ती जिले के गिदही ग्राम में बिजली के सब-स्टेशन बनाने के लिए २७ किसानों के उपजाऊ खेत लिये गये हैं।

श्री अश्विनी कुमार---

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जिन किसानों की उपजाऊ जमीन ली जा रही है उसी की बगल में मिल मालिकों की परती जमीन है और बड़े किसानों की भी जमीन है जिस को नहीं लिया जा रहा है ? छोटे किसानों की उपजाऊ जमीन क्यों ली जा रही है ?

श्री रामप्रसाद देशमुख---

वहां के जिलाधीश ने और दो अन्य अधिकारियों ने उसी जमीन को उपयुक्त समझा है। इसके अलावा और जमीन नहीं ली जा सकती थी।

श्री चन्द्रबली सिंह (जिला देवरिया)---

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जो जमीन ली गयी है उसका मुआवजा दिया जा रहा है ?

श्री रामप्रसाद देशमुख---

एक्वीजीशन होने पर मुआवजा तय किया जायेगा।

श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)---

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि इन किसानों का डेपूटेशन मिला था और उन को आश्वासन दिया गया था कि जिलाधीश से जांच करायी जायेगी और दूसरे सुझाव आने पर दूसरी जमीन ली जायगी ?

श्री रामप्रसाद देशमुख---

इसके लिए नोटिस की आवश्यकता है।

श्री मधुकर दिघे--

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि छोटे किसानों की उपजाऊ जमीन न लेने के लिए और जहां ट्यूब वेल बनाये जा सकते हैं वहां बड़े किसानों के खेत और बिना उपजाऊ जमीन लिये जाने के आदेश दिये जायेंगे ?

श्री रामप्रसाद देशमुख--

श्रीमन्, यहां ट्यूब वैल बनाने की कोई योजना नहीं है। यहां सब स्टेशन बनना है और छोटे किसानों की जमीन न छोड़ी जाय ऐसा कोई सवाल नहीं है। लेकिन उपयुक्त जमीन समझकर वहां बनाने की जरूरत पड़ी।

औरंगाबाद ताहरपुर में नलकूप से सिंचाई

*९--श्री नेमपाल सिंह (जिला बुलन्दशहर)--

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या ग्राम औरंगाबाद ताहरपुर ब्लाक ऊंचागांव, जिला बुलन्दशहर में कोई राजकीय नलकूप हैं ? यदि नहीं, तो क्या मन्त्री उपरोक्त गांव में शीघ्र ही राजकीय नलकूप लगवाने के लिए आदेश जारी करेंगे ?

श्री रामप्रसाद देशमुख--

प्रथम भाग--इस ग्राम में दो राजकीय नलकूपों द्वारा सिंचाई होती है।

द्वितीय भाग--इस ग्राम के लिए और राजकीय नलकूप लगवाना इस समय प्रस्तावित नहीं है।

श्री नेमपाल सिंह--

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि ग्राम औरंगाबाद ताहरपुर में जो सिंचाई दूसरे गांवों के सरकारी नलकूपों से होती है वह उस भूमि के लिए पर्याप्त है ?

श्री टंडबरेश्वर प्रसाद--

इस के लिए जो कमान्ड एरिया बना हुआ है उस में इस को उपयुक्त समझकर ही रखा गया है।

श्री नेमपाल सिंह--

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि एक गांव जिसमें सरकारी नलकूप की बड़ी आवश्यकता थी वहां की जमीन को दूसरे ट्यूबवेल के कमान्ड में दे दिया गया है ?

श्री अध्यक्ष--

आप किसी खास गांव के बारे में कह रहे हैं।

श्री नेमपाल सिंह--

औरंगाबाद ताहरपुर के लिए मैं कह रहा हूं।

श्री टंडबरेश्वर प्रसाद--

श्रीमन्, इस ग्राम का जो क्षेत्र फल है, उस में से १६५ एकड़ का रकबा नं० १०१ जे० बी० के कमान्ड में है वह २१३ एकड़ है, ८७ नम्बर का, लगभग ९० एकड़ नहरी कमान्ड है। शेष क्षेत्रफल असिंचित है। मैं समझता हूं कि यह कमान्ड एरिया इस के लिए पर्याप्त है क्योंकि इस से सींच बहुत अधिक नहीं होती।

कमालपुर ग्राम में सिंचाई

*१०—श्री नेमपाल सिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री को यह ज्ञात है कि ग्राम कमालपुर ब्लाक ऊंचागांव, जिला बुलन्दशहर में रजबहा जखेड़ा कुलाबा नं० ५० से उपरोक्त गांव की पूर्व सिंचित लगभग ५०० बीघा (कच्चा) उत्पादन की भूमि इस समय सिंचाई से वंचित है ? क्या मन्त्री जी इन भूमि को उपरोक्त कुलावा नं० ५० से सिंचाई की सुविधा देने के लिए शीघ्र ही आवश्यक कदम उठाने की कृपा करेंगे ?

श्री रामप्रसाद देशमुख—

ग्राम कमालपुर, ब्लाक ऊंचागांव, जिला बुलन्दशहर की जो भूमि रजबहा जखेड़ा के कुलावा नं० ५० के कमान्ड में है वह सिंचाई से वंचित नहीं है। परन्तु चकबन्दी के पश्चात् पर्याप्त मात्रा में तथा लगातार एक से जुड़ी गूलें न देने के कारण सुचारु रूप से सिंचाई करने में असुविधा हो गयी है और गूलें बनवाने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

श्री नेमपाल सिंह—

क्या माननीय मन्त्री बतायेंगे कि यह कार्यवाही कब तक पूरी हो जायगी और जो उन कृषकों को अब तक नुकसान हुआ है उन के लिए सरकार क्या फैसला करेगी ?

श्री रामप्रसाद देशमुख—

इस पर कार्यवाही कर रहे हैं। जल्दी से जल्दी चाहते हैं। सरकार के विचाराधीन है।

श्री नेमपाल सिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री को यह भी पता है कि उस गांव के कुलाबे से जो परेशानी पैदा हुई है उस में पुरानी नालियां चकबन्दी वालों की कमी की वजह से रद्द कर दी गयीं और नयी नालियों की भूमि किसानों ने तोड़ दी हैं, अभी तक नालियां नहीं बनी हैं, तो सिंचाई मन्त्री क्या कुछ भूमि अक्वायर करके कुछ बन्दोबस्त करेंगे ?

श्री टण्डरेश्वर प्रसाद—

मैं समझता हूं कि काश्तकारों को असुविधा जरूर हुई है। लेकिन नियमों के अन्तर्गत नालियां बनायी जाती हैं। अब ऐसा आग्रह किया है, यदि नहीं मानेंगे तो भूमि को अक्वायर करके नाली बनाने की सरकार आज्ञा देगी।

किरावली तहसील में विद्युत् कार्य

*११—श्री रघुनाथ सिंह (जिला आगरा)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि तहसील किरावली, जिला आगरा के ग्रामीण क्षेत्र में बिजली पहुंचाने का कार्य जो प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही पास किया गया था अधूरा ही पड़ा है ? यदि हां, तो उसे कब तक पूरा करने की कार्यवाही की जायगी ?

श्री राम प्रसाद देशमुख—

सूचना नत्थी किये गये ब्योरे में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ... २९३ पर)।

श्री रघुनाथ सिंह—

क्या माननीय मन्त्री बतायेंगे कि यह रिपोर्ट किस अधिकारी के द्वारा दी गयी है ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद--

इसके लिए सूचना की आवश्यकता है।

श्री रघुनाथ सिंह--

जिन गांवों का सर्वेक्षण किया गया बताया जाता है, तहसील किरावली में उस नाम के गांव नहीं हैं, तो क्या फिर से इस की सूचना प्राप्त करेंगे ?

श्री टम्बरेम्श्वर प्रसाद--

यदि माननीय सदस्य लिखित देंगे कि किन-किन ग्रामों के सम्बन्ध में चाहते हैं तो पुनः सर्वेक्षण जरूर करवा लेंगे।

जगनेर कस्बे का विद्युत् सर्वेक्षण

१२--श्री रमाशंकर अग्रवाल (जिला आगरा)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आगरा जिला के जगनेर कस्बा में बिजली लगाने के लिए सर्वे हो चुका है ? यदि हां, तो वह बिजली कब तक लगेगी ?

श्री रामप्रसाद देशमुख--

जी हां, परन्तु प्राविधिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण से इसका विद्युतीकरण अभी सम्भव नहीं है।

श्री रमाशंकर अग्रवाल--

क्या माननीय मन्त्री यह बतायेंगे कि यह सर्वे कितनी बार हुआ और कब-कब हुआ ?

श्री रामप्रसाद देशमुख--

सर्वे जानकारी के लिए करवाया जाता है। इस के लिए नोटिस की जरूरत है कि कितने बार हुआ है।

श्री रमाशंकर अग्रवाल--

क्या माननीय मन्त्री बतायेंगे कि कौन सी प्राविधिक कठिनाइयां सर्वे में बतायी गयी हैं ?

श्री रामप्रसाद देशमुख--

तीस मील लम्बी लाइन है। उस पर दो ढाई लाख खर्च का अनुमान है। इसलिए धन के अभाव के कारण सरकार के विचाराधीन हैं।

श्री रमाशंकर अग्रवाल--

क्या माननीय मन्त्री को यह सूचना है कि कागारोल तक बिजली पहुंच चुकी है ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद--

जब भी कोई लाइन आगे बढ़ायी जाती है, तो उस में वोल्टेज ले जाना पड़ता है, उसके लिए सब-स्टेशन बनाने पड़ते हैं। अधिक लम्बी लाइन बनाने में मोटर जलने का भय रहता है। लेकिन वह २० मील लम्बी लाइन बनानी है, काफी खर्चा है, इसलिये इसको बनाने पर विचार करना पड़ेगा।

श्री भृगुनाथ चतुर्वेदी (जिला गोरखपुर)—

माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश के सभी गांवों में बिजली पहुंचाने की सरकार के पास कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री रामप्रसाद देशमुख—

बिजली पहुंचाने की योजना है, लेकिन जब गांवों के पास पहुंच जायेगी और ५० प्रतिशत रिटर्न होगा तभी उस गांव में बिजली दी जाएगी ।

श्री सोहनलाल धुसिया—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सर्वे कराने के बाद क्या कोई समय निश्चित है, कि इतने दिनों के बाद बिजली मिल जायेगी ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

जी नहीं, ऐसा कोई नियम बनाना आज की स्थिति में ठीक नहीं है ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि 'आज की स्थिति' से उनका क्या तात्पर्य है ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

यह माननीय सदस्य के उस प्रश्न का उत्तर दिया गया था कि दिन नियत कर दिये जायें कि सर्वे कराने के इतने दिनों के भीतर बिजली लग जाय । सर्वे जानकारी के लिये किया जाता है और एक साथ अनेक स्थानों पर सर्वे किया जाता है । इसलिये इसको करने के लिये दिन नियत करना संभव नहीं है ।

श्री जगदम्बा प्रसाद—

कस्बों और गांवों में जो बिजली लगाई जाती है वह रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन स्कीम के अन्तर्गत होती थी । किन्तु अब उस स्कीम को आपने समाप्त कर दिया है । तो मैं जानना चाहता हूं कि इस कारण से कस्बों और गांवों में बिजली नहीं पहुंचाई जा रही है ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

ट्यूब वेल्स आदि अन्यान्य योजनायें इसीलिये बनाई गयी हैं । कोई ऐसी योजना नहीं है कि गांवों में बिजली नहीं लगायी जाएगी ।

श्री नेकराम शर्मा—

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कितने गांवों में उत्तर प्रदेश में बिजली लगेगी ? और इस चालू वर्ष में कितने गांवों में लगेगी ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

इसके लिये सूचना की आवश्यकता है ।

माताटीला बांध में पानी भरने की क्षमता

*१३—श्री शंकर सिंह चौधरी (जिला जालौन)—

क्या यह सरकार बताने की कृपा करेगी कि झांसी जिले के माता टीला बांध में कितना पानी भरने की क्षमता है ? तथा वित्तीय वर्ष १९६६-६७ में कितना पानी रोका गया ?

श्री रामप्रसाद देशमुख—

प्रथम भाग—३,४०,६५० लाख घनफुट ।

द्वितीय भाग—२,५०,६०० लाख घनफुट ।

श्री शंकर सिंह चौधरी—

पहली बात तो यह है कि मेरे पास प्रश्नों का उत्तर ही नहीं पहुंचा ....

श्री अध्यक्ष—

कल भी यह शिकायत मिली थी, इस हेतु मैंने अपने कार्यालय में काफी कहा सुनी की है । मुझको यह दिक्कत बताई गई है कि कुछ नये माननीय सदस्यों को मकानों का जो बंटन हुआ है उसकी सूचना मेरे कार्यालय में नहीं है । इसलिये जिनको नये कमरे मिले हैं वे माननीय सदस्य उसकी सूचना हमारे यहां भी देने की कृपा करें । इसके अलावा भी मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को असुविधा न हो, किन्तु अच्छा हो आप हमारी सहायता कर दें ।

श्री शंकर सिंह चौधरी—

वैसे मैं सूचना दे चुका हूं, यदि आप कहेंगे तो दुबारा दे दूंगा । इसलिये यह प्रश्न आगे ले लिया जाय तो ज्यादा अच्छा हो ।

श्री अध्यक्ष—

पहले ही आप बता देते तो हो सकता था, अब नहीं । क्योंकि मैंने मंत्री जी को बुला लिया है और उन्होंने उत्तर भी दे दिया है ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि यह जरूरी नहीं है कि माननीय सदस्य आपके पास अपने पते की सूचना दें जैसा कि पहले भी हुआ है । आप स्टेट डिपार्टमेंट से पूछ लें किसको कौन-सा स्थान दिया गया है ।

श्री अध्यक्ष—

यदि आपने मेरी पूरी बात सुनी होती तो ऐसा न कहते । मैंने तो केवल सुविधा के लिये माननीय सदस्यों से सहायता मांगी है । किन्तु मैं अन्य तरीके से भी उनकी असुविधा दूर करने का प्रयास करूंगा । १–२ दिन में यह व्यवस्था ठीक हो जायेगी ।

श्री शंकर सिंह चौधरी—

माननीय मंत्री जी के उत्तर से प्रतीत होता है कि माताटीला की क्षमता के अनुसार पानी नहीं भरा गया । तो मैं पूछना चाहता हूं कि जो पानी कम भरा गया उसकी क्या वजह थी ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

इस वर्ष तो सूखा रहा जिससे सदस्यगण अवगत हैं ।

श्री शंकर सिंह चौधरी—

क्या सिर्फ सूखे की वजह से ऐसा हुआ या आफिसरों की गलती की वजह से ऐसा हुआ ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

माननीय सदस्य कोई भी ऐसी सूचना देंगे कि किसी अधिकारी की वजह से हुआ तो जांच करवा ली जायगी ।

श्री शंकर सिंह चौधरी--

मेरी जानकारी है कि . . .

श्री अध्यक्ष--

आप जानकारी मत दीजिये, वह उनके कक्ष में दीजियेगा, यहां प्रश्न कीजिये।

श्री शंकर सिंह चौधरी--

क्या यह सही है कि बरसात के पहले महीनों में पानी नहीं भरा गया और बाद में जब पानी नहीं बरसा उस वक्त पानी भरने की कोशिश की गयी ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद--

मैं इसकी जांच करा लूंगा।

जालौन जिले में नहरी पानी कम मिलने की शिकायत

*१४--श्री शंकर सिंह चौधरी--

प्रश्नकर्ता की इस सूचना को सत्य मान कर कि जालौन जिले में इस वर्ष रबी की सिंचाई में नहर विभाग द्वारा बहुत कम पानी दिया गया तथा काश्तकारों को एक बार से अधिक पानी नहीं मिल सका जिससे वे पानी का पूरी तरह उपयोग नहीं कर सके, क्या सरकार इसकी जांच करा कर काश्तकारों को माफी देने की कृपा करेगी ?

श्री रामप्रसाद देशमुख--

जी नहीं। यह सत्य नहीं है कि जिला जालौन में इस वर्ष रबी की सिंचाई के लिये बहुत कम पानी दिया गया। वास्तव में पिछले वर्ष वर्षा कम होने तथा सूखे के कारण जिले के लगभग शत प्रतिशत क्षेत्र में पलेवा की मांग थी। अतएव रबी बोआई के पूर्व पलेवा के लिये नहरी पानी दिया गया तथा पलेवा के उपरान्त फसल की सींच के लिये भी अधिकतर क्षेत्र में एक और पानी दिया गया। केवल उन क्षेत्रों में जहां कि कृषकों ने बहुत देर में पलेवा किया था फसल उगने के बाद सींच के लिये पानी उपलब्ध न हो सका जहां केवल पलेवा ही किया जा सका वहां पलेवा की ही सिंचाई कर ली गयी गया अन्य सिंचित क्षेत्र में फसल को कोई ऐसी हानि नहीं हुई जिसके कारण सिंचाई कर से छूट दी जाय। इस विषय में कोई प्रार्थना-पत्र भी प्राप्त नहीं हुआ।

श्री शंकर सिंह चौधरी--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आम तौर से एक फसल को कितना पानी नहर विभाग की ओर से दिया जाता है ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद--

काश्तकार जितना उपयुक्त समझता है लगाता है।

श्री शंकर सिंह चौधरी--

क्या जिला जालौन में नहरों से पानी सरकार ने दिया या नहीं ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद--

इस वर्ष विशेष स्थिति थी कि पलेवा को पानी देना पड़ा और यह भी सही है कि सूखे के कारण इस सिस्टम में पानी कम था लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है। इस बात का प्रयत्न अवश्य किया गया है कि अधिक से अधिक क्षेत्रों में सिंचाई हो सके ताकि फसल सूखे से बच सके।

श्री चन्द्रशेखर—

पलेवा में एक बार पानी देने के बाद फिर पानी नहीं मिला जिसके कारण फसलें सूख गयीं। उसके बाद भी उनसे नहर का टैक्स लिया गया ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

जी नहीं। पलेवा के समय १,०५,४०० एकड़ में, और २,५८,००० एकड़ मुख्य सिंचाई में दिया गया है।

आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)—

यह बात सही है कि सिंचाई मैनुअल के मुताबिक अगर किसान अपने खेत सींचे अपने साधन से और नहर विभाग का इस्तेमाल किया गया तो सिंचाई कर वसूल हो जाता है तो क्या सरकार सिंचाई मैनुअल में कोई तरमीम करने की सोच रही है ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

नहीं। ऐसा विचार नहीं है।

श्री माता प्रसाद (जिला जौनपुर)—

काश्तकार को जितने पानी की जरूरत होती है अगर उतना पानी नहीं मिलता नहर से, या कम मिलता है तो क्या सरकार इस तरह के काश्तकारों को सिंचाई में कोई छूट देने की व्यवस्था करेंगी ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

सिंचाई के लिये काश्तकारों से कर लेने के लिये कुछ नियम बने हुये है। उनके अन्तर्गत सिंचाई कर लिया जाता है। काश्तकार अपनी आवश्यकता भर पानी लेता है और वह जितना चाहे ले। हम तो सिंचाई भर का धन उससे लेते हैं।

श्री चन्द्रबली सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि किसान जब अपना अपने ट्यूबवैल और अपने कुंए से सिंचाई करते ह और अपने बराह इस्तेमाल करते ह तो आपका कौन-सा नियम है जिससे अपने साधन से सिंचाई करने के बाद भी उनको सिंचाई कर देना पड़ता है ? क्या इसको तब्दील किया जायगा ताकि किसानों को राहत मिल सके ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

अभी इस नियम के ऊपर पुनः विचार करने का इरादा नहीं है।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—

जिन पुराने नियमों का अभी मंत्री जी जिकर कर रहे हैं उनसे कब तक छुट्टी लेंगे ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद

जब वे बेकार हो जायेंगे तब उनके ऊपर विचार किया जायगा। अभी तो वे काम कर रहे हैं।

*१५—सर्वश्री बलदेव सिंह सरदार (जिला गोंडा) सुखदेव प्रसाद, रामदुलारे तथा रामदेव मिश्र (जिला प्रतापगढ़)—

[२रे शुक्रवार के लिये प्र० सं० २५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*१६-१७—श्री हरीसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

[२रे गुरुवार के लिये प्र०सं० ३-४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

हाईडेल विभाग के सुपरिण्टेन्डेन्टों का प्रमोशन

*१८—श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि असिस्टेंट इंजीनियर के पदों पर हाइडेल विभाग के सुपरिंटेंडेंट का जो प्रमोशन दिनांक १२ फरवरी, १९६७, के जी० ओ० के मुताबिक दिनांक २५ फरवरी, १९६७ को किया गया है उसमें पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा भेजी गई वरीयता सूची को क्या नजरअन्दाज किया गया था? यदि हां, तो किन कारणों से ऐसा किया गया ?

श्री राम प्रसाद देशमुख—

जी नहीं। पावर हाउस सुपरिंटेंडेंट का पद सबार्डिनेट इलेक्ट्रिकल ऐंड मेकेनिकल इंजीनियरिंग सर्विस का "सेलेक्शन ग्रेड" है। इस पद पर जूनियर ग्रेड के लोगों का प्रमोशन होता है और लोक सेवा आयोग द्वारा पावर हाउस सुपरिंटेंडेंट की कोई वरीयता निर्धारित नहीं होती।

*१९—श्री जगन्नाथ प्रसाद—

क्या सरकार उन सभी चुने गये अथवा न चुने गये व्यक्तियों के नाम मय उनकी विभागीय वरीयता एवं पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा निर्धारित उनकी वरीयता की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री राम प्रसाद देशमुख—

उपलब्ध सूचना †अनुसूची १-२ व ३ में प्रस्तुत है।

श्री जगन्नाथप्रसाद—

क्या सरकार बतायेगी कि सूची में लिखे गये कितने सुपरिंटेंडेंट ने यह प्रार्थना-पत्र दिया है कि सेलेक्शन ग्रेड देने में उनके साथ ज्यादती हुई है?

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

इस प्रकार का एक प्रार्थना-पत्र सरकार को प्राप्त हुआ है।

शारदा नहर की उन्नाव शाखा से माइनर निकालना

*२०—श्री भगवतीप्रसाद विशारद—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शारदा नहर उन्नाव शाखा से उन्नाव जिले में कौन-कौन सी माइनर निकालने की योजना विचाराधीन है ?

श्री रामप्रसाद देशमुख—

उन्नाव जिले में कोई माइनर निकालने की योजना विचाराधीन नहीं है।

श्री भगवतीसिंह विशारद—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इसमें उस माइनर को शामिल नहीं किया गया है जिसका नहर विभाग के द्वारा सर्वे किया गया है और जिसके लिये गांव वालों ने प्रार्थना की थी ?

---

†छापी नहीं गयी।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद---

उन्नाव जिले की हरदोई शाखा, शारदा की मुख्य शाखा से निकलती है । उनमें अभी अतिरिक्त जल उपलब्ध नहीं है इसलिये नहर की लम्बाई बढ़ाने के ऊपर विचार नहीं किया गया, अभी तक उसको पूरा जल नहीं मिल रहा है ।

श्री भगवतीसिंह विशारद---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब उनके पास इस समय पानी देने की क्षमता नहीं है जिसके कारण नहर की लम्बाई बढ़ा सकें, तो क्या शारदा कैनाल जो उन्नाव जिले में गई है उनकी क्षमता बढाने के लिये ऐसा कार्य करेंगे जिससे नहर की उपयोगिता बढ़ सके ?

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

अभी हम लोगों ने यह विचार किया है कि सरजू को बांध कर पानी लिया जाय किन्तु इसमें समय लगेगा । अभी निकट भविष्य में इसकी क्षमता बढ़ाना संभव नहीं है ।

श्री भगवतीसिंह विशारद--

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि निकट भविष्य में नहरों से सिंचाई की कैपेसिटी बढ़ाने का सरकार का कोई इरादा नहीं है तो क्या वे सिंचाई के लिये नलकूपों की व्यवस्था करने की कृपा करेंगे ?

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

माननीय सदस्य अगर उस क्षेत्र के बारे में लिखेंगे तो अवश्य विचार किया जायगा ।

तिलहर तहसील में नहरों का निर्माण

*२१--श्री रामनाथ (जिला शाहजहांपुर)--

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तहसील तिलहर, जिला शाहजहांपुर में कितनी ऐसी नहरें हैं जिनकी पैमाइश हुई, परन्तु उनका निर्माण कार्य रोक दिया गया है ?

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

१८ प्रस्तावित नहरों के निर्माण का विचार स्थगित कर दिया गया है ।

*२२--श्री रामनाथ--

क्या यह सही है कि पैना माइनर के अन्तर्गत उपरोक्त तहसील की ग्राम सहतेपुर और पचदिउरा के मध्य से होकर बनने वाली नहर की पैमाइश आदि होने के बाद रोक दिया गया है और उसी तहसील की ढकिया तिवारी माइनर को आगे बढ़ाने से रोक दिया गया है ? क्या सरकार उपरोक्त नहरों को बनवाने का शीघ्र आदेश देने की कृपा करेंगी ?

श्री टम्बेश्वर प्रसाद--

जी हां, पानी की कमी के कारण इन नहरों का निर्माण सम्भव नहीं है ।

नोट--तारांकित प्रश्न २० के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

शारदा विद्युत् की लाइन हल्द्वानी तहसील में न पहुंचना

*२३—श्री इन्द्रलाल (जिला नैनीताल)—

क्या यह सही है कि शारदा विद्युत् की एक लाइन जिला नैनीताल, तहसील हल्द्वानी में कालाढूंगी रोड से फतेहपुर तक पहुंचाये जाने की योजना बनाई गई थी ? यदि हां, तो कब तक सम्पन्न होने जा रही है ?

श्री टम्बेश्वर प्रसाद—

जी हां, आर्थिक दृष्टि से उपर्युक्त न पाये जाने के कारण उक्त लाइन सम्पन्न नहीं की गई ।

अलावारा झील का सर्वेक्षण

*२४—श्री नाथूराम शिक्षक—

क्या सरकार जिला इलाहाबाद की तहसील मंझनपुर की झील अलवारा का सर्वेक्षण करा कर दो या तीन बांध-बांध वाकर उसे कृषि कार्य के लिये उपयोगी बनाने की व्यवस्था करेगी ?

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

सर्वेक्षण के पश्चात् योजना उपयुक्त नहीं पाई गई ।

बड़ागांव को बिजली देने की मांग

*२५—श्री सालिकराम तथा श्री जवाहिर लाल (जिला सीतापुर)—

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सीतापुर के अन्तर्गत ग्राम महोली से बड़ागांव तक विद्युतीकरण की योजना कब पूर्ण होगी ?

श्री टम्बेश्वर प्रसाद—

वर्तमान समय में ग्राम बड़ा गांव के विद्युतीकरण की कोई योजना नहीं है ।

*२६—श्री सालिकराम तथा श्री जवाहिर लाल—

क्या यह सही है कि उपरोक्त स्थान का सर्वेक्षण पूर्ण हो चुका है ? यदि हां, तो विद्युतीकरण योजना पूर्ण करने में क्या कठिनाई है ?

श्री टम्बेश्वर प्रसाद—

प्रश्न नहीं उठता

सम्भल तहसील में नलकूप चालक

*२७—श्री महेश कुमार (जिला मुरादाबाद) —

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मुरादाबाद जिले की संभल तहसील में कितने सरकारी ट्यूबवेल पिछले छः महीने से अधिक से बन्द पड़े हैं और क्यों ? सरकार इनको कब तक चालू करा पायेगी ?

श्री टम्बेश्वर प्रसाद—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

*२८—श्री महेशकुमार—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मुरादाबाद जिले के कितने ऐसे ट्यूबवेल आपरेटर हैं जो पिछले पांच साल में से एक ट्यूबवेल पर नियुक्त हैं ?

श्री टम्बेश्वर प्रसाद—

ऐसे कुल १०७ ट्यूबवेल आपरेटर हैं।

झांसी डिवीजन में नहरी पानी के तावान की वसूली

*२८—श्री रामश्री राजपूत (जिला हमीरपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस वर्ष रबी की फसल में नहर धसान डिवीजन झांसी द्वारा जो पानी पलेवा को दिया गया था उस पर दुगना तावान वसूला जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

जी नहीं । धसान नहर प्रणाली से इस वर्ष १९६६-६७ रबी की फसल में पलेवा की सिंचाई हेतु नियमानुसार दिये गये पानी पर नियमानुसार लगान लिया जा रहा है । केवल उस क्षेत्र में जो पलेवा द्वारा सिंचित भूमि के दस प्रतिशत से भी कम है और जहां नहरों की पटरी काटकर अवैधानिक रूप से सिंचाई की गयी थी वहां नियमानुसार दुगुना तावान लगाना पड़ा ।

सुरहा ताल की पम्प नहर से पानी न मिलना

*३०—श्री बैजनाथ (जिला बलिया)—

क्या सरकार को मालूम है कि पिछले दो साल से बलिया जिले की भैरीटार पम्प नहर काम नहीं कर रही है ? अतः इस नहर के क्षेत्र में राजकीय ट्यूबवेल शीघ्र बैठा कर यहां के किसानों का कष्ट दूर करने की कृपा करेगी ?

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

बलिया जिले में मराटार नामक कोई पम्प नहर नहीं है । किन्तु तहसील बांसडीह के ग्राम मेरिटाई के पास स्थित सुरहाताल से एक पंप नहर निकाली गई है । वर्षा कम होने के कारण ताल में इतना कम पानी एकत्र हो सका कि यह नहर २३ जनवरी, १९६६ से बन्द है । सामान्य वर्षा होने पर ताल भर जायगा और नहर फिर चालू की जायगी । अतः नलकूप बनाने का प्रश्न नहीं उठता ।

फतेहपुर क्षेत्र में नहर काटने वालों के खिलाफ कार्यवाही

*३१—श्री नाथूराम शिक्षक—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि फतेहपुर डिवीजन में लोअर गंगा कैनाल तथा उसकी शाखायें, दिसम्बर, १९६६ तथा जनवरी एवं फरवरी, १९६७ में कितनी बार कट गई ? इस प्रकार कटने का कारण क्या था तथा इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री टम्बेश्वर प्रसाद—

दिसम्बर, १९६६ से फरवरी, १९६७ के बीच के समय में फतेहपुर डिवीजन, लोअर गंगा नहर, फतेहपुर शाखा तथा उसकी शाखायें ११४ बार कटी थीं ।

एक खांडी चूहे के सूराख की वजह से हुई थी, बाकी सब खांडियां काश्तकारों ने काटी थीं ३५ मामले जहां खांडियों के पानी से सिंचाई की गई थी, काश्तकारों पर तावान लगाया गया, शेष मामलों में काश्तकारों को नहर काटते हुये पकड़ा गया था, उनकी सूचना पुलिस में दी गई थी और खांडी तुरन्त बन्द करा दी गई थी ।

निगोही नहर काटने वालों को नोटिस

*३२—श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)—

क्या यह सही है कि कैनाल विभाग, शाहजहांपुर ने, निगोही, पत्तराजपुर डलेखेड़ा, सिंगापुर व रहापुर गांव के निवासियों को हाल ही में नोटिस दिया है कि उन लोगों ने निगोही शाखा को काट कर अपने खेतों को पानी दिया है ?

श्री टम्बेश्वरप्रसाद----

जी हां, यह सही है ।

*३३-३४---श्री बद्रीप्रसाद अवस्थी (जिला लखनऊ)---

[१६ जून १९६७ को प्र०सं० ६४-६५ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है ।]

एक्जीक्युटिव इंजीनियर के विचाराधीन मुरादाबाद जिले के कार्मशियल मुकदमे

*३५---श्री शराफत हुसैन रिजवी---

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि चीफ इंजीनियर हाइडिल के कार्यालय के एक्जीक्युटिव इंजीनियर (यू०) कार्मशियल जो व्यक्तिगत केसों को देखते हैं उन्होंने जनवरी, सन् १९६६ में ११ अक्टूबर, १९६६ तक किन-किन जिलों का दौरा किया और किस संबंध में और विभाग से भत्तों के रूप में कितनी धनराशि प्राप्त की ?

श्री टम्बेश्वरप्रसाद---

एक्जीक्युटिव (कार्मशियल) ने परिषद् के कार्य के संबंध में १ जनवरी, १९६६ से ११ अक्टूबर, १९६६ तक प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का दौरा किया---

इलाहाबाद, अलीगढ़, अल्मोड़ा, आगरा, बुलन्दशहर, देहरादून, कानपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, नैनीताल और सहारनपुर ।

उनको उपर्युक्त जिलों में बिजली के एग्रीमेंट्स, बिलों, कार्मशियल मीटिंगों व मुकदमों, लाइसेंसी व उपभोक्ताओं के अन्य मामलों, विभागीय परीक्षा इत्यादि के संबंध में दौरे करने पड़े । इसके अतिरिक्त उनको देहली और पटियाला एक मीटिंग एवं पंजाब के रेट्स लाने के लिये भेजा गया था । इन दौरों से रु० १,९६८.४६ की धनराशि भत्तों के रूप में इनको प्राप्त हुई ।

*३६---श्री शराफत हुसैन रिजवी---

क्या सिंचाई मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि उपरोक्त कार्यालय में मुरादाबाद जिले के कुल कितने केस कार्मशियल संबंधी पड़े हुये हैं, उनको अभी तक तय न करने का क्या कारण है ?

श्री टम्बेश्वरप्रसाद---

चीफ इंजीनियर के कार्यालय में मुरादाबाद जिले के लगभग दस केस कार्मशियल संबंधी, इस समय विचाराधीन हैं । मुरादाबाद के जल विद्युत् अधिकारियों से रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् उन पर आवश्यक कार्यवाही की जायगी । रिपोर्ट भेजने के लिये स्मृति पत्र संबंधित अधिकारियों को भेज दिये गये हैं ।

*३७-३८---श्री राम सुन्दर शास्त्री (ज़िला गाजीपुर) तथा श्री ऊदल---

[पहले गुरुवार के लिये प्र० सं० ४८-४९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*३९---श्री इन्द्रलाल---

[१९ जून, १९६६ को प्र० सं० ५९ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है ।]

सहारनपुर व मुजफ्फरनगर जिलों में बांधों का निर्माण

४०—श्री मुल्की राज (जिला सहारनपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायगी कि कैराना, जिला मुजफ्फरनगर में पंजाब सरकार द्वारा बांध बांधे जाने के कारण सहारनपुर व मुजफ्फरनगर जिलों में आबादी व कृषि योग्य भूमि के बचाव के लिये क्या कार्यवाही की गई ?

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

पंजाब सरकार द्वारा बनाये गये बाधों के कारण उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में नुकसान नहीं होता है। राजकीय बाढ़ नियंत्रण योजनाओं के अन्तर्गत सामान्य तौर से सहारनपुर जिले में लखनौती बांध का निर्माण किया गया है। मुजफ्फरनगर जिले में बढ़ी मुस्तफाबाद बांध की योजना यमुना कमेटी द्वारा स्वीकार हो गई है तथा खाजपुर सनौली बांध की योजना पर सर्वेक्षण हो रहा है।

गगहा व बरहलगंज विकास क्षेत्रों में बिजली

*४१—श्री कल्पनाथ सिंह—

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गोरखपुर जिले की बांसगांव तहसील में रिम्रांव ग्राम में बिजली ले जाने की योजना है ? यदि हां, तो उसमें बिजली कब तक पहुंच जायगी ?

श्री टम्बेश्वर प्रसाद—

इस समय रिम्रांव ग्राम में बिजली ले जाने की कोई योजना नहीं है।

*४२—श्री कल्पनाथ सिंह—

क्या सरकार गगहा और बरहलगंज, विकास क्षेत्र जिला गोरखपुर के कछार के गांव में भी बिजली देने की व्यवस्था करेगी ?

श्री टम्बेश्वर प्रसाद—

प्रश्न में किसी विशेष गांव का उल्लेख नहीं है, वैसे जिला गोरखपुर के गगहा और बरहल गंज विकास क्षेत्र में निजी नल कूपों व पंपिंग सेटों के लिये विद्युत् दी जा रही है।

फैजाबाद–तारून बस सर्विस की मांग

*४३—श्री राजबहादुर द्विवेदी (जिला फैजाबाद)—

परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने फैजाबाद से तारून तक राजकीय बस सर्विस चलाने का निश्चय किया है? यदि हां, तो बस कब से चलना प्रारम्भ होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवहन मंत्री (श्री मानसिंह वर्मा)—

फैजाबाद–तारून मार्ग के राष्ट्रीयकरण करने का प्रस्ताव अभी विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में यह बतलाना संभव नहीं है कि इस रूट पर रोडवेज बस चलना कब से प्रारम्भ होगी।

तुलसीपुर विकास क्षेत्र के नलकूपों में खराबी

*४४—श्री शुकदेव प्रसाद तथा सरदार बलदेव सिंह—

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि नलकूप नं० बी० यल० जी० १३ खुलनिया तथा नं० १४ भुसहवा विकास क्षेत्र तुलसीपुर, जिला गोंडा, के नलकूपों के खराब होने से मेक्सीकन गेहूं आधा से अधिक समाप्त हो गया है ? यदि हां, तो सरकार उन्हें ठीक कराने की क्या व्यवस्था करने जा रही है ?

श्री टम्बेश्वर प्रसाद—

कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण नलकूप नं० १३ खुलनिया तथा नलकूप नं० १४ मुसहवा ठीक पानी नहीं दे रहे हैं। नलकूप नं० १३ बालू दे रहा है और इस कारण बार-बार बन्द हो जाता है। नलकूप नं० १४ मार्च, सन् १९६४ से मिट्टी मिला हुआ पानी दे रहा है। मैक्सीकन गेहूं उन्हीं क्षेत्रों में बोने की सिफारिश की जाती है जहां पानी का पूरा प्रबन्ध हो। इन कुओं में खराबी के कारण हानि हुई बताई जाती है लेकिन हानि की मात्रा नहीं मालूम हो सकी।

नलकूप नं १३ में बालू रोकने के लिये नलकूप के स्ट्रेनर का प्लार्गिंग व अन्य कार्यवाही मई, सन् ६७ से की जा रही है। नलकूप नं १४ का पुनर्निर्माण किया जायेगा।

कायमगंज विकास क्षेत्र में नहर शाखा पर पुल

*४५—श्री गिरीश चन्द्र तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला फर्रुखाबाद के कायमगंज विकास क्षेत्र के अन्तर्गत पांच मील लम्बी नहर के खारिजा के ऊपर पुल निर्माण की कोई योजना है? यदि हां, तो उसका कार्य कब प्रारम्भ होगा?

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

जिला फर्रुखाबाद के कायमगंज विकास क्षेत्र के अन्तर्गत नहर खारिजा पर पुल निर्माण धनाभाव के कारण सम्भव नहीं है।

नकोइया नहर की मुड़हुआ माइनर

*४६—श्री रामसजीवन (जिला बांदा) तथा श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुड़हुआ माइनर में जो नकोइया माइनर व चुनार जिला मिर्जापुर में है इसका संबंध नकोइया माइनर की टेल से हटा कर बबुरी नहर से जो डबरी गांव के उत्तर ५०० फीट की दूरी पर है उससे मिलाने की योजना है? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई?

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

नकोइया नहर से निकलने वाली मुड़हुआ माइनर को हटा कर बबुरी नहर से निकालने की कोई योजना नहीं है।

ललितपुर नहर एवं ढुलावन रजबहे से पानी न मिलने की शिकायत

*४७—श्री रघुनाथ सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि झाँसी जिले की बेतवा कैनाल की तृतीय सब डिवीजन गोबिन्द सागर बांध से निकली हुई नहर से तथा नहर की शाखा ढुलावन डी० बाई० से विशेष रूप से इस रबी की फसल को समय पर पानी न देने के संबंध में अधिशासी अभियंता, जिला झाँसी, के पास वहां के किसानों के शिकायती-पत्र मार्च, १९६७ में आये हैं? यदि हां, तो उन पर आज तक सरकार ने क्या कार्यवाही की?

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

इस संबंध में केवल एक प्रार्थना-पत्र श्री रघुबीर सिंह का प्राप्त हुआ था जिस पर सहायक अभियंता द्वारा जांच कराई गई जिसके फलस्वरूप ज्ञात हुआ कि गोबिन्दसागर गांव से निकलने वाली ललितपुर नहर एवं ढुलावन रजबहे से रबी १९६६-६७ में पानी समय पर दिया गया। अलबत्ता मार्च के महीने में सूखे के कारण बांध में पानी की कमी होने से ढुलावन रजबहे पर चौथे मील के आगे पानी नहीं जा पाया।

सिंचाई कार्यशाला वृत्त, कानपुर में कार्य प्रबंधक

*४८--श्री रामदुलारे पटेल (जिला गोंडा)--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि सिंचाई कार्यशाला वृत्त, कानपुर के अन्तर्गत कितने कार्य प्रबन्धक ऐसे हैं जो विगत ३ वर्ष से अधिक अवधि से एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं ?

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

३ वर्ष से अधिक अवधि से २ तथा ५ वर्ष से अधिक अवधि से १ कार्य-प्रबन्धक एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं।

*४९--श्री मुल्की राज--

[२रे सोमवार के लिये प्र० सं० ३२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

गाजीपुर जिले की कथित चन्द्रप्रभा नहर

*५०--श्री कृष्णानन्द राय--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि गाजीपुर जनपद में स्थित चन्द्र प्रभा नहर इस वर्ष न तो खरीफ में या रबी में गाजीपुर जिले में पानी दे पाई, जिससे धान की लगी फसल सूख गई और सूखा के कारण से रबी की फसल बोई तक न जा सकी ?

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

गाजीपुर में चन्द्र प्रभा नामक कोई नहर नहीं है ।

*५१--श्री कृष्णानन्द राय--

क्या सिंचाई मंत्री बतायेंगे कि उपरोक्त स्थिति को देखते हुये इस क्षेत्र में कैनाल रेट सरकार ने माफ कर दिया है ? यदि हां, तो इसकी घोषणा कब की गई है ?

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

प्रश्न नहीं उठता ।

सगड़ी तहसील में बिजली घर के लिये अध्याप्त भूमि का मुआवजा

*५२--श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि आजमगढ़ जिले में सगड़ी तहसील के प्रतापुर ग्राम के किसानों को बेदखल करके उनकी उपजाऊ भूमि विद्युत विभाग ने पावर सब-स्टेशन बनवाने के लिये ली, जहां पर सब स्टेशन बन गया है? किन्तु अभी तक किसानों को उनकी भूमि का मुआविजा नहीं मिला ?

श्री टम्बेश्वर प्रसाद--

जी हां ।

*५३--श्री मुक्तिनाथ राय--

यदि हां, तो उन किसानों को कब तक मुआविजा मिल जायगा ?

श्री टम्बेश्वर प्रसाद--

किसानों की भूमि का मुआविजा स्पेशल रेट से देने की व्यवस्था की गई है । इसके लिये राजस्व परिषद् की स्वीकृति आवश्यक है । उनकी स्वीकृति मांगी गई है ; प्राप्त होने पर मुआविजा फौरन दे दिया जायगा ।

मुआविजे के साथ भूमि पर अधिकार करने की तिथि से ६ प्रतिशत वार्षिक दर से सूद भी दिया जायेगा ।

अतारांकित प्रश्न

बझेड़ा रजबहा के पतरौल के खिलाफ शिकायत

१—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि बरेली की फरीदपुर शाँच से जो रजबहा बझेड़ा निकला है, उस पर तैनात कर्मचारियों एवं अधिकारियों की शिकायत जनता द्वारा एवं प्रश्नकर्ता द्वारा मुख्य मंत्री, सिंचाई मंत्री एवं मुख्य अभियंता, सिंचाई विभाग, को १ दिसम्बर, सन् १९६५ से ३१ दिसम्बर, १९६६ तक अनेक बार लिखित रूप में की गई ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री टम्बेश्वर प्रसाद—

जी हां, कुछ शिकायतें प्रश्नकर्ता महोदय ने श्री हरनाथ सिंह पतरौल के विरुद्ध अपने कई पत्रों में की थीं परन्तु कोई अन्य शिकायत जनता द्वारा न तो पतरौल के विरुद्ध की गई और न किसी और अधिकारी के विरुद्ध ।

इन शिकायतें की जांच की गई परन्तु वे साबित न हो सकीं ।

वाराणसी तहसील में नलकूप सर्वेक्षण

२—श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव, १—फतेहपुर, २—मकसूदन पट्टी, ३—दारापुरटेहुआ, ४—निमाइच, ५—कनिपर, ६—भरथरा, ७—भरथीपुर, ८—बलुआ ९—कुरु, १०—कोईलार, ११—सरावां , १२—ढोरा, १३—कठिरांव जंगलपुर, १४—नकटी, १५—लखमीपुर, १६—बसनी, १७—कैथेडली, १८—रघुनाथपुर पूर्वी, १९—सगुमहां, २०—गंगाकलां, २१—रतनपुर पचराही, २२—मधुमखियां, २३—कुरु, २४—महिमापुर, २५—मलहथ, २६—खरारिध, खरारियां तालुके विरांव ब्लाक बड़ा गांव, तहसील व जिला वाराणसी में ट्यूबवेल लगाने का सर्वे हो चुका है ? यदि हां, तो उपरोक्त स्थानों में ट्यूबवेल कब तक लग जायेगा ?

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

केवल तीन ग्रामों निमाइच, कोइलर और सरांव में सर्वेक्षण पूर्ण हो चुका है तथा शेष ग्रामों में सर्वेक्षण हो रहा है । वाराणसी जिले में विश्व बैंक की सहायता से प्रस्तावित विकास योजना के अन्तर्गत आगे नलकूप बनेंगे। इस योजना के इस वर्ष के अन्त तक स्वीकार होने की संभावना है ।

३—श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव भटपुरवा, छतांव, भरुई सहमलपुर, कटौना, वरवांजलालपुर, धरसौना, चितौरा, रतनपुर, खलिसपुर, परसरां, गजोखर, देवराई-, सरांय, पिंडरा पूर्वी, पिंडरा दक्षिणी, काशीपुर, मानपुर, भई, धाँधली, रामनगर खूंची, चमरू, कहरका, बंकुंठपुर, रमईपट्टी, हथिवारकोईरीपुर, अनरखापुर चक्का, रसूलपुर, इन्दरपुर, गोरीसालिवाहनपुर, शाहपुर, रामनगर, बाबतपुर, गिरधवलपुर निबाहें, निनदासपुर, ब्लाक पिंडरा, तहसील व जिला वाराणसी में ट्यूबवेल सिंचाई हेतु कब तक लग जायगा ? क्या उपरोक्त स्थानों का इस हेतु सर्वे भी किया जा चुका है ? यदि हां, तो कहां-कहां ?

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

ब्लाक पिंडरा तहसील व जिला वाराणसी के ग्राम दिनबासपुर, छितांव एवं भरुई नहरी कमान्ड में है । शेष ग्रामों का प्रारम्भिक सर्वेक्षण हो चुका है और जिला स्तर पर बनी हुई स्थल चयन समिति की सिफारिशों के अनुसार नलकूप लगाने के लिये विस्तृत सर्वेक्षण किया जायगा ।

निगोही ब्लाक में बिजली

४--श्री रामनाथ दीक्षित--

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला शाहजहांपुर, तहसील तिलहर, के निगोही ब्लाक में कब तक बिजली पहुंचाने की व्यवस्था हो जायगी ?

श्री टम्मनेश्वर प्रसाद--

निकट भविष्य में निगोही ब्लाक में बिजली पहुंचाने की कोई योजना नहीं है ।

बुलन्दशहर जिले में नलकूपों के लिये बिजली

५--श्री हरीसिंह (बुलन्दशहर)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर में १ मार्च, १९६५ से २१ मार्च, १९६७ ई०, तक कितने लोगों ने खेती की सिंचाई के लिये ट्यूबवेल्स के लिये बिजली मांगी है और उनमें कितने लोगों को बिजली दी गई है विशेष तौर पर १ दिसम्बर, १९६५ से १५ फरवरी, १९६७ तक खुर्जा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में कितने लोगों को ट्यूवेल को बिजली दी गई है ?

श्री टम्मनेश्वरप्रसाद--

इस अवधि में बुलन्दशहर जिले में ट्युववेल के लिये ४३६० कनेक्शन स्वीकृत हुये और इनमें से १४०५ कनेक्शन दे दिये गये हैं ।

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर यह सूचना नहीं रखी जाती है ।

वेरी क्वारी ग्राम में सिंचाई

६--श्री इन्द्रलाल--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नैनीताल जिले की तहसील रामनगर के ग्राम वेरी क्वारी (बौक्साड़) की बांध द्वारा सिंचाई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह सिंचाई योजना कब तक पूर्ण हो जायगी ?

श्री टम्मनेश्वर प्रसाद--

जी नहीं । प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता ।

गरया ग्राम के निकट राप्ती बांध कट जाना

श्री कल्पनाथ सिंह--

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ग्राम गरया कोल के पास राप्ती नदी से कोठा रकहट-सेमराघाट बांध कट गया है ? यदि हां, तो इस बांध को ठीक करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही हुई और यह कब तक बन जायगा?

श्री टम्मनेश्वर प्रसाद--

प्रथम भाग--जी हां ।

द्वितीय भाग--ग्राम गरया कोल के पास इस बांध पर सिंचाई विभाग द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया ।

बुलन्दशहर जिले में अपरगंगा कैनाल व छोइया नदी से प्रभावित भूमि

८--श्री नेम पाल सिंह--

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अपर गंगा नहर में जो जिला बुलन्दशहर होती हुई जाती है, उसके जल स्तर ऊंचा होने से कितनी उपजाऊ भूमि बेकार हो गई है ? इस भूमि को बचाने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्री टम्बेश्वर प्रसाद--

अपर गंगा नहर जो जिला बुलन्दशहर होती हुई जाती है उसके जल स्तर ऊंचा होने से उत्तरी डिवीजन गंगा नहर रुड़की में लगभग ७०० एकड़ तथा मेरठ डिवीजन गंगा कैनाल मेरठ में करीब १३० एकड़ ऊपजाऊ भूमि प्रभावित हुई। बुलन्दशहर डिवीजन तथा अलीगढ डिवीजन में कोई उपजाऊ भूमि बेकार नहीं हुई । प्रभावित भूमि को बचाने के लिये नहर के किनारे-किनारे बनी वर्तमान नालियों को गहरा व चौड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है और इन नालियों को बराबर साफ रखने की कोशिश की जा रही है ।

९--श्री नेमपाल सिंह--

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि बुलन्दशहर जिले में छोइया नदी से हर बरसात में जो सैलाब आ जाता है उसके बचाव के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्री टम्बेश्वर प्रसाद--

छोइया नदी नीम नदी में गिरती है और नीम नदी को चौड़ा करने की योजना शासन के विचाराधीन है ।

जमनिया तहसील में कथित चन्द्रप्रभा नहर

१०--श्री कृष्णानन्द राय--

क्या सिंचाई मंत्री बतायेंगे कि चन्द्र प्रभा नहर को गाजीपुर जिले में जमानियां तहसील में कौन-कौन सी शाखायें आधी खुदी पड़ी हुई हैं, पूर्ण नहीं हुई हैं और उन्हें कब पूरा करके पानी दिया जायेगा ?

श्री टम्बेश्वर प्रसाद--

गाजीपुर जिले की जमानिया तहसील में चन्द्र प्रभा नाम की कोई नहर नहीं है ।

* * * *

प्रश्नोत्तर के लिये अधिक समय की मांग

श्री प्यारेलाल (जिला मेरठ)--

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । जितने प्रश्न कार्यसूची में होते हैं उससे डुगने या ड्योढ़े रोज बाकी बच जाते हैं और उन पर अनुपूरक प्रश्न यहां नहीं किये जा सकते । क्या आप उतने प्रश्न रखने की कृपा करेंगे कि जिन के रोज जवाब मिल जाया करें और उन पर अनुपूरक प्रश्न करने का अवसर भी मिल जाय ?

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य ने एक तरह से एक उपयोगी प्रश्न सदन के सामने रखा । मैं उनकी और दूसरे सदस्यों की सूचना के लिये बताना चाहता हूं कि जो संख्या प्रश्नों की आ रही है उसके ऊपर तो मैं नियमों के अनुसार कोई कन्ट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन एक व्यवस्था मैं कर सकता हूं कि पूरक प्रश्नों का जितना समय मैं देता हूं उसे कुछ कम कर दूं । लोक सभा में ऐसी स्थिति में माननीय नेता सदन और नेता विरोधी दल के परामर्श से ऐसी व्यवस्था हुई है कि कुछ प्रश्नों

पर ही वे पूरक प्रश्न किया करते थ । तो ऐसी व्यवस्था में आगे करने का प्रयत्न करूंगा और कुछ समय भी कम दूंगा जिससे ज्यादा से ज्यादा प्रश्न हो सकें ।

श्री अश्वनी कुमार (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, आपका ध्यान इस ओर भी आकर्षित किया गया था कि प्रश्नों के लिखित उत्तर नहीं मिलते । वही शिकायत अभी भी है ।

श्री अध्यक्ष—

मैं इस विषय में अभी-अभी कह चुका हूं । शायद आप उस समय सदन में नहीं थे ।

श्री गेंदा सिंह (जिला बेवरिया)—

श्रीमन्, मैं प्रश्नों के ही सम्बन्ध में एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं । मैं ऐसा समझता हूं कि यह सदन कभी २०० मेम्बरों का था और उस समय भी प्रश्नों के लिये समय एक घंटा था और उस समय प्रदेश की परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि सभी सदस्य प्रश्न कर सकें । तो मेरी प्रार्थना है कि नेता सदन और नेता विरोधी दल और आप मिल कर विचार करें कि प्रश्नों का समय कुछ बढ़ा दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय गेंदा सिंह जी, यह सदन सर्वशक्तिमान है और आप सब मिल कर यदि चाहें वैसा संशोधन नियमों में सदन की अनुमति से कर सकते हैं । लेकिन हाउस आफ कामंस में जो थिंकिंग है इस समय उसके अनुसार वे प्रश्नों का समय कम कर रहे हैं । वे सप्ताह में कुछ दिन ही प्रश्न रखेंगे, ऐसा वे कर रहे हैं ।

उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड, कानपुर के कार्यकरण पर १९६५–६६ की रिपोर्ट

उद्योग उपमंत्री (श्री हिम्मत सिंह)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड, कानपुर के कार्य-करण पर वर्ष १९६५–६६ की रिपोर्ट की कम्पनीज ऐक्ट, १९५६ की धारा ६१९–ए के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (निर्माण कार्यों के लिये विस्तृत नक्शे और तखमीने तैयार और स्वीकृत करने तथा टेन्डर आदि आमंत्रित करने, उनकी जांच करने और उन्हें स्वीकार करने की) नियमावली, १९६३, में प्रख्यापित संशोधन †

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बरमेश्वर पांडेय)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश नगरमहापालिका (निर्माण कार्यों के लिये विस्तृत नक्शे और तखमीने तैयार और स्वीकृत करने तथा टेन्डर आदि आमन्त्रित करने, उनकी जांच और उन्हें स्वीकार करने की) नियमावली, १९६३ में, नगरपालिका विभाग की विज्ञप्ति संख्या ४२७१-बी (नि-१३) (संशो०–१)/११-ग–कार्प (६)-५७, दिनांक १० अप्रैल, १९६७ द्वारा प्रख्यापित संशोधनों को, उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ की धारा ५४० की उपधारा (४) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

---

†छापी नहीं गई ।

कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) (द्वितीय) आदेश, १९६७*

शिक्षा उपमंत्री (श्री अनन्तराम)--

अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से शिक्षा (ग-१) विभाग की विज्ञप्ति संख्या ग-१--२१७क/१५-३९ (७४)-६६, दिनांक १७ मई, १९६७ द्वारा प्रख्यापित "कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) (द्वितीय) आदेश, १९६७" को, कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय अधिनियम, १९६५ की धारा ५० की उपधारा (२) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान मंडल सदस्यों की उपलब्धियों की (द्वितीय) (संशोधन) नियमावली, १९६७†

शिक्षा उपमंत्री (श्री अनन्तराम)--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से विधायिका विभाग की विज्ञप्ति संख्या २३६क-१७--२३१-६४, दिनांक ५ जून, १९६७ द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों का) अधिनियम, १९५२ की धारा २ की उपधारा (३) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

सदन के अधिवेशन काल में सरकारी नीति की सदन से बाहर घोषणा करने के संबंध में वन मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष--

मुझे माननीय कृष्णानन्द राय द्वारा एक विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना मिली है, वह इस प्रकार है --

"संसदीय परम्परा एवं औचित्य के अनुसार यह आवश्यक है कि जब सदन की बैठक चल रही हो या आहूत कर ली गयी हो तो मंत्रिपरिषद् के सदस्य नीति संबंधी महत्वपूर्ण घोषणाएं सदन में करें जिससे कि सदन उन घोषणाओं की सत्यता का परीक्षण कर सके। आज, अर्थात् २० जून, १९६७ के "नेशनल हेराल्ड" में यह समाचार प्रकाशित है, जिसे मैं सत्य समझता हूं कि झांसी की एक जनसभा में श्री विकल ने विगत शनिवार को यह घोषणा किया है कि प्रदेश में भूमि पर पूरी लगान शनैः शनैः तथा कम जोतों का लगान तुरन्त समाप्त की जायगी। सदन का बजट अधिवेशन इस समय चल रहा है और यह घोषणा उन्हें सदन में करनी चाहिये थी। किन्तु उनका यह कथन नितांत गलत है और असत्य था अतः सदन में घोषित न करके इसे जनता में मिथ्या प्रचार के रूप में उन्होंने घोषणा की। कल अर्थात् १९ जून, १९६७ को मंत्रिपरिषद् के सदस्य श्री उदित नारायण शर्मा ने विधान परिषद् में यह घोषणा की है कि उनकी सरकार ने लगान समाप्त करने का निश्चय नहीं किया है। यह श्री विकल के कथन को असत्य सिद्ध करता है। ऐसी स्थिति में श्री विकल ने सदन के प्रति अपने मंत्रिपरिषद् के दायित्व का निर्वाह नहीं किया है और सदन का अवमान किया है। अतः उनके विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की कार्यवाही की जाय।"

श्री विकल जी, यह जो समाचार के बारे में इसमें आरोप है कि आपने ऐसी घोषणा की, यह ठीक है या नहीं ? यानी सत्र के आरम्भ हो जाने के बाद सदन के बाहर नीति संबंधी घोषणा की, क्या यह बात ठीक है ?

---

*छापा नहीं गया।

†छापी नहीं गयी।

वन मंत्री (श्री रामचन्द्र विकल)---

कृष्णानन्द राय जी ने अखबार का हवाला दिया, अच्छा होता वह बात कर लेते। लेकिन फिर भी संयुक्त विधायक दल का जो कार्यक्रम है जब लोग उसके संबंध में मुझसे सवाल करते हैं और अखबार वाले भी करते हैं तो मैं यह कह देता हूं कि हमारा इरादा अपनी आर्थिक कठिनाइयों को दूर करके धीरे धीरे उन प्रोग्रामों का पूरा करने का है। हम उनको किस्तों में पूरा करेंगे, इतना मैंने कहा है।

श्री कृष्णानन्दराय (जिला गाजीपुर)---

विकल जी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि वे आजकल अखबारों में या जहां कहीं भी जा रहे हैं इस बात को कहते चले जा रहे हैं कि १९ सूत्री कार्यक्रम के अनुसार हमें जब आर्थिक साधन उपलब्ध होंगे तो लगान समाप्त करने का प्रयास करेंगे। श्रीमन्, मैंने जो प्रिविलेज का प्रश्न उठाया है वह बड़े महत्व का है। आज कल बजट सेशन चल रहा है, अगर लगान समाप्ति की घोषणा करनी है तो सरकार को यहां सदन में ही करना चाहिए, न कि बाहर घूम घूम कर जनता में भ्रामक प्रचार करके.....

श्री अध्यक्ष--

अब और अधिक इस पर प्रकाश की आवश्यकता नहीं है.....

श्री कृष्णानन्द राय--

यह अजीब भ्रमपूर्ण वातावरण बनाये हुये हैं। यहां सदन में कहते हैं हम नहीं करेंगे, जनता में जाकर कहते हैं करेंगे। यह सदन का अवमान है।

(श्री नवल किशोर के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

अब इस पर और वादविवाद की आवश्यकता नहीं है। एक विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न था। जिसने उस प्रश्न को उठाया था उसको मैंने सुन लिया, जिसके खिलाफ वह उठाया गया था उसको भी मैंने सुन लिया। जहां मुझे स्वयं कोई सन्देह होता है, मैं माननीय सदस्यों की मदद ले लेता हूं।

श्री नवल किशोर (जिला बरेली)--

इस प्रस्ताव में एक चीज और है जो नहीं आ पायी है। बजट पेश हो गया, बजट भाषण भी पेश हो गया, उसमें कहीं इस बात की चर्चा नहीं की गयी है कि लगान माफ होगा। बजट में कोई बात निहित नहीं है मगर बाहर तालियां पिटवाने के लिये यह सब कहा जाता है।

(श्री गेंदासिंह के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

मैं आप का आदर करता हूं, मगर इस तरह में समय दूंगा तो अनेक माननीय सदस्यों को समय देना पड़ेगा।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---

मैं माननीय कृष्णानन्द राय जी के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। मैं माननीय रामचन्द्र विकल जी को बधाई देता हूं कि बजट आने के बाद भी उन्होंने यह कहने का साहस किया कि लगान माफ किया जायेगा। यह तो अच्छी बात है। माननीय कृष्णानन्द राय जी को इसे वापस लेना चाहिये। (हंसी)

मुख्य मन्त्री (श्री चरण सिंह)--

मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इस पर आप अपना अन्तिम निर्णय देने के पूर्व ट्रेजरी बेंचेज को भी अपनी राय देने का अवसर देंगे ?

श्री अध्यक्ष--

मुझे कोई आपत्ति नहीं है, अगर आप चाहते हैं तो कहें।

श्री चरण सिंह--

मेरा कहना यह है कि बावजूद विधान सभा या संसद का सेशन होने के, मिनिस्टर्स को यह अख्तियार है कि बाहर भी पालिसी स्टेटमेंट कर सकते हैं। अगर वे न करें तो अच्छा है, लेकिन इस विषय की बहुत सी रूलिंग्स हैं और पार्लियामेन्टरी रूलिंग्स हैं कि बाहर स्टेटमेंट हो सकते हैं। इसलिये अगर आप अपनी राय जाहिर करने के पूर्व गवर्नमेंट को भी मौका दें अपना पक्ष रखने का, तो शायद ज्यादा मुनासिब होगा।

श्री अध्यक्ष--

मुझे इसमें तो कभी कोई एतराज नहीं होगा, न ही एतराज है, अगर सरकार मुझे यह बताना चाहे कि इस तरह की कोई परम्परा है या इसके लिये कोई रूल्स इजाजत देते हैं। इस पर अगर माननीय नेता सदन कुछ कहना चाहते हैं तो वे कुछ समय लेने के बाद भी कह सकते हैं, मैं सुनने के लिये अवश्य तैयार हूं क्योंकि मैं समझता हूं कि यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। महत्वपूर्ण इसलिये भी है कि यह नीति से संबंधित है।

माननीय मंत्रिमंडल के सदस्य ऐसी नीति की घोषणा सदन के बाहर कर सकते हैं, कारण में औचित्य है। इसमें संसदीय परम्पराओं का अनुसरण है या नहीं है, एक तरह से महत्वपूर्ण प्रश्न है। साधारणतया मैं इसमें कोई आवश्यकता नहीं समझता था किसी और जानकारी की लेकिन अगर नेता सदन उसमें समय चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है या अगर अभी.....

श्री चरण सिंह--

२६ तारीख को।

श्री अध्यक्ष--

मैं २६ तारीख को इस विषय को लूंगा।

श्री अब्दुल मुईज खां (जिला बस्ती)--

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा एक और भी पहलू इस विषय का निकलता है।

श्री अध्यक्ष--

मैंने उस विषय पर तारीख निश्चित कर दी है उस पर भी उसी दिन विचार हो जायेगा,।

श्री अब्दुल मुईज खां--

अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि वित्तीय साल पर जो ऐसे ऐसे विभिन्न वक्तव्य हुआ करते हैं और उसके लिये वह बात तो सही है कि माननीय नेता सदन अपनी बात जाहिर करेंगे। लेकिन जो एक विशेष परिस्थिति है, जो बजट सेशन चल रहा है, इसके संबंध में कई मोटी-मोटी किताबें, सरकार के जितने इरादे हैं.....

श्री अध्यक्ष--

यह वक्त कोई भाषण का नहीं है।

श्री अब्दुल मुईज खां---

उस बजट के लिट्रेचर में जरा भी गलती नहीं है, लेकिन वही बाहर कही जाय तो वह ही गलत मालूम होती है ।

श्री अध्यक्ष---

इस पहलू पर भी विचार कर लिया जायेगा ।

(माननीय टम्बरेश्वर प्रसाद के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष---

आप किस विषय पर बोलना चाहेंगे ?

सिंचाई मंत्री (श्री टम्बरेश्वर प्रसाद)---

माननीय कृष्णानन्द राय जी ने राय प्रकट की है उसका प्रश्न इस विषय में नहीं उठता है ।

उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, १९६७

श्री अध्यक्ष---

उठे या न उठे, मैं २६ तारीख को ही इस विषय को लूंगा ।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बरमेश्वर पांडेय)---

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, १९६७ को पुरःस्थापित करने के हेतु सदन की अनुज्ञा चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, १९६७ को पुरःस्थापित करने के हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री बरमेश्वर पांडेय---

अध्यक्ष महोदय मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय अल्पकालिक व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९६७ को पुरः स्थापित करता हूं ।

(देखिये नत्थी (ख) आगे पृष्ठ २९४-२९५ पर)

१९६७-६८ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (जारी)

श्री नवल किशोर (जिला बरेली)---

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान समय के विभाजन की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । परम्परा यह थी कि जो विरोधी दल होता था उसको हम आधे से अधिक समय दिया करते थे चाहे उनकी तादाद जितनी कम क्यों न रही हो । विरोधी दल में सात आठ पार्टियां थीं, उनके नेता सात-आठ हुआ करते थे । अगर उस ओर से मन्त्रिगण बोलते थे तो मैं चाहता हूं कि आप कृपा करके ऐसा समय का विभाजन कर दें कि जनरल डिबेट में इस पक्ष को अगर अधिक नहीं तो कम से कम आधा समय तो दिया ही जाय । ऐसी मेरी मांग है कि इस पक्ष को आधे से ज्यादा समय देना चाहिये ।

---

*१९ जून, १९६७ की कार्यवाही से ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय नवल किशोर जी ने जो प्रश्न उठाया, यह प्रश्न इस सदन में कई बार उठ चुका है। माननीय खेर साहब ने सन् १९५३ में जब इस प्रकार की व्यवस्था उठायी गयी थी तो जो व्यवस्था उन्होंने दी थी उसे मैं सदन की जानकारी के लिये सुना देता हूं—

"यह तो पहले व्यवस्था हो चुकी है कि एक घंटा इसमें दिया जायगा और बजट के बारे में साधारण प्रथा यह रही है कि विरोधी दल वाले जो ज्यादा दिलचस्पी इसमें रखते हैं वे बोल सकें, क्योंकि सरकारी पक्ष के लोगों को तो मौका यह माना जाता है कि जो कार्यक्रम वह रखना चाहते हैं विचार करके रखते ही हैं। तो उनको अधिक बोलने के लिये समय देना बजट के समय, मैं समझता हूं उचित नहीं है। हालांकि उनको भी बोलने का अधिकार तो है ही। इसलिये विरोधी दल के सदस्यों के सुझाव पर मैंने व्यवस्था दे दी। उस समय किसी ने आक्षेप नहीं किया। अब अगर आपको दिक्कत हो रही है और आप बोलना चाहते हैं तो दूसरी कटौती पर आपको मौका मिल जायगा।"

इस तरह से पहले यह व्यवस्था दी है कि विरोधी दलों को अधिक अवसर देना चाहिये। इसके बाद तो एक नहीं अनेकों ऐसी व्यवस्थायें हैं। बात भी ठीक है कि जो बजट प्रस्तुत होता है सरकार की ओर से, समझ बझ कर, उस पर विचार-विमर्श करके कि यह माना जायगा, रखा जाता है। उस पर स्वाभाविक है कि विरोधी पक्ष को पूरा अवसर होना चाहिये और अधिक समय उनको मिलना चाहिये। अब समय के इस सिद्धांत को मैं स्वीकार करता हूं और जहां तक समय के आबंटन का प्रश्न है, मैं माननीय नेता विरोधी दल और माननीय नेता सदन से बात करके कोई ऐसा तरीका निकालूंगा जिससे इस सिद्धांत का प्रतिपादन होते हुये भी सभी को समय मिल जाय।

*खाद्य मंत्री (श्री झारखंडेराय)—

मान्यवर, मैं कल इस बात की चर्चा कर रहा था जिसका सीधा संबंध माननीय गुप्ता जी से था। मैं उनको यह याद दिला रहा था कि वे इस बात को न भूलें कि पिछले २० सालों तक हिन्दुस्तान में कांग्रेस का ही एकछत्र शासन रहा है और आज की जो वर्तमान स्थिति है, आज की जो वर्तमान दुर्व्यवस्था है, वह २० साल तक की कांग्रेस शासन की गलत नीति व पूंजीवादी नीति का ही परिणाम है। उसी का परिणाम है कि आज बढ़ती हुई बेकारी है, बेरोजगारी है और बढ़ती हुई बेगारी है, जिसका इस सरकार को भी सामना करना पड़ रहा है और साहसपूर्वक सामना करना पड़ेगा।

आपने खाद्य समस्या की चर्चा की। खाद्य की समस्या हमारी राष्ट्रीय समस्या है। देशभक्ति की परिभाषा समय-समय पर बदलती रही है और बदलनी चाहिये। एक युग था जब कि देशभक्ति इस बात में मानी गयी कि देश को आजाद करने के लिये अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया जाय और देश के लाखों लोगों ने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। एक युग आया जब कि चीन और पाकिस्तान का हमला देश पर हुआ। उस समय देशभक्ति की परिभाषा यह हुई कि बड़ी कठिनाई से अपनी अर्जित आजादी की हम रक्षा करें और उसके लिये सब कुछ न्योछावर कर दें। आज भी किसी से कम देशभक्ति हिन्दुस्तानियों में नहीं है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम सब मिल कर इस राष्ट्रीय महान समस्या का समाधान करें जिसे हम खाद्य समस्या कहते हैं। इसी आधार पर हम सारी चीजों को लेते हैं। कुछ विषय ऐसे हैं जो राजनीति और दलों से ऊपर हैं, जैसे देश की सुरक्षा। इसी प्रकार से खाद्य की समस्या भी राजनीति और दलों से ऊपर है। पिछले २० सालों में जो खाद्य समस्या का समाधान नहीं हुआ इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस सरकार और कांग्रेस की गलत नीतियों के ऊपर है। अब आगे अगर हम इस मामले में कोई परिवर्तन नहीं ला सकें तो उसके लिये

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हम जिम्मेदार हो सकते हैं और हमारे संयुक्त विधायक दल की सरकार हो सकती है। लेकिन उसकी जिम्मेदारी इस दो महीने की सरकार पर आयद नहीं हो सकती बल्कि वह आयद होती है कांग्रेस की पुरानी २० साल की सरकार पर। हिन्दुस्तान में करोड़ों एकड़ और इस प्रदेश में लाखों एकड़ भूमि जिसका सम्यक बटवारा आज तक नहीं हुआ है। लखीमपुर जिले में ही ३,६०० एकड़ के फार्म हैं, जो बड़े-बड़े पूंजीपतियों और भू-स्वामियों के हाथों में है। क्या इन बड़े-बड़े फार्मों का वजूद हमारी नीतियों का फल है? अगर प्रत्येक परिवार को ५-५ एकड़ बांटा गया होता तो ७०० परिवारों को रोजी-रोटी दी जा सकती थी और ५ आदमियों का परिवार अगर हम मान लें तो ३५०० आदमियों को रोटी दाल मिल सकती थी। इस प्रकार की स्थिति सारे तराई एरिया में है। जिस पर पुराने रिटायर्ड लोग, पूंजीपति, भूस्वामी अधिकार किये हुये हैं। ऐसा मालूम होता है कि सरकार की ओर से उन लोगों को खैरात बांटी गयी है। क्या यह हमारी नीतियों का फल है? मैं माननीय गुप्ता जी का बड़ा आदर करता हूं और करता रहा हूं....

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि क्या वे यह घोषणा करने जा रहे हैं कि प्रदेश के जो बड़े-बड़े फार्म हैं उन फार्मों का वे राष्ट्रीयकरण कर देंगे? अगर नहीं, तो उसका क्या कारण है?

श्री झारखंडेराय—

हम उन तमाम कुरीतियों को खत्म करने का प्रयास करेंगे जिन्हें हम देश और प्रदेश के हित में बाधक समझते हैं।

दूसरी बात सिंचाई के साधनों की है। सिंचाई के साधनों के लिये जो प्रयास अभी तक किया गया है वह नाकाफी है। अब तक जो भी २० साल में सिंचाई के साधन मुहैया किये गये वे एक सूखा का भी मुकाबला नहीं कर सके। इन साधनों को हमें तेजी से बढ़ाना है और यही कारण है कि पूरे बजट भाषण को एग्रीकल्चर का बजट कहा जा सकता है। हम यह महसूस करते हैं कि अगर हम एग्रीकल्चर का समुचित विकास न कर सके तो हमारे उद्योग धंधे भी नहीं पनप पायेंगे। पिछली सरकार ने पहली पंचवर्षीय योजना कृषि की योजना के नाम से बनायी, दूसरी पंचवर्षीय योजना उद्योगों की बनायी और तीसरी पंचवर्षीय योजना कृषि और उद्योग दोनों की मिली हुई बनायी। लेकिन अदूरदर्शिता के कारण यह सरकार उनको ठीक प्रकार से कार्यान्वित नहीं कर पायी। चौथी योजना दिशा शून्य रही। इस दिशा शून्य अवस्था को हम समाप्त करना चाहते हैं। हम यह महसूस करते हैं कि कृषि हमारी आधारशिला है और उसको मजबूत होना चाहिये। इसका उस तरफ के माननीय सदस्यों को भी स्वागत करना चाहिये।

मान्यवर, एकोनामिक मेजर्स की चर्चा करते हुये माननीय गुप्ता जी ने छटनी और बेरोजगारी की चर्चा की। छंटनी से हमको किसी प्रकार से भी सुख नहीं मिलता, यह हमारे लिये बड़े दुख की बात है। लेकिन जब हम अपने सीमित साधनों को देखते हैं और जनता को पहुंचाई जाने वाली दूसरी सहूलियतों को देखते हैं और जब हम देखते हैं कि डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट बेकार बने हुये हैं, विभागों में अनावश्यक आदमी भरे पड़े हैं, मानो बड़े-बड़े खैरातखाने हों, जहां काम धंधा कुछ नहीं है, तो हमें विवश हो कर इसके लिये सोचना पड़ता है। इस सब का श्रेय भी मैं गुप्ता जी की सरकारों को ही देता हूं। हम उस समस्या का समाधान करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि किसी को रिट्रेंच करें, एक भी आदमी की रोजी-रोटी हम नहीं छीनना चाहते, जो आज भी बहुत से बेकार हैं उनमें और भी बेकार लोगों को हम जोड़ना नहीं चाहते और हम हर एक आदमी का खयाल रखेंगे, लेकिन कुछ कार्य हमें अनिवार्यरूप से करने ही हैं। अगर हमने एकोनामी मेजर्स को न अपनाया तो जो राहत हम लोगों को पहुंचाना चाहते हैं वे कैसे पहुंचा पायेंगे, जो संयुक्त विधायक दल के सूचना पत्र में हैं जो लगान

[श्री झारखण्डे राय]

पिछली सरकार ने ४ आने वाला माफ किया था, हमने जो भूमिभवन कर समाप्त किया है, उसके लिये रुपया कहां से आयेगा ? हमने सरकारी कर्मचारियों को दस करोड़ रुपया दिया है हालांकि वह अभी असंतुष्ट हैं और दुखी हैं; उनकी समस्याओं का समाधान होना चाहिये लेकिन हमारे प्रयास का फल है कि अब मामला शांत हुआ है और जरूरत इस बात की है कि वह और सरकार मिलकर, बैठकर कोई रास्ता निकाले ताकि उन की समस्याओं और मांगों का एक शांतिपूर्ण समाधान हो सके। राज्य कर्मचारी, सरकार के एक अंग हैं, उन को अपना शत्रु बनाकर कोई सरकार चल नहीं सकती। जो वातावरण आज बन रहा है उसमें फिर से उन की मांगों पर शांतिपूर्ण तरीके से और गम्भीरता के साथ बैठकर विचार हो सकता है और अपने साधनों को देखते हुए हम जरूर विचार करेंगे।

एकोनामी मेजर्स एक कठिन और कड़वी चीज है और अगर वह न लिये जायं तो फिर रिलीफ हम कहां से दें ? एकोनामी मेजर्स का नतीजा है कि छटनी हो। एक विसेज सर्किल बना हुआ है जिससे निकलने का रास्ता बनाना बहुत कठिन है और वह सारे का सारा पिछली कांग्रेसी सरकार का बनाया हुआ है और उसी की जिम्मेदारी है, अपनी २० साल की गलत नीति से उसने इसे पैदा किया है और हमें उसमें बुनियादी तौर पर परिवर्तन करना होगा और उन की बहुत सी नीतियों को हमेशा के लिये जमींदोज करना होगा। जब हम उन को गहरे धरती के नीचे दबा देंगे तभी प्रगति की तरफ आगे बढ़ सकते हैं।

माननीय गुप्ता जी ने कहा कि उधर यह ८ दल कैसे इकट्ठा हैं। मैं उन से सत्य कहता हूं कि यह इतिहास का कठोर सत्य है और इस को अब उन्हें स्वीकार करना ही होगा, इससे वह अब इंकार नहीं कर सकते। इस तरह की बात को बार-बार दोहराने से अब कोई लाभ न होगा। हमने अपने दल को जनता के निर्दोष मेनडेट के सामने सिर झुकाकर खड़ा किया है और एक एरिया आफ एग्रीमेंट पर हमारी बुनियाद मजबूत है। उस एरिया आफ एग्रीमेंट में कोई किसी तरह का मतभेद नहीं है। कुछ लोग कुछ लोगों को देशद्रोही समझते हैं और बड़े अनोखे ढंग और तरीके से राजनैतिक चाल चली जाती है, लेकिन मैं उन को बता देना चाहता हूं कि हमारे अन्दर डिवीजन हो, वह स्वप्न उन का पूरा न होगा और यह डिवीजन इसलिये नहीं होगा क्योंकि हमारे अन्दर कोई मतभेद नहीं है। मतभेद लोगों में होता है, दल और दल में होता है, लेकिन हमारा जो कामन प्रोग्राम है उसमें कोई मतभेद नहीं है। मैं उधर के लोगों को जानता हूं कि उन में भी मतभेद रहा, लेकिन वह सिद्धांत और नीतियों का कम रहा, और कुर्सियों का ज्यादा रहा। हमारे यहां तो मतभेद नीतियों का है और उस मतभेद को भी हमने स्थगित और मुल्तवी कर रखा है और न मैं उस की इस समय चर्चा ही करना चाहता हूं। हम एक एरिया आफ एग्रीमेंट के अनुसार काम करना चाहते हैं ताकि हम उसके अनुसार काम करके एक जिम्मेदारी के साथ सूबे की महान् जनता को कुछ न कुछ राहत दे सकें। इसी उद्देश्य से हम काम करेंगे और अगर उस में सफल रहेंगे तो सरकार में हम रहेंगे, वर्ना हम शासन छोड़ देंगे। हमारा प्रयास है और इरादा है कि हम ईमानदारी से इस प्रदेश की जनता की सेवा करें....

(व्यवधान)

श्री चन्द्रदेव (जिला देवरिया)---

अध्यक्ष महोदय,... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

माननीय चन्द्रदेव जी, आप बैठ जायं, इस तरह से इंटरप्शन करने से कोई लाभ नहीं है।

श्री झारखंडे राय---

आप कुछ भी कहें, लेकिन हमारा एरिया आफ एग्रीमेंट एक है और वह हर तरह से मजबूत है, हमारे मतभेदों में भी एकता है, यह यूनिटी-इन-डाइवर्सिटी है और हम एक दूसरे के मतभेदों

को जानते भी हैं और जानते हुये भी हम साथ हैं, साथ रहेंगे, जानबूझ कर हम ने अपने मतभेदों को मुल्तवी किया है और तब तक एरिया-आफ-एग्रीमेंट पर पूरा काम नहीं हो जाता हम साथ रहेंगे ।...

(एक सदस्य के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य बैठ जायं, इस तरह से बीच में न खड़े हों, अगर वह बैठ जायं तभी आप बोल सकते हैं ।

श्री झारखंडेराय--

मैं आज एक बात की चेतावनी सदन में देना चाहता हूं । आज पूरे राष्ट्र तथा सभी प्रदेशों के सामने एक महान् संकट है और वह संकट साधनों का है, यह एक क्राइसिस आफ रिसोर्सेज है जिसके बीच से होकर हमारा सारा राष्ट्र गुजर रहा है । चाहे केंद्र हो या राज्य सरकारें हों, सब के सामने यह अभाव है और उस का समाधान हमें मिलकर करना होगा । आज यह समय की पुकार है कि किसी तरह भी हो इसका समाधान शीघ्र किया जाय । अगर सूबा सरकारें और केंद्र सब मिलकर इस क्राइसिस आफ रिसोर्सेज पर काबू न पा सकेंगे तो कोई काम नहीं चलेगा और हम चकनाचूर हो जायेंगे । हमें कोई न कोई रास्ता रिसोर्सेज को बढाने का निकालना होगा । यह भी हमें समझना चाहिये कि हमारे साधन सीमित हैं । मैं माननीय वित्त मंत्री जी और उन के विचार का स्वागत करता हूं, उन्होंने इस को समझा है कि अब कर अधिक देने की जनता में क्षमता नहीं है, कम से कम उस समय तो वह क्षमता समाप्त हो गई है । यह बात मैं ही नहीं कहता और यह न केवल वित्त मंत्री जी का ही विचार है बल्कि आज के बड़े-बड़े अर्थशास्त्रियों का भी यही मत है । हिन्दुस्तान की साधारण जनता की टैक्स पेइंग कैपेसिटी समाप्त हो चुकी है। जब तक जिन्दगी का मियार न ऊंचा उठे, जब तक जीवन का स्तर न ऊंचा उठे, जब तक लिविंग स्टैन्डर्ड न ऊंचा उठे तब तक के लिए नए टैक्स हमारे देश और प्रदेश की जनता पर लगाना गलत होगा । इसलिए हम उस खतरनाक कदम को नहीं उठा सकते और सिद्धान्ततः उस को हम गलत समझते हैं। इसमें साहस की बात नहीं है कि हम में साहस नहीं है और पहले वाली सरकार में बड़ा साहस था । वह पूंजीपतियों की सरकार थी । जब उन पर टैक्स लगाने के उपाय नहीं मिलते, उनको रद्द करने का उपाय नहीं मिलता था, पूंजीपतियों को दबोचने का उपाय नहीं मिलता था तो घुमा फिराकर जनता पर टैक्स लगाने का रास्ता अपनाती रही है, जो मौत की घाटी है । जनता के ऊपर टैक्स लगाती रही है सीधे या टेढ़े । इस हकीकत को हम को समझना चाहिए ।

शासन यन्त्र की चर्चा की गई कि कोई खास परिवर्तन नहीं । जरूर परिवर्तन नहीं है जनता भी कह सकती है । लेकिन दो महीने में जादू की लकड़ी नहीं घुमायी जा सकती है । मैं गुप्ता जी से पूछना चाहता हूं कि जब आजादी के बाद शासन सूत्र कांग्रेस के हाथ में आया तो कांग्रेस के नेताओं ने, जिस में पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे, कौन-सा प्रयास हुआ हिन्दुस्थान में पूरे शासन यन्त्र के आमूल परिवर्तन का ? कुछ नहीं, वही विरासत अंग्रेजों की बनायी हुई कांग्रेस ने ली । वही विरासत हम को भी मिली है । इस हकीकत को हम को नहीं भूलना चाहिए । यह हमारी क्षमता, मनोबल और लायकी के ऊपर है कि इस विरासत को परिवर्तित करें ; और यह हम को करना पड़ेगा अगर हम सचमुच अपने ध्येय को सफलीभूत करना चाहते हैं ।

मान्यवर, समाजवाद की चर्चा गुप्ता जी ने भी की जो हम लोग वहां से किया करते थे । समाजवाद के बारे में हम को कोई भ्रम नहीं है । समाजवाद कांग्रेस सरकार स्थापित नहीं कर सकी, न कर सकती है और न कर सकेगी । इस में मुझे कोई सन्देह नहीं है और मैं यह भी कहता हूं कि यह सरकार जो एस० बी० डी० की बनी है वह समाजवाद की सरकार नहीं है । झूठा ढोंग हम नहीं करना चाहते हैं । हमारा ३६ प्वाइन्ट का एक प्रोग्राम है उसीको

[श्री झारखण्डे राय]

हम क्रमशः जैसा विकल जी ने कहा है, पूरा करें। यही हमारा एक दृढ़ विचार है और उसी ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। यह कोई समाजवाद परिवर्तन की बात नहीं है। इसलिए समाजवाद का नाम लेना और अमल में पूंजीवाद को पनपाना, यह हम नहीं करना चाहते हैं। हम तो कहते हैं कि प्रगतिशील कदम उठाते जायें, रेडिकल चेंजेज करते जायं और समाजवाद के लिए मार्ग प्रशस्त कर पायें, यही हम बहुत समझते हैं, एक सीमित दायरे के अन्दर महदूद रहते हुए।

आखिर में एक बात कहना चाहता हूं। मुझे निहायत तकलीफ उस समय हुई जब कांग्रेस के लोगों ने बैठ कर के गल्ले की सीधी खरीद का विरोध किया और माननीय कमलापति त्रिपाठी जी ने किया। मैंने कल इसकी चर्चा की थी। चाहता हूं उसको पुनः दोहरा देना, क्योंकि दोनों दिग्गज, श्री गुप्ता और श्री त्रिपाठी यहां बैठे हुए हैं। अगर ७,८ प्रतिशत किसानों के ऊपर लेवी लगी हुई है और ९२ प्रतिशत किसान इससे मुक्त हैं तो यह क्या किसान विरोधी काम है? या वह लोग किसान विरोधी हैं जो ७, ८ प्रतिशत किसानों की ताईद करते हैं? इससे उदार कौन-सा कानून बन सकता है? मैंने कल कहा और अब भी कहता हूं कि उस में कमियां हो सकती हैं, लेकिन कमियां ज्यों-ज्यों मालूम हुयीं, उस में तरमीम की गई। हम कोई ब्रह्मा तो हैं नहीं कि जो एक बार तय कर लिया वह ब्रह्म लेख है, उस में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। नहीं, हमने जनता के सामने, जन प्रतिनिधियों की भावनाओं के सामने सर झुकाया और उन को मान कर के परिवर्तन किया है और आगे भी परिवर्तन का जो उचित सुझाव दिया जायगा उस को करेंगे। हम कहना चाहते हैं कि जब बाबू गेंदा सिंह खाद्य मन्त्री थे, गुप्ता जी मुख्य मन्त्री थे तभी से यह स्कीम बनी हुई थी। उसी को हमने भी स्वीकार किया क्योंकि हमारे सामने कोई रास्ता नहीं है। पंजाब का जोन केंद्रीय सरकार की कमजोरी से अलग हो गया है। अब केंद्रीय सरकार का गेहूं है और अपना बाहुबल रह गया है। अगर चीप पापुलेरिटी हासिल करना है तो उसे हासिल करने का यह दुष्प्रयासमात्र है। इसलिये मैं कहूंगा कि इसका विरोध मत कीजिये। यह राष्ट्रीय समस्या है। हम और आप मिल कर इसको हल करें।

चीन के आधुनिक नेताओं की बददिमागी बढ़ रही है। फिर चीन का हमला हो सकता है। वह अपने अन्दर के विरोध को डाइवर्ट करने के लिये सब कुछ कर सकता है। उस समय क्या हमारे और गुप्ता जी के बीच में खाई रहेगी? नहीं रहेगी, मिट जायगी और मिट जानी चाहिये। देश ने पहले चीन व पाकिस्तान के आक्रमण के समय दो बार परीक्षा दी है। कुछ चीजें हैं, जैसे खाद्य समस्या, उनमें हम एक स्वर हो कर चलें, एक कदम मिला कर चलें। बाकी रही राजनीति की अखाड़ेबाजी वह तो चलती रहेगी क्योंकि पूंजीवाद और प्रगतिवाद में कोई समझौता नहीं हो सकता।

*श्री चतुर्भुज शर्मा (जिला जालौन)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इस बजट को पढ़ा। मेरी यह इच्छा थी कि मेरे पुराने मित्र श्री चरण सिंह जो इस सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं बहैसियत मुख्य मंत्री के उन्होंने यह पहला बजट पेश किया है इसमें कोई भी बात किसानों के अथवा जनता के हित की दिखाई देती तो मैं उनको बधाई देता। मुझे बड़ा अफसोस है कि मैं उसे नहीं पा पाया। हां, मैं उनको इस बात के लिये अवश्य बधाई दे सकता हूं कि चरण सिंह जी ने कुछ उग्रसेन, व्यग्रसेन, कुछ नीले सिंह तथा कुछ पीले सिंह को एक रस्सी में बांध कर कठघरे में बन्दकर दिया है और उनको पालतू बना दिया है। इसके लिये उनको अवश्य बधाई मिल सकती है। लेकिन फिर सोच में आता है कि एक पीले जनसंघी मदारी ने हमारे डबल सिंह को कठघरे में बन्द करके उसको पालतू बना लिया और अपने इशारे पर उनको नचा रहा है, वह बधाई फीकी पड़ जाती है। जनतांत्रिक प्रणाली की कुछ शुद्ध परम्परायें होती हैं, लेकिन वह उनको भूल गये। कोई भी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बजट प्रतिबिम्ब होता है किसी शासन को देखने का। यह बजट जो साल भर के लिये बनाया गया है इसमें संकेत हो सकता था कि वह किस दिशा में जा रहे हैं। अभी-अभी झारखंडे राय जी ने कांग्रेस के २० साल के कुशासन पर संकेत किया, लेकिन आगे उनको क्या गति लानी है इसका कोई संकेत नहीं दिया। समाजवादी व्यवस्था लानी है, समता लानी है, किसान तथा मजदूरों का हित करना है, आम जनता का हित करना है उसके लिये कहीं भी इसमें संकेत नहीं है, कहीं भी नाम नहीं है। क्या कहीं इसकी बात भी कही गयी ? समाजवाद के नाम को कसदन हटाया गया। यह नहीं कि मुख्य मंत्री जी नहीं चाहते होंगे, हमारे झारखंडे राय जी नहीं चाहते होंगे, हमारे सोशलिस्ट भाई नहीं चाहते होंगे या उल्टे कांग्रेसी भाई नहीं चाहते होंगे जो गवर्नमेंट में शामिल हैं। हम लोग तो कांग्रेस जन हैं और जो भाई हमको छोड़ कर गये हैं वे जन कांग्रेस हैं। कांग्रेस जन के माने हैं जो जनहित को पहले रखता है और अपने को पीछे रखता है, जो अपने हित को छोड़ कर देश के हित को आगे रखे। और जब वह उलट कर दूसरी तरफ गया तो जन कांग्रेस हो गया। यानी, उसने अपने को आगे रखा और कांग्रेस और देश के हित को पीछे ढकेल दिया, क्योंकि १६ आदमी होते हुये जनता से गिराये जाने पर उनको आज यह खशकिस्मती मिली कि वे कांग्रेस के बीस साल के शासन को कुशासन कह सकते हैं। और यह कह सकते हैं कि कांग्रेस पूंजीवादियों की संस्था है।

मैंने वित्त मंत्री जी का भाषण सुना। झारखंडे राय जी पर दुःख होता है कि ये तो कभी कांग्रेसी थे और वित्त मंत्री जी भी कभी कांग्रेसी थे। हमारे जन कांग्रेसी भाई आजतक कांग्रेसी थे। लेकिन वह आदमी अच्छा हो जाता है जो एक रोज पहले तक बुरा था और जो अपने किसी हित के लिये उल्टा हो गया और आप में शामिल हो गया। अगर अच्छे और बुरे का आपका यही पैमाना है तो, मुझे माफ करें, यह आपको मुबारक हो। मैं यह कह देना चाहता हूं कि कांग्रेस वह संस्था है जिसको एक महात्मा ने पाला और पोसा है। कांग्रेस वह संस्था है जिसका नेतृत्व पार्लियामेंटरी पद्धतियों में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया है, जो सच्चा सोशलिस्ट था। उस जवाहरलाल ने जिसके आप गुण गान करते हैं, उसने १८ साल तक इसका नेतृत्व किया है। मैंने वित्त मंत्री जी का भाषण पढ़ा। मेरी आंखें काम नहीं कर रही थीं कि वित्त मंत्री जी ने वह वाक्य पढ़ा या नहीं कि कोई भी सिद्धांतविहीन राजनीतिक दल अगर ज्यादा दिनों तक शासन में रहता है तो एक गड्ढे की भाँति हो जाता है और उसमें कीचड़ पड़ता है। बीस साल का कांग्रेस का शासन शानदार शासन रहा है। उसमें समाजवाद का कार्य हुआ है, जनहित का कार्य हुआ है। मैं अभी आपको बताऊंगा कि क्या क्या हुआ। प्रातः स्मरणीय पंडित गोविन्द वल्लभ पंत, जिनके चरणों में हमने और मुख्य मंत्री ने, सब ने पाठ सीखा है, उन्होंने इस उत्तर प्रदेश का नक्शा बनाया है और २० साल के शासन में सब से ज्यादा हाथ उनका रहा है। कांग्रेस को यह कहना कि वह गड्ढा है, मैं बाअदब श्रीमन् से अर्ज करना चाहता हूं कि कांग्रेस एक बहती हुई गंगा है जिसमें जो गड़बड़ लोग आ जाते हैं वे भी पवित्र हो जाते है। जब उसमें बाढ़ आती है तो पानी इधर-उधर चला जाता है। तो जैसे कम्युनिस्ट पार्टी में झारखंडेराय जी गये, जैसे सोशलिस्ट पार्टी में हमारे भाई गये, बाढ़ के जमाने में इधर उधर गड्ढे भर गये और उन गड्ढों में पड़े हुये लोग गंगा स्नान का मजा ले रहे हैं।

आज क्या कोई कह सकता है कि जमींदारी उन्मूलन के कानून का काम पूंजीपतियों के हित में था ? क्या हरिजन कल्याण के लिये जो कानून बनाये गये और जो काम किये थे वे क्या पूंजीपतियों के हित के लिये काम थे ? क्या यह जो सारी प्लानिंग उत्तर प्रदेश और सारे देश में की गई वह क्या पूंजीपतियों के हित में थी ? उसमें आपका विश्वास है या नहीं ? आज आप लोग एक मदारी के जादू के ऊपर चल रहे हैं। चाहे जनसंघ के मेम्बर हों या किसी भी पार्टी के मेम्बर हों उनको किस कोठरी में वह मदारी बन्द करेगा, हम नहीं जानते हैं। लेकिन इतना समझ लें कि सच्ची बात को छिपाना नहीं चाहिये। हम अपनी गलती मंजूर करते हैं गुप्ता जी ने भी अपनी गलती मंजूर की, लेकिन कांग्रेस की जो अच्छी बातें हैं उनको सुनना चाहिये, समझना चाहिये और देखना चाहिये।

[श्री चतुर्भुज शर्मा]

आज कहा जाता है कि हम पूंजीपतियों के साथी हैं और माननीय झारखंडेराय, उग्रसेन जी, स्वायत्त शासन मंत्री वगैरह राजा महाराजाओं को अपनी बगल में लिये हुये हैं, नबाबजादों और उनके एजेंटों को अपने साथ में लिये हुए हैं, पूंजीपतियों को अपने साथ में लिये हुये हैं और उनके साथ काम करना चाहते हैं। इसमें क्या चीज है ? उन्होंने आपकी प्लेज पर दस्तखत नहीं किये हैं और ये लोग आप से अपना काम करा रहे हैं। इन लोगों के कारनामे आपने देखे हैं। कल एक दृश्य आपने देखा। जिस समय हमारे देश में अंग्रेज राज्य करते थे उनसे लड़ने के लिये जो हमारे राष्ट्र के नेता स्कीम बनाते थे उसमें प्रलोभन के मिल जाने पर ये लोग उनसे मिल जाते थे। कल ऐसे लोगों ने एक नजारा दिखा दिया क्योंकि यह हमेशा ऐसा करते हैं, करेंगे और आप लोगों के साथ भी करेंगे। आप भ्रम में न आयें। हम चाहते हैं कि आपकी सरकार ज्यादा दिन चले, लेकिन अच्छे काम करे।

श्रीमन्, मजदूरों के लिये, उनके हित के लिये, उनके कल्याण के लिये और उनके अधिकारों को बढ़ाने के लिये इन्होंने कोई भी योजना बनाई होती, जो मजदूर कारखानों में काम करते हैं उनके लिये कोई संकेत इस बजट में किया होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया है। किसानों के लिये माननीय विकल जी जो मेरे दोस्त हैं, बड़े विकल रहा रहते थे। मैं उन आदमियों में से हूं कि उनके अनुशासन तोड़ने पर भी मैंने उनकी बुराई नहीं की थी। उनका यह कहना है कि किसानों के ऊपर जो यह कर लगाया जाता है यह ठीक नहीं है। किसानों की पहली मांग थी अलाभकर जोतों पर से लगान माफ किया जाय। आज इसके ऊपर उनको विकलता नहीं हो रही है। आज वे शनैः शनैः के रास्ते पर आ गये हैं। पी० एस० पी०, एस०एस० पी०, कम्युनिस्ट पार्टी ये बहुत आगे बढ़ने वाले हैं और ये कहते थे कि खेती बिना लगान के होगी। हमने मुजफ्फरनगर में जिसमें विकल जी भी थे एक प्रस्ताव पास किया था कि सवा छ एकड़ की अलाभकर जोतों का लगान हम माफ करेंगे। और हमने यह नारा दिया "छोटी खेती बिना लगान"। जब जवाहर लाल जी ने यह देखा कि इस प्लानिंग का फायदा नीचे नहीं गया तो जिन्होंने प्लानिंग चलाया था उनको रिपोर्ट करने के लिये कहा। उन्होंने बताया कि खेतिहर मजदूर को जीरो फायदा हुआ, पांच एकड़ तक किसानों को जीरो फायदा हुआ। ऊपर के और मध्यम के लोगों को कुछ फायदा हुआ। तो उसको बदलना चाहते थे। आप उसको और स्कीमों से फायदा नहीं पहुंचा सकते। उसके पास कच्चे कुएं बनाने की भी शक्ति नहीं है। ऐसे लोगों का अगर लगान माफ कर दिया जाय तो उस छोटे काश्तकार को सीधी मदद हो जाती है। जो रुपया वह लगान में देता है उससे वह अच्छा बीज खरीदेगा। उसके लिए हम कमिटेड हैं और आप भी हैं। लेकिन एक पार्टी है जो कमिटेड नहीं है जिसका बाहुल्य है। वह बड़े लोगों के लिए कमिटेड है। शहर में रहने वालों, जिसमें हम भी शामिल हैं, हम पर भी भूमि-भवन कर पड़ता है लेकिन हम दे सकते थे। लेकिन आपने भूमि-भवन कर तो माफ कर दिया लेकिन खेतिहर मजदूरों और छोटे काश्तकारों के लिये कुछ नहीं किया इसलिये कि बड़े-बड़े पूंजीपतियों के कुछ इशारे हैं। उनको आपने पहले मंजूर किया, लेकिन किसानों को बिलकुल भूल गये जिसपर कहते हैं कि यह किसान मजदूर की सरकार बनी है।

मैं झारखंडे राय जी से अर्ज कर दूं। उनकी और उनकी पार्टी की मैं कद्र करता हूं। उनके नेता श्री जेड० ए० अहमद मेरे साथी हैं। मैं मानता हूं कि राष्ट्र प्रेमी हैं लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो आपको राष्ट्र प्रेमी नहीं मानते। लेकिन जो आपका गठबंधन हुआ, सारंगी सतरंगी सरकार बनी, यह कह लीजिये कि यह सरकार सतभतरी है, जिसके सात भतार हों, वह किस किस को मनायेगी ? जो ज्यादा ताकतवर है, जिसके हाथ में जूता है, उसी को वह नमस्कार करेगी। आपने कहा कि आप मिल गये। बड़ा अच्छा होता कि आप मिल जाते। एक पांच साल का प्रोग्राम बना लेते। लेकिन लोहिया साहब कहते हैं कि छ महीने हम देखेंगे और छ महीने से पहले अगर कांग्रेस वाले खेतिहर मजदूरों और किसानों के लिये प्रस्ताव लाते हैं तो हम उनके साथ वोट देंगे। तो कैसे आपकी सरकार चलेगी ? मैं आप से फिर माफी चाहता हूं। मोटिव नहीं लगाता, कुछ लोग आप में से ऐसे हैं, ऊपर से मेल मालूम होता है, एक हाथ

मेल का बढाये हुये हैं और दूसरे हाथ में छुरा लिये हुए हैं। फिर कहते हैं कि हम मिल गये। फिर पता नहीं कि लाल क्रांति आयेगी या काली पीली क्रांति आयेगी। कांग्रेस वाले जो जन संसदीय पद्धतियों में विश्वास करते हैं उनको कुछ कह लो। आपके प्रत्यक्ष सामने है। आपने देखा सदन में लोग बैठे हैं, निर्दलीय सदस्य, कितना उपद्रव उनकी तरफ से किया गया। कल भी किस तरह का नजारा उपस्थित किया गया। निर्दलीय हो कर कैंडीडेट बन गये। फासिस्टवादी प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं। यह आप जान लें कांग्रेस के जो लोग कांग्रेस छोड़कर चले आयें वे आप लोगों के लिये बड़ा आदर्श उपस्थित करते हैं। उनके लिये भी हम कांग्रेस वाले कुछ कह सकते थे, काले झंडे दिखा सकते थे, अनशन कर सकते थे और उनके घरों पर धरना भी दे सकते थे, हमारे पास भी आदमी हैं कमी नहीं है, लेकिन हम आपकी तरह नहीं करते हैं, क्योंकि हम रोना नहीं जानते हैं और प्रजातांत्रिक तरीकों में आस्था और विश्वास रखते हैं।

इस सरकार में जो मुख्य मंत्री हैं चरण सिंह जी वह सारे मंत्रियों में सबसे ज्यादा वोटों से जीतकर आये हैं। वह किसके आदमी थे, वह कांग्रेस के ही आदमी थे। तो उससे क्या जाहिर होता है ? इससे यही स्पष्ट होता है कि जनता की वरडिक्ट कांग्रेस के साथ है आपकी सतरंगी पार्टियों की सरकार के साथ नहीं है। आज सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी है, जिसे जनता ने चुनकर भेजा है। जनता चाहती है कि हमारे साथ जिनका प्रोग्राम मिलता है वह हमारा साथ दें, कांग्रेस का साथ दें, क्योंकि जनता ने समाजवाद के नाम से इनको जिताया है। समाजवाद के नाम से जिन्हें वोट मिले हैं वे सब हमारे साथ आयें और समाजवाद का सपना साकार करने में सहायक बनें। उनका बहुमत सदन में है और यदि कोई गवर्नमेंट बने तो ऐसे लोगों की ही बने, ऐसे लोगों की नहीं जो अल्पमत में हैं और जो समाजवाद विरोधी हैं तथा फासिस्टवादी हैं।

हमारे झारखंडे राय जी समाजवाद की बड़ी बात करते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि आप प्रगतिशीलता और समाजवाद की बात नहीं कर रहे हैं, आप उसकी सिर्फ कल्पना कर रहे हैं। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि आप देखें कांग्रेस सरकार ने यह आर्डर निकाला था कि व्यापारी ढाई सौ क्वींटल से ज्यादा अनाज नहीं रख सकेगा, किन्तु आपने क्यों उसको बढ़ा कर एक हजार क्वींटल कर दिया। यह आपने चोरबाजारी, जखीरेबाजी को बढ़ाने के लिये और व्यापारियों का बेजा फायदा कराने के लिये किया या जनता के हित के लिये किया। इसे आप देखें, इसे जनता भी अच्छी तरह से देख रही है। कांग्रेस प्रशासन में जिन चोरबाजारी और अत्याचारी व्यापारियों को पकड़ा गया और बन्द किया गया, उनको जब आपकी गवर्नमेंट आई तो उनको बाइज्जत छोड़ दिया गया, छोड़ा नहीं आप तो उनको घर-घर जाकर छोड़ आये। वह आदमी जिनपर १८ दिन की गुप्ता जी की गवर्नमेंट में वारंट निकला, जो सबसे बड़ा गल्ला का स्टाकिस्ट था, चोर था। उसके बारे में आपके मंत्रियों ने राय दी कि उसे बाइज्जत छोड़ दिया जाये और आप ने छोड़ दिया, अब उस पर मुकदमा चलाया जा रहा है पता नहीं आगे क्या होगा। आप तो क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन का दावा करते थे, लेकिन वह तो कल्पना मात्र बनकर रह गया है। गांधी जी ने सिखाया है कि पवित्र साधनों से ही पवित्र ध्येय प्राप्त हो सकता है, अपवित्र साधनों से धोखाधड़ी से और दूसरी चीजों से आप प्रशासन में स्वच्छता नहीं ला सकते हैं।

श्री अध्यक्ष––

श्री शर्मा जी, अब आपका समय समाप्त हो गया।

श्री चतुर्भुज शर्मा––

अभी थोड़ा समय और मुझे दे दें ?

श्री अध्यक्ष––

अच्छा एक दो मिनट और बोल लें।

श्री चतुर्भुज शर्मा—

मुख्य मंत्री जी चाहते हैं, उनका इरादा है, उन्होंने कहा था, कि संयुक्त विधायक दल की सरकार में कोई उप मुख्य मंत्री नहीं होगा, अखबारों में भी निकल गया, लेकिन उनकी घोषणा का क्या हुआ ? आज उप मुख्य मंत्री जी सामने बैठे हैं । उन्होंने यह भी कहा था कि विधान परिषद् का कोई सदस्य मंत्री नहीं बनाया जायेगा, लेकिन विधान परिषद् के सदस्य को ही नहीं ऐसे व्यक्ति को भी मंत्री बना दिया गया है जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है । उप मुख्य मंत्री जी ने कहा कि हम किसी भी संस्था में नामिनेशन नहीं करेंगे, लेकिन उनके सहयोगी ने उसे ताक पर रख दिया और एक पार्टी विशेष के लोगों को सहकारी संस्थाओं में योजना बद्ध रूप से भरा जा रहा है । उनका नामिनेशन किया जा रहा है । यहां तक कि मुख्य मंत्री जी की सलाहों को ठोकर मारकर एक पार्टी के आदमियों को आपने कोआपरेटिव में नामिनेट कर दिया । मैं जब कांग्रेस गवर्नमेंट का सहकारिता मंत्री था तब मैंने एक आर्डर दिया था कि कोआपरेटिव में जो गड़बड़ियां होती हैं उसके लिये नामिनेशंस ऐसे व्यक्तियों का होना चाहिये जो धन की रक्षा कर सकें और इसलिये रिजर्व बैंक आफ इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव उसमें रहें यह हमने रखा था और जिला बोर्ड में सहकारिता के आदमी जाते हैं इसलिये जिला बोर्ड का प्रेसीडेंट उसमें हो । उन आर्डर्स को तो आप बुरा कहें, लेकिन एक पार्टी के आदमियों का आप पोषण करें तो उसे क्या कहा जायगा ? बेचारे मुख्य मंत्री जी क्या करें, वे भी फंसे हुये हैं । मैं जानता हूं कि उनका इरादा होगा कि सही बात हो, लेकिन वह नहीं हो पाता है । मैं इतना कह कर के खत्म करता हूं कि मेरे मित्र जरा जोश में न आयें, अभी सरकार में आये बहुत दिन नहीं हुये हैं, वे सरकार को चलावें, चलाकर कुछ दिन देख लें, तजुर्बा कर लें और तब मालूम हो जायगा कि सरकार कैसे चलाई जाती हैं और किन पद्धतियों पर चल कर जनहित किया जा सकता है ।

श्री भैरवदत्त धूलिया (जिला गढ़वाल)—

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं कल से बजट पर भाषणों को सुन रहा हूं । मैं समझता था कि बजट पर जो भाषण होंगे उनमें बजट के भाषणों को लक्ष्य करके कहा जायगा । लेकिन जितने भी भाषण यहां हो रहे हैं उनमें बजट को लक्ष्य में नहीं रखा गया है बल्कि आक्षेपों और प्रत्याक्षेपों की बातें की जा रही हैं । होना तो यह चाहिये था कि उस दृष्टि से देखा जाता । खुशी है कि १९ वर्ष ७ महीना १७ दिन के कांग्रेस का शासन खत्म हुआ और दूसरे रूप में परिणत होकर शासन आया जिसे २ महीना १४ दिन आज होते हैं ।

(इस समय १ बजकर ८ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री हरीशकुमार गंगवार, पीठासीन हुए।)

इतने समय में हमने देखा कि दीनानाथ आज दीनबन्धु के रूप में बैठे हैं और जो दीनबन्धु थे वह दीनानाथ बन गये हैं । जो बजट उपस्थित किया गया है उस पर हमारे बड़े बड़े लोग बोले, गुप्ता जी ने भी कल कहा मैंने बड़े ध्यानपूर्वक सुना । गुप्ता जी ने अपने को बजट पर सीमित रखा लेकिन आज चतुर्भुज शर्मा जी के भाषण को सुनकर मायूसी हुई और मेरा जो बजट पर बोलने का भाव था उसमें परिवर्तन आ गया । उन्होंने बजट पर कुछ न कुछ कहकर पुरानी कांग्रेस की महत्ता पर प्रकाश डाला । उसको कौन अस्वीकार कर सकता है ? जिस संस्था ने भारत को स्वतंत्रता प्रदान करायी, जिसने विदेशी राज्य से मुक्त कराया उसे कौन नहीं मानता ? उन्होंने कांग्रेस की उपमा गंगा जी से दी । मुझे अफसोस है कि उधर बैठने वाले बन्धुओं ने उस गंगा को पतनाला बना दिया है । जो कांग्रेस हमारी माता थी, आज उसको वैश्या के रूप में बनाकर रुपया कमाने के लिये रख दिया है। आज देश के अन्दर कांग्रेस के लिये लोगों के मन में एक तिल भर भी श्रद्धा नहीं है । (व्यवधान) मैं प्रार्थना करूंगा इधर और उधर दोनों ओर के माननीय सदस्यों से कि ताली न बजावें । मेरी बातें सुनें । कांग्रेस के अन्दर जो कुछ भी समाजवाद की बात करते हैं वे सब १९ वर्ष ७ मास १७ दिन तक के तमाम बजट में भरे हुये हैं । कांग्रेस समाजवाद का कराची का सबसे पहला रेजोलूशन है।

अवादी और भुवनेश्वर के भी रिजोल्यूशन उस संबंध में हैं लेकिन सबसे लेटेस्ट रेजोल्यूशन समाजवाद के संबंध में मुजफ्फरनगर का है लेकिन आपने देश को समाजवाद में लाकर रखा है। आज देश के अन्दर हालत इतनी खराब है कि वह एक समस्या है कि किस प्रकार से उसको ठीक किया जाय। आज देश की ऐसी स्थिति है कि जैसे कहीं कोई नंगा बच्चा जाड़े से ठिठुरता हुआ पड़ा हो और सब समाजवादी कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट भी वहां पर खड़े हों और वह उस पर सोच रहे हों कि किस प्रकार के सिद्धांत से इसको ठीक करें। आज प्रश्न यह है कि इस बच्चे के लिये सब से पहले कपड़े का इन्तजाम होना चाहिये जिससे वह तन ढक सके। फिर उसकी दशा संकीर्ण हो रही है, उसके शारीरिक यंत्र ठीक नहीं हैं तो उसके लिये भोजन की व्यवस्था होनी चाहिये। इसमें किसी को किसी आपत्ति का प्रश्न नहीं है। यह बातें तो कम से कम प्रोग्राम की हैं और इन बातों पर हम लोगों को चलना है।

आज हमारे देश में ३७ अरब रुपये का अनाज बाहर से खरीद कर आता है। हमने आज तक अपनी प्लानिंग के विषय में नहीं सोचा है कि वह कितनी गलत है और कितने डिफेक्ट उसके अन्दर हैं। आज सारी परेशानी हमारी गलत प्लानिंग की वजह से हो रही है। हमारे देश में सरकार ने प्लानिंग कांडला बन्दरगाह से शुरू करके गरीब आदमी की झोपड़ी तक जाने की प्लानिंग की, यह गलत प्लानिंग थी। होना यह चाहिये था कि झोपड़ी से पहले प्लानिंग करके चलते जिससे गरीब की पहले प्लानिंग होती। वह एक सही प्लानिंग हो सकती थी। उस गलत प्लानिंग का नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि हमको अमेरिका से गेहूं खरीदना पड़ा और वह हमारा क्रम अब भी जारी है। लोगों ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया और गन्ना और दूसरी चीजें बोना शुरू किया और उससे धन पैदा किया। उधर पैदावार बढ़ाने के लिये अपनी गति धीमी कर दी। यह हमारी गलत प्लानिंग का ही परिणाम है कि जो हमको पूर्वी जिलों में देखने को मिल रहा है। यह गलत प्लानिंग के ही कारण है कि फ्री किचन और फ्री मैस चल रहे हैं। यह बातें ठीक नहीं हैं वहां लोगों को काम करना चाहिये। उनको खाना दिया जाय या मजदूरी दी जाय, लेकिन उनको काम करना चाहिये। इस पर विचार करने की आवश्यकता है। यह हमारी प्लानिंग के कारण ही है।

इधर गंगा और जमुना में सब जगह पानी रोककर, बांध कर पानी लेने का प्रयास किया गया है। यहां पर कमलापति जी आज बैठे हुये हैं। वे जानते हैं कि एक दिन मैं असी घाट और रामनगर के बीच गंगा में खड़े खड़े उस पार निकल गया। मुझे तैरने की जरूरत नहीं पड़ी। इतना कम पानी था कि मैं वैसे ही पार हो गया और फिर हमारी प्लानिंग गलत हुई कि जो ट्यूबवैल लगाये गये उनका पानी अपर स्ट्रैटा से लिया गया। इसका परिणाम हुआ कि जितने कुयें थे वे सब सूख गये। इसलिये प्लानिंग इस विचार से होनी चाहिये कि कुओं का पानी सूख न सके। जितने ट्यूबवैल बनाये जायं वह इस तरह से बनायें जायं कि लोअर स्ट्रैटा से पानी आ सके और ऊपर की सतह पर कोई असर न पड़े। जितने तालाब हों वहां पर बगीचे लगाना चाहिए। यह सूखा गलत प्लानिंग की वजह से हो रहा है।

दूसरी बात यह कही जाती है कि जिस दिन यहां पर सरकार उलटी उस दिन जो कौल करार किये गये थे उनका समावेश इस बजट के अन्दर नहीं किया गया है। यह ठीक है कि इसमें इतने प्वाइंट्स हैं और बातें हैं जिनके लिये लगभग १॥ अरब रुपया लिया जाना चाहिये था। इसमें एक कार्यक्रम बनाया गया है। हम को उसे तरतीबवार इसमें लाना है। जैसे जाड़े से ठिठुरते हुए बच्चे की सबसे पहली जरूरत कपड़ा होती है, तो उस समय वह कपड़ा टाटा का है, बिरला का है या रूस का है अथवा अमरीका का है, यह नहीं देखा जाता। इसी तरह से बजट में जो सबसे पहली जरूरत की चीज है उसे ही पूरा करने का प्रयत्न किया गया है। मैं चाहता हूं कि इस प्रदेश में ५ वर्ष तक यह संयुक्त दल की सरकार चल जाय तभी यहां का काम सुचारु रूप से चल सकता है। यदि इन पांच सालों में यह सरकार भ्रष्टाचार का निराकरण कर दे और अन्न के संबंध में प्रदेश को आत्मनिर्भर कर दे तो इसके लिये यह एक बड़ी बात होगी।

[श्री भैरवदत्त धूलिया]

इसी दृष्टिकोण से इस बजट में आधे से अधिक धन बिजली, सिंचाई तथा अधिक अन्न उत्पादन के लिये रखा गया है। मैं आशा करता हूं कि यह काम जल्दी ही पूरा होगा।

एम्ब्रुड्समैन पद्धति को यहां स्थापित करने का प्रयत्न किया गया है और शुरू से ही यह पद्धति यहां अपनायी जानी चाहिये। अगर वह शुरू से होती तो किसी को कुछ कहने की गुंजायश नहीं थी। दूसरी बात है कि हम अधिक अन्न का उत्पादन करेंगे। जो दूसरी बातें हैं वे शनैः शनैः होंगी और समाजवाद इसमें नहीं आया इसके लिये हमें अधिक सोचना नहीं चाहिये। मैं कहता हूं कि दुनिया में जितनी चीजें हैं अगर वे उसी रूप में होतीं जैसी कि वे कागज पर हैं तो दुनिया का रूप ही दूसरा होता। हिन्दुओं का एक सिद्धान्त है "एकमेवा द्वितियम् ब्रह्म' एक ही ब्रह्म सब का है। और क्रिश्चियन लोगों का सिद्धान्त है कि अगर कोई एक गाल पर चपत दे तो दूसरा गाल भी उसके सामने कर दो। लेकिन आप देखें कि उनके यहां विश्व को नष्ट करने के लिय सारी एटामिक शक्ति इस्तेमाल की जा रही है। हमारा समाजवाद देश में कागज का समाजवाद है। यह कागज के अन्दर का समाजवाद चलेगा नहीं। कल परसों मैंने अखबार में पढ़ा है कि समाजवादी प्रवृत्ति के नेहरू जी के साथी १५ सौ रुपया माहवार किराये का देकर रह रहे हैं। समाजवाद की डेफीनीशन यह नहीं है कि बाप मंत्री बना हुआ है और बेटा डिस्टिलरी की दूकान खोल कर कमाई कर रहा है। यहां के पिछले मंत्री लाखों और करोड़ों रुपयों का संचय कर के बैठे हैं। समाजवाद तो यह है कि यावद भ्रियते जठरं, तावत्सेत्वं हि दोहेमाम्। जितना पेट में जाता है वही ग्रहण करना चाहिये। उससे अधिक जो रखता है वह चोर है। आपको इसी समाजवाद को मानना चाहिये। यह कागज में नहीं आया, लेकिन इस सरकार के प्रयोग में यही समाजवाद आ रहा है।

विरोधी पक्ष की तरफ से यह लांछन इस ओर के लोगों पर लगाया जाता है कि यह सब लोग अधकचरे हैं और इन को न तो कोई शऊर है और न कोई तमीज है। एक चरण सिंह हैं जो इनकी गाड़ी को खींच रहे हैं। अगर वह हमारे साथ होते तो ये अवश्य ही उलट पुलट हो जाते, ऐसी बात कह दिया करते हैं। मैं आप से उम्मीद करता था और आज भी करता हूं। चाहे सहाय जी हों, गौतम जी, बडुगु जी इनसे मैं कहता हूं कि क्या वास्तव में डेमाक्रेसी का यही स्वरूप है जो हिन्दुस्तान में चल रहा है? आज हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, लेकिन सबसे बड़ा पतन हुआ है उसका। यहां डेमोक्रेसी कम्युनलिज्म में परिवर्तित हो गयी है और समाजवाद घूसखोरी में बदल गया है। मैं कहता हूं कि आप लोगों की एक शैडो कैबिनेट होनी चाहिए। आज इधर बाप बैठे होते हैं तो उधर बेटे हैं और कल हम ही बेटे के रूप में हो सकते हैं और आप बाप हो सकते हैं। अगर यह सरकार भी गिरती है, इसका डाउनफाल होता है तो कहां है आप का सारा मंत्रिमंडल और कहां है आपकी योजना? मैं यहां देखता हूं कि विवाद का स्तर यहां ऐसा बन गया है जैसा साग और सब्जी यहां बिकती है वहां वादविवाद होता है। गुप्ता जी ने तो कल ठीक कहा था, लेकिन आज चतुर्भुज शर्मा जी की स्पीच सुन कर मुझे दुख हुआ। आप हमारा पथ प्रदर्शन करें, यह हम चाहते हैं आप अपने प्रपोजल को रखें अगर यह सरकार नहीं सुनती है तो अखबार में प्रकाशित करें, यह समय का तकाजा है। ये २७-२८ की मजारिटी में है, आप भी २७-२८ की मजारिटी बताते हैं। आज ग्रेट ब्रिटेन के अलावा कोई इतनी बड़ी और सफल डिमाक्रेसी नहीं है। वहां विलसन ने १ से ४ के बहुमत में ४ साल तक शासन चलाया और उसने स्वयं ही अपनी सरकार को डिजाल्व किया और आज फिर आ गया। यह प्रजातंत्र का नमूना है। यहां इतना बहुमत होते हुये भी क्या क्या हुआ? कल जो कुछ हुआ वह हिन्दुस्तान के और प्रजातंत्र के इतिहास में एक कलंक के रूप में लिखा जायगा कि यह आदमी थे या कुछ और चीज थे।

मुझे इस संबंध में कथानक बात याद आती है। जब गांधी जी का राज्य हो गया तो नारद जी घूमते घूमते एक अपने शिष्य की ओर जा निकले। वह एक क्लार्क था और सौ रूपए

उसे मिलते थे। वह बड़ा परेशान था कि कहां गया नारद जो कहता था घूस मत खाना, बुरे कर्म मत करना, मैं तो मर रहा हूं। नारद आया और उसके पास गया और पूछा कि तेरी क्या पीड़ा है। उसने कहा कि आजकल मैं तुम्हारी आज्ञा से ईमानदारी से अपना गुजारा कर रहा हूं। मेरे ४ बेटे और ४ बेटियां हैं। सौ रूपया मिलता है। आठों लड़के लड़की कालेज में पढ़ते हैं और प्रत्येक की १०-१० रुपया फीस जाती है और १० रूपया माहवार बेटियों के पाउडर के लिये चला जाता है और १० रुपया बेटों के तेल के लिये चला जाता है, तो मैं जहर खाऊं या क्या करूं? नारद ने कहा कि गांधी जी के राज्य में ऐसा अंधेर। वह ब्रह्मा जी के पास गया उससे कहा कि ब्रह्मा जी संसार में तो त्राहि त्राहि मची हुई है, कोई तरकीब बताओ जिससे उससे निस्तार मिले। ब्रह्मा ने कहा कि अरे नारद, तू तो सन्यासी होकर भी बेवकूफ है—

सुख दुखे समे कृत्वा, पुण्यं पापं तथैव च, कर्मत्यं कुरु कर्मत्यं।
स्व कर्त्तव्य कुरुस्व स्वं कर्त्तव्य च्यति पिप्लवम्। कर्मयं च मि पिप्लवम्

सुख दुख को बराबर करो, पुण्य पाप को बराबर करो और कर्त्तव्य का पालन करते रहो। कर्त्तव्य न करना ही विप्लव का कारण है। उसने कहा कि जिस राज्य में मजदूर अपनी ईमानदारी से काम करता हो, जिस राज्य में सरकार मजदूर की बेहतरी के लिये उसका पोषण करती हो वहां इसी प्रकार के कष्ट होते हैं। नारद, तुम कहते थे वहां गांधी जी का राम राज्य है। फिर भी नारद ने पूछा कुछ उपाय बताओ; वह संस्कृत श्लोक में इस प्रकार है—

दुखी नारदो पृष्टवान् पद्मयोनिं
धारित्री तले दुखिता दीन भला
चतुर्भि-मुखै रिसावोचन् स ब्रह्मा
करप्शन करप्शन-करप्शन।

ब्रह्मा ने कहा चारों मुखों से कि ऐसे राज्य में तो करप्शन ही जीने का उपाय है। नारद ने पूछा कि धी, सुरा और सुन्दरी आदि तीन प्रकार का करप्शन होता है, मैं उनके बीच में रहूंगा। मैं ब्रह्मचारी हूं, सन्यासी हूं, उनके बीच कैसा करप्शन मुझे करना होगा?

पुनः पृच्छवान् चाह तो जल्प कोऽसौ
कथ करप्शन करप्शन महयम्
चतुर्भि मुखै रिसावोचन स ब्रह्मा
तिकड़म-सिफारिश-तिकड़म-सिफारिश

अर्थात् करप्शन की पहली सीढ़ी सिफारिश और तिकड़म है।

मेरा कहने का मतलब यह है कि जिस देश के मजदूर अपनी शक्ति भर काम करेंगे उनका उचित संरक्षण होगा तभी देश का हित होगा, तभी करप्शन दूर होगा। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप लोग इस तरह से एक दूसरे पर लान्छन न लगायें। माननीय शर्मा जी की स्पीच जब अखबारों में छपेगी और लोग पढ़ेंगे तो क्या कहेंगे? गुप्ता जी ने तो ठीक कहा कि बजट में यह-यह कमियां हैं। उनकी ओर उन्होंने ध्यान दिलाया। आज आवश्यकता इस बात की है कि सबसे पहले करप्शन को दूर किया जाय, फिर अन्न के मामले में आत्मनिर्भर बना जाय। (लाल बत्ती होने पर) लाल बत्ती हो चुकी है, अतः संक्षेप में मैं यह कहना चाहता हूं कि बजट में ये दोनों बातें हैं। एम्बुडसमैन प्रणाली स्थापित कर करप्शन दूर होगा और आधा से अधिक बजट अन्नोत्पादन पर व्यय होगा।

*श्रीमती इन्द्रमोहिनी (जिला मुरादाबाद)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने माननीय खाद्य मंत्री जी के भाषण को बड़े गौर से सुना और उनको बधाई देती हूं कि उन्होंने यह कुबूल किया है कि उनके बजट में सोशलिज्म नाम की कोई चीज नहीं है। इसके लिये मैं उनका हार्दिक धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने कम से कम

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्रीमती इन्द्रमोहिनी]

इस चीज को कबूल तो किया। उन्होंने अपने भाषण में कांग्रेस पार्टी को क्रीटीसाइज करते हुये बताया कि वह पूंजीपतियों को सपोर्ट करती है। यह तो सर सर गलत है। अगर माननीय खाद्य मंत्री जी ने कांग्रेस पार्टी के रिजोलूशन को पढ़ा होता तो वे ऐसी बातें नहीं कहते। अगर हमारे साथियों के पास उस रिजोलूशन की कोई कापी हो तो मैं चाहूंगी कि वे उसे माननीय खाद्य मंत्री जी के पास भेज दें। कांग्रेस पार्टी का तो जो सोशलिज्म की तरफ एप्रोच है उसी के अनुसार वह काम करती है। हमने रोडवेज को नेशनलाइज किया, उद्योगों को किया, और भी चीजों को करने का हमारा इरादा है। फिर भी यह कहना कि कांग्रेस पार्टी पूंजीपतियों को सपोर्ट करती है बिलकुल गलत है।

मान्यवर, कल यहां सदन में जो सीन हुआ उससे क्या जाहिर होता है? किस तरह से महाराजा साहब उधर के लोगों के साथ आये, किस तरह से उन्होंने अपना प्रपोजल वापस लिया, उससे क्या जाहिर होता है? मेरी समझ में नहीं आता कि यह राजा महाराजा लोग कब से सोशलिज्म का समर्थन करने लग गये। आपके यहां तो कोलीशन गवर्नमेंट बनी है जिसमें स्वतंत्र पार्टी के लोग है, जन संघ के लोग हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं, सोशलिस्टिक ग्रुप के लोग हैं। अतः मैं आपके बजट का विरोध करती हूं और आशा करती हूं कि आप इस में संशोधन करेंगे।

*श्री अश्वनीकुमार चतुर्वेदी 'राकेश' (जिला मिर्जापुर)---

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अभी इसके पहिले बहुत काफी हमारे वरिष्ठ सज्जनों ने इस बजट के सिलसिले में अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त कीं और मैं भी इस संतुलित बजट के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जब हमारे तमाम विपक्षी बन्धु यहां पर आकर तरह-तरह की बातें करते है तो उन्हें भी निश्चित रूप से उन बातों को कहना चाहिये था जिन परिस्थितियों में पहिली अप्रैल को वर्तमान सरकार और कांग्रेस सरकार का पतन हुआ था। अभी इसके पहिले श्री शर्मा जी ने कहा कि इस संयुक्त विधायक दल ने अपने विरोधी लोगों को कैटल कटघरे में खड़ा कर दिया और उन्होंने यह भी कहा कि इनके तरह-तरह के सिद्धान्त हैं तरह-तरह की बातें हैं। कटघरे की बात के सिलसिले में मुझे यह कहना है कि शर्मा जी के सम्बन्ध में भी कुछ बातें यदि जानकारी में आजाती तो शायद वे भी कटघरे में खड़े होकर ही कुछ बातें कह पाते। हो सकता है कि इस सरकार के माध्यम से अब तक बहुत से लोगों को कटघरे में नहीं खड़ा किया जा सका, अभी इस सरकार के हाथों वह काम होने का सुअवसर नहीं आया है। यह हो सकता है कि जिस प्रगति से कार्यक्रम बनना चाहिये वह नहीं बन सका, लेकिन बावजूद इसके इस बीच में जो कुछ भी कार्य हो सका है अगर उस रोशनी में वे इस सरकार को देखने की कोशिश करें और इसके कार्यों पर दृष्टिनिक्षेप करें तो स्वयं ही स्पष्ट हो जाता है वर्तमान सरकार ने क्या किया है। इस सरकार के आने के पहिले की स्थिति पर अभी अगर हम देखते हैं, चाहे वे किसान लोग हों चाहे वे मजदूर रहे हों, उनमें चारों ओर रोष व्याप्त था, कहीं भी संतोष और शान्ति नहीं थी। जैसा कि हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने कहा, कोरे कागजों पर कागजी घोड़े दौड़ाते हुए हमें समाजवाद की बात नहीं करनी चाहिये, उसे कार्य रूप में दिखलाना चाहिये। परन्तु जब से यह सरकार बनी है इसने सभी बातों को आदर्श-गगन से उतारकर यथार्थ की धरती पर उतारने की कोशिश की है। बीस सालों में आपने जो योजनाओं का विस्तार किया लेकिन उनका कार्यान्वयन कुछ न हो सका, उसको भी तो आप देखने की कोशिश करिये। बीस साल के दौरान्ने में आपने जो जो प्रयास किये और उसको जनता जनार्दन के बीच में पहुंचाया जब जब आपने कोई कदम बढ़ाने की कोशिश की तब तब कैसा कैसा गतिरोध उनमें उत्पन्न हुआ है। जैसा कि गुप्ता जी ने विश्लेषण किया, समाजवाद का, वे तो पूंजीपतियों के सदैव समर्थक रहे हैं और उनको उन्हीं की ओर से थैलियां मिलती हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बड़े-बड़े अरबपतियों के साथ बैठने की बात होती है और उनके चरण चूमने की बात होती है। यहां पर गुप्ता जी तरह-तरह की आलोचनायें करते रहे। अगर उन्होंने वर्तमान सरकार की जो पद्धति रही उस पर भी विचार कर लिया होता तो ठीक होता।

हमारी वर्तमान सरकार कार्यक्रमों को लागू नहीं कर सकी, इसको हम स्वीकार कर लेते हैं, कालाबाजार में जैसी घटनायें हुईं हम यह भी स्वीकार कर लेते हैं कि हमने शक्तियों का उपयोग किया, आज भी मजदूरों को सन्तोष नहीं है हम यह भी महसूस कर लेते हैं कि शिक्षा नीति में परिवर्तन नहीं हुआ, राज्य कर्मचारियों के लिये जो भी काला कानून है, वह भी है इस समय, हम उसको भी महसूस कर लेते हैं, उसके लिये हमें खेद है। यह भी महसूस कर लेते कि हमारा १६ सूत्री कार्यक्रम चलने वाला था वह भी सारा का सारा लागू नहीं हो सका। लेकिन आज की परिस्थिति में समय को देखते हुये हमें आंकना चाहिये कि यह जनता जनार्दन का बजट है या नहीं। माननीय वित्त मंत्री ने जो बातें अपने बजट भाषण में कहीं हैं और जो चीजें बजट में रखी हैं, हो सकता है कि आप बहुत सी चीजों को देख कर उन्हें मान्यता न दें, हो सकता है कि जो टैक्स उन्होंने नहीं लगाया है तो उसको आप मान्यता न दें, हो सकता है कि भ्रष्टाचार दूर करने के खयाल से जो उन्होंने आनरेरी मैजिस्ट्रेट के पदों को समाप्त कर दिया है उसे आप मान्यता न दें हो सकता है कि किसी मंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार सम्बन्धी जो जांच होने वाली है उसे आप मान्यता न दें, लेकिन साथ ही इस बात को भी अपने सामने आपको अवश्य रखना चाहिए कि जिस माहौल में यह बजट आया है, क्या उससे लोगों के मन में कुछ परिवर्तन नहीं आया है। इस बात को तो आप भी मानेंगे ही कि कम से कम इतना तो लोग महसूस करते ही हैं कि निश्चितरूप से कुछ परिवर्तन हुआ है। आप जब हिन्दुस्तान में प्रजातंत्र की पुकार कर रहे थे तब एक लम्बे अर्से तक सिद्धान्तहीन लोगों का दल कांग्रेस के बाद जन को रखता था जबकि जन कांग्रेस ने कांग्रेस से पहले जन को रखा है...

श्री अधिष्ठाता—

माननीय राकेश जी, आपका भाषण इतना प्रभावी है कि बहुत से लोगों को दिक्कत हो रही है।

श्री अश्वनीकुमार चतुर्वेदी 'राकेश'—

मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रजातंत्र की महान पुकार को सुन कर संयुक्त विधायक दल की सरकार ने अपना जो भी कार्यक्रम निश्चित किया है बजट के अन्तर्गत, निश्चित रूप से समय की सीमा के अन्दर उसे पूरा किया जायगा। मैं यह नहीं कहता कि ढाई महीने के अन्दर इस सरकार ने जो कुछ किया है सब का सब अच्छा ही है। मैं तो इस बात को मानता हूं कि जो कुछ भी वह करना चाहती है उसका केवल एक अंकुरमात्र है...

श्री अधिष्ठाता–

माननीय राकेश जी, आपकी वजह से रिपोर्टर्स कठिनाई महसूस करते हैं, इसलिये कृपया आप धीरे-धीरे बोलें।

श्री अश्वनीकुमार चतुर्वेदी 'राकेश'—

मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय गुप्ता जी ने सरकारी कर्मचारियों को उकसाने की बात सामने रखी, लेकिन जब जब ऐसी बातें आयीं हमने उनका समर्थन किया और हम आगे बढ़ते रहे, लेकिन माननीय गुप्ता जी ने उन कर्मचारियों को आगे बढ़ाने की हरकत और हिमाकत की फिर भी मुट्ठी भर लोग भी उनके साथ नहीं आये। हम तो उनके दर्द को सही समझते हैं और अपनी ईमानदारी से चरित्र को सामने रखते हुये आगे बढ़ते हैं। हम यह नहीं कहते कि उन कार्यक्रमों को हम जल्दी पूरा कर ही लेंगे, लेकिन यदि जल्दी पूरा नहीं कर सके तो उनको पूरा करने की दिशा में प्रगति अवश्य करेंगे। ऐसी परिस्थिति में संयुक्त विधायक दल की सरकार बनी है और आप लोग जो विरोधी पक्ष के हैं, रचनात्मक कार्यक्रम के लिये कुछ रचनात्मक सुझाव देने की

[श्री अश्वनीकुमार चतुर्वेदी 'राकेश']

बात करनी चाहिये, लेकिन अक्सर आप लोग आदर्श की बात करते हैं, प्रजातंत्र की बातें करते हैं और समाजवाद की बातें करते हैं। प्रजातंत्र के नाम पर आपने तमाम काले कानून बनाये जिससे सारे प्रदेश में हाहाकार मच गया जबकि नीचे के लोगों को ऊपर और ऊपर के लोगों को नीचे गिराना चाहिये था। आपने समाजवाद के नाम पर केवल बड़े-बड़े सेठों और पूंजीपतियों को बढ़ावा दिया, उनके खजाने को बढ़ाया तथा बड़े-बड़े पूंजीपतियों के साथ समझौता कर डाला जिससे प्रदेश की आय प्रति व्यक्ति पहले से काफी गिर गयी। भ्रष्टाचार खत्म करने के नाम पर आपने कुनबापरस्ती को पनपाया। चाहे भूतपूर्व मंत्री हों, चाहे वर्तमान मंत्री हों, भ्रष्टाचार की जांच करने के लिये जब निष्पक्ष आयोग की बात आवे तो सारे मंत्रियों का अंकन एक तरह से करना चाहिये और अगर उनके पीछे कोई गड़बड़ी हो तो उसे दूर भी कर देना चाहिये। लोगों के दुख को देख कर आपको बहुत दर्द हो रहा है, यह बात सही है और निश्चित रूप से हम भी उस दर्द को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। २० साल के कांग्रेस के कुकर्मों का भुगतान हम आज भी कर रहे हैं यह सही है कि हम अपनी नीतियों को पूरा करने में कुछ समय अवश्य लेंगे। आज तक के काफी सारे के सारे अवशेष कांग्रेस सरकार के बाकी हैं, वे इतने दृढ़ कर गये हैं कि उनको ठीक करने में प्रयत्न और समय की आवश्यकता है। संयुक्त विधायक दल की सरकार भरसक प्रयत्न करेगी और कर रही है कि जनता जनार्दन को जल्दी राहत पहुंचाई जाय। कुछ कार्य इस सरकार ने इस दिशा में किये भी हैं, जैसा कि सबको मालुम है।

भुखमरी का जिक्र यहां आया। निश्चय ही आप यह जानना चाहेंगे कि मिर्जापुर में भुखमरी की हालत क्या है। मैं साफ कहना चाहता हूं कि आज भी वहां भूख से लोग मर रहे हैं। लेकिन यह भी इसके साथ सोचने की आवश्यकता है कि ऐसा हो क्यों रहा है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है। यह सब कांग्रेस सरकार के २० वर्ष के कुकर्मों का फल है। हम उस गन्दगी को साफ करने का प्रयास कर रहे हैं। आप समय की रफ्तार को पहचानिये। हम चाहते हैं कि जनता को जल्द से जल्द राहत पहुंचावें। आज हमारे वे साथी जो २० वर्ष तक लगातार इस भुखमरी को दूर न कर सके, हमसे यह आशा रखने में कि हम २० दिन में उस भुखमरी को दूर कर दें, हमारे साथ न्याय नहीं करेंगे। जब कभी मौलिक मान्यताओं को लेकर हमने आगे बढ़ाने की बात की, उसमें हमको आपका सहयोग नहीं मिल रहा है। अगर मौलिक मान्यताओं के आधार पर समाजवादी विचारधारा को अपनाकर कार्य नहीं किया जायगा, उसमें आप हमारा सहयोग नहीं देंगे, तो प्रदेश कैसे आगे बढ़ सकेगा? हम चाहते हैं कि आप जनता जनार्दन के लिये अच्छाई के कामों में, उसकी भलाई के कार्यों में, हमारी सहायता करें, हमारे साथ सहयोग करें। आपके अच्छे सुझावों का हम स्वागत करेंगे हम जनता को अभी कोई अधिक राहत नहीं दे सके है, यह सही है। हमने सिद्धान्तों में अपने को बांधा है। लेकिन फिर भी मैं यह कहना चाहता हूं कि हम भ्रष्टाचार को दूर करना चाहते हैं, जनता को अधिक से अधिक राहत देना चाहते हैं, आत्म निर्भर होना चाहते हैं।

मैं यह कहना चाहता हूं कि इस मौजूदा सरकार ने, जैसे बिहार सरकार ने अकाल क्षेत्र घोषित कर दिया है, मिर्जापुर को अकाल क्षेत्र नहीं माना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी इस मौजूदा सरकार ने वहां के लोगों के भूखे नंगेपन को कम करने के लिये कोई प्रयास न किया हो, भले ही हम उसमें अभी उतने सफल नहीं हो पाये हैं जितना कि हम चाहते हैं। जो वहां की परिस्थितियां हैं, उनके आधार पर भ्रष्टाचार आदि में कुछ न कुछ सुधार अवश्य हुआ है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें वहां अपने काम में तेजी नहीं लानी है। आप भी यह तो महसूस करते ही होंगे कि उद्दंडता से काम नहीं चलेगा। इससे काम चलने वाला नहीं है कि हमारे उधर के साथी हर समय यही कहें कि जनता को कोई लाभ नहीं हुआ, कालागढ़ में क्या हुआ, मिर्जापुर में क्या हुआ, किसानों को कोई राहत नहीं पहुंचाई गई, कर्मचारियों को क्या दिया, कुछ न कुछ ऐसी ठोस योजनायें बनानी होंगी जिससे कम से कम हम लोग कुछ सीख सकें।

हमने सिद्धान्तों की निश्चित योजना में संगठित होते हुए एक ऐसा मोड़ देने की कोशिश की है जिसे आप निश्चय रूप से प्रशंसा के स्वर में अलापेंगे। हम जानते हैं कि अभी भ्रष्टाचार दूर नहीं हुआ है। हम जानते हैं कि केवल कुछ अधिकारियों के इधर से उधर कर देने से भ्रष्टाचार दूर नहीं होगा। हम यह भी जानते हैं कि सिद्धान्त के रूप में वे १९ सूत्री बातें इस वर्ष के बजट में पूरे तौर से ले आना कदाचित् किसी के लिये सम्भव नहीं होगा कि इतने थोड़े समय के अन्दर यह हो सके। लेकिन कम से कम जो कुछ हमने इन २, ३ महीनों में किया है उसे तो आप पहचानिये उसे जानने की आपको कोशिश करनी चाहिए। सेशन चलने से पहले इधर-उधर की घोषणायें हुआ करती थीं कि हम इस सरकार को उलट देंगे। मैं अपने उधर के साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर ऐसी बातें कही गईं या ऐसी हरकत की गई तो प्रजातन्त्र की रोशनी सारी की सारी खत्म हो जायगी। आपको इस सरकार का स्वागत करना चाहिये। साथ ही साथ जहां आलोचनायें और प्रत्यालोचनायें होंगी हम उनका स्वागत करेंगे। लेकिन आपको यह भी देखना चाहिये कि आपके पक्ष में कितने ऐसे लोग हैं जो समाजवादी विचारधारा को लेकर चल सकेंगे।

हम चाहते हैं कि केन्द्र और प्रदेश की सरकारों का आपस में समन्वय स्थापित हो। जब हम कहते हैं कि किसानों का लगान माफ करेंगे, जब हम कहते हैं कि हम कर्मचारियों को कुछ देंगे, तो केन्द्र की सरकार कहती है कि हम पैसा नहीं देंगे। मैं तो कहता हूं कि निश्चित रूप से किसानों का लगान माफ होना चाहिये। उसमें हमारे कांग्रेस के भाइयों का भी प्रयास होना चाहिये। जब किसानों का हम लगान माफ करना चाहते हैं यहां के सरकारी कर्मचारियों को कुछ राहत और देना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश की सरकार को कुछ पैसा केन्द्र से अवश्य मिलना चाहिये।

गल्ला खरीदारी की योजना चली। सम्भव है कि हमारे कुछ भाइयों को जिनके पास ज्यादा जमीन है यह योजना पसन्द न आई हो। जब उत्तर प्रदेश की सरकार अपने किसानों से गल्ले की भीख मांगने चली तो त्रिपाठी जी और बहुगुणा जी ने उसका विरोध करना शुरू कर दिया। लेकिन आपकी सरकार अमरीका और इंगलैण्ड के चरणों में सिर झुका कर भीख मांगती रहे, उसे देखकर आपको शर्म नहीं आती है। हम अपने ही लोगों से भीख मांगते हैं और आप अपनी इज्जत और आबरू को बेचते हो, उसे मटियामेट करते हो। केन्द्र की सरकार का कर्तव्य है कि प्रदेश की सरकार को इस पोजीशन में ले आये कि हम कुछ काम कर सकें। १९ सूत्री कार्यक्रम ऐसा ही है कि जैसे सूरज की रोशनी में तरह तरह के रंगों की किरणें होती हैं और जब वे एक जगह हो जाती हैं तो सफेद रंग की रोशनी पैदा होकर हमको चमक देती हैं। प्रदेश को प्रगति के पथ पर जाने के लिये, समाजवादी विचारधारा को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यकता थी कि सरकार बदलती। मैं विश्वास करता हूं कि जनतंत्र के हिमायती और प्रगति के मार्ग पर देश को देखने वाले हमें कम से कम इस बात का मौका देंगे कि यह सरकार चले। हम अपनी सरकार से मांग कर सकते हैं। वह समय दूर नहीं है जब हम जनता के सामने खड़े होकर यह कह सकेंगे कि उनका लगान माफ हो गया है। इस प्रकार से हम किसानों का लगान माफ करने के लिये प्रयास करत रहेंगे और एक दिन वह माफ हो जायगा, ऐसा हमारा विश्वास है।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त।

*श्री चन्द्रबली (जिला देवरिया)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जब यह सरकार बनी तो मैं उस सरकार के साथ था। इधर कुछ दिनों से मैं उससे अलग बैठने लगा हूं जिसके कारण लोगों का कहना है कि अभी यह सरकार

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चन्द्रबली]

कमसिन है, इस सरकार से छेड़ा-छेड़ी न करो। लेकिन जब पुरानी सरकार केवल १० महीने की थी तो सोशलिस्ट पार्टी उससे अलहेदा हो गयी थी क्योंकि उसने एक चावल को टोह लिया था और उस टोहने से उसको पता चल गया था कि यह कांग्रेस सरकार जनता के हित में कुछ कर नहीं सकती है। लेकिन उस कांग्रेस सरकार को यहां से हटाने में १० महीने के बजाने वर्ष लग गये। इसी प्रकार जब मैंने इस नयी सरकार के चावल को टोहा तो पता चला कि यह भी उसी रास्ते पर चल रही है और इसीलिये मैंने ढाई महीने बाद ही उसका विरोध करना प्रारम्भ कर दिया कि इसको कम से कम ५ साल में हटा दिया जाय।

जब यह सरकार गद्दी पर बैठी थी तो उसने यह वादा किया था कि हम सभी कैदियों को, चाहे वे छात्र हों, किसी पार्टी के हों अथवा सरकारी कर्मचारियों के हों, उनके मुकदमे वापस लेकर छोड़ देंगे। लेकिन यह सरकार उस कार्य को आज तक पूरा नहीं कर पायी। इसने एक वादा यह भी किया था कि जितने भी गोलीकांड हुए हैं उनकी न्यायिक जांच की जायगी तथा भविष्य में अगर कोई गोलीकांड होगा तो उसके लिये एक स्थायी कमीशन नियुक्त कर दिया जायगा जो उनकी जांच किया करेगा। आपने देखा कि इसके ढाई महीने के कुशासन में ३ बार गोली लाठी चल चुकी है---बनारस में, कालागढ़ में और लखनऊ में। लखनऊ में तो चीफ मिनिस्टर के बंगले के सामने स्त्रियों के ऊपर अमानुषिक व्यवहार किया गया, उनको बूटों से ठोकरें लगायीं गयीं जिससे तीन स्त्रियों के तो गर्भपात हो गये। लेकिन उनकी कोई भी न्यायिक जांच कराने के लिये यह सरकार तैयार नहीं है। जब इधर के लोग आपकी आलोचना करते हैं तो आप कहते हैं कि आपने भी तो ऐसा किया था। लेकिन उन्होंने ऐसा न करने का और न्यायिक जांच कराने का वादा कहां किया था? आपने इन दोनों बातों का वादा किया है। आपको उस वादे को पूरा करना चाहिये। इन कारणों से मैंने इस सरकार का समर्थन छोड़ दिया और अलग हो गया।

स बजट में कहा गया है कि बेसहारों को सहारा देने की बात सोची जा रही है, लेकिन, अधिष्ठाता महोदय, १६ महीनों में इस सरकार ने लाखों लोगों को बेसहारा कर दिया है। २० हजार तो कर्मचारियों को बेकार किया है। उन कर्मचारियों में वे महिलायें भी हैं जो अभी तक राज काज से अलग रहती थीं। किसी तरह से भी राजकाज में शामिल नहीं थीं, पर्दा छोड़ कर अभी बाहर आयी थीं, जो समाज का बड़ा भारी पिछड़ा हुआ तबका है, उनको खींच कर बाहर कर दिया गया है। एक लाख हलवाई और एक लाख उनके नौकरों को बेकार कर दिया है। इसके अलावा १२-१३ लाख हलवाइयों के संबंधित लोगों को तथा ३ लाख दूसरे पेशे वालों को, यानी १६लाख लोगों को बेकारी अथवा अर्द्ध बेकारी की दशा में कर दिया है इस संयुक्त सरकार ने। और इसी नाते हमें इस सरकार से अलग होना पड़ा ताकि हम खुलकर उनकी आलोचना कर सकें और कोई हिचक व शर्म न रहे। आप भी ऐसा ही पहले करते थे। हम चाहते हैं कि हमारी आलोचना से सुधार हो और आप सही काम करें।

जो वादे आपने अपने १९ सूत्री कार्यक्रम के द्वारा किये थे जब कि आपका संयुक्त विधायक दल बना था उनको आप पूरा करें और जो मसविदा तैयार किया गया था उस पर आप चलने की कोशिश करें। लेकिन अफसोस है कि आपने इन ढाई मास में कोई कदम नहीं उठाया जिसको कि अभी श्री अश्वनी कुमार जी ने भी कबूल किया और कहा कि किसानों की मालगुजारी माफ नहीं की गई। शर्मा जी जो समाजवादी हैं उन्होंने कहा कि जनता को राहत के लिये हमने भूमि भवन-कर को हटा दिया है। भूमि भवन कर देने वाली कौन जनता है, वाह री आपकी जनता जिसको आपने राहत दी है। मालगुजारी माफ कर के गरीब किसानों को राहत देने की बात नहीं सोची गई ताकि उनका भी मन प्रफुल्लित होता और वह सरकार को आशीर्वाद देते। उसको माफ करते हुये आप हिचकते हैं और कहते हैं कि उसमें अभी कुछ कानूनी अड़चनें हैं। मैं आप से जानना चाहता हूं कि उसमें कौन सी कानूनी अड़चनें हैं। अगर मालगुजारी माफ हो जायगी तो क्या किसान हाई कोर्ट में कोई रिट करने जायगा कि उसकी मालगुजारी

क्यों माफ की गई ? अगर आप बढ़ाते तो उसमें कोई कानूनी अड़चन हो सकती थी लेकिन मालगुजारी हटाने में कौन सी कानूनी अड़चन है ? यह सब बहानेबाजी है और माफ करने का मालूम होता है आपका इरादा नहीं है। जब यह बुनियादी काम आपके जनहित के नहीं हैं तब फिर आप दूसरे जनहित के कोई काम कर सकेंगे इसका ही अब क्या भरोसा है।

वह जो उधर माननीय अश्वनीकुमार, माननीय उग्रसेन जी और दूसरे रिपब्लिकन दल के लोग, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग बैठे हैं उन पर मुझे तरस आता है कि उनका सारा कार्यक्रम वहां बैठ कर डूब रहा है। आज जनसंघ के लोग क्या कर रहे हैं, सहकारी विभाग में जनसंघ के लोगों को ही नहीं भरा जा रहा है बल्कि वह आर० एस० एस० के लोगों को भर रहे हैं और उन्हें मालूम होता है कि केवल उन्हीं का भरोसा है। मैं विकल जी से कहूंगा कि आज बहुत अन्याय हो रहा है परन्तु जब कोई अन्याय के पथ पर चल पड़ता है तो वह रुकता नहीं है जब तक रोका न जाय। कभी भी भूतपूर्व सरकारों से जनता को डर नहीं हुआ है, भूतपूर्व सरकार नहीं सताती है, सताती है वर्तमान सरकार। मां बाप बच्चों को भूत से डराते हैं लेकिन जब वह बच्चों को मारते हैं तभी वह डरते हैं। भूत ने आज तक किसी को नहीं मारा है। तो डर भूतपूर्व सरकार से अब नहीं है, जो डर है वह तो आप से है। जब डर हो तो निश्चित रूप से आपका विरोध करने में किसी हिम्मतवर आदमी का सिर नहीं झुकना चाहिये और अगर कोई डरता है तो वह आदमी फिर जनता के प्रतिनिधित्व से पीछे हटता है।

अब थोड़ी सी बात मैं पैरिटी के बारे में भी सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। कहा गया था और वादा किया गया था कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनका महंगाई भत्ता केन्द्र के बराबर कर दिया जायगा। वह केन्द्र के बराबर तो नहीं किया गया, लेकिन एलान जरूर कर दिया गया कि हमने केन्द्र के बराबर कर दिया। अगर नहीं कर सके हो तो साफ-साफ कह दो कि अभी हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि पैसा नहीं है, दूसरी तरफ भी जनता दुखी है, इतना अभी ले लो और जब अधिक पैसे की जुगाड़ होगी तो और दे देंगे, लेकिन पूरी पैरिटी न देकर यह कहना कि केन्द्र के बराबर हो गया यह झूठ है, उनके साथ धोखा है और गलतबयानी है। जब कर्मचारी लड़ने को तैयार होता है और आलोचना करता है तो कहा जाता है कि वह चौधरी चरण सिंह को गालियां सुनाते हैं, यही लोहिया जी के लिये भी कहा जाता है कि गालियां सुनाते हैं, लेकिन न लोहिया जी गालियां देते हैं और न सरकारी कर्मचारी ही गालियां देते हैं। जब उनको हथियार या लाठी भाले चलाने नहीं हैं तो उनके पास आलोचना और जबान ही एक हथियार है और उनको उसका प्रयोग करना चाहिये। जब उनको तलवार से चोट करना नहीं है, भाला चलाना नहीं है तो फिर वह आवाज उठाने से आलोचना करने से भी कैसे बाज आ सकते हैं जो उनका अधिकार है अगर वे ऐसा न करें तो विरोध और आन्दोलन करने का नतीजा ही क्या होगा ?

आज उनको जेल खाने में नजबंन्दी कानून के अन्दर बन्द कर दिया। मैं आपसे अर्ज करता हूं कि कृपा करके सरकार को मजबूर कीजिये कि वह उन कर्मचारियों के नताओं को रिहा करें क्योंकि उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है। अपनी रोटी रोजी के लिये वह आन्दोलन कर रहे थे, सत्याग्रह कर रहे थे, धरना दे रहे थे। आप अगर उन्हें रोटी नहीं दे सकते तो क्या उनकी बातें भी आप नहीं सुन सकते ?

अभी-अभी हमारे एक माननीय सदस्य जो समाजवादी आन्दोलन के एक अच्छे लेखक भी हैं उन्होंने जो प्रदेश में घटना घटी है सरकार बदलने की उसके बारे में कहा कि रावण का वध हुआ है और विभीषण का राज्य हुआ है। यही बात माननीय राजनारायण सिंह चिल्ला चिल्ला कर कहते थे, जब विकल जी नेता बन रहे थे, कि श्री चरण सिंह जी रावण का वध करो और विभीषण का राज्य लो। वही हुआ लेकिन रावण की बीबी का तबादला नहीं हुआ, वही मन्दोदरी आज उनकी है, श्री बी० बी० लाल चीफ सेक्रेटरी मौजूद हैं। इसका नतीजा यह है कि समूची

[श्री चन्द्रबली]

सरकार बी० बी० लाल के कब्जे में है। राज्य बदल गया है और उस मन्दोदरी के कारण जो घाघ हैं, जिनके घरों में आज भी जांच की जाय तो पैसा मिलेगा और छोटे छोटे कर्मचारियों को बिना कारण बताये आये दिन मुअत्तल किया जा रहा है। जनतंत्र चाहते हो तो कम से कम कारण तो बताओ। अगर माननीय झारखंडे राय की बात का असर पड़ गया हो कि हम तानाशाही चलायेंगे तो कबूल करो उसको और कहो कि हमारी समझ में अगर आ गया कि यह अधिकारी गलत है तो हम तुरन्त आर्डर कर देंगे कि तुम बाहर निकल जाओ, तुम्हारी सेवा की आवश्यकता नहीं है। और अगर माननीय झारखंड राय की बात को नहीं मान लिया है तो अर्ज है कि कारण बताओ और जवाब का मौका दो। अगर ऐसा नहीं किया तो नतीजा यह निकलेगा कि जो सरकारी अधिकारी हैं, जो लूट रहे हैं, मिसाल के तौर पर स्वास्थ्य विभाग की यहां पर एक कमेटी बनी हुई है दवायें खरीदने की, लाखों रुपये की दवायें तो सैम्पिल में भी आ जाती है और कम दाम की दवायें भी नहीं ली जाती हैं, एक छोटी सी फर्म है उसी से कीमती दवायें खरीद ली जाती हैं और इतनी खरीद ली जाती हैं कि दवाओं की अवधि समाप्त हो जाती है और वे पड़ी हुई हैं। इस तरह के बड़े-बड़े अधिकारी हैं जो भ्रष्टाचार के घाघ हैं, लेकिन इनको छांटने की हिम्मत नहीं है। जब तक इनको नहीं छुओगे, मैं उग्रसेन जी से कहूंगा कि वह माननीय चरण सिंह से कहें कि जब तक ऐसे अधिकारियों को नहीं छूयेंगे तब तक भ्रष्टाचार से निजात नहीं मिलेगी। यही लोग लूटने वाले हैं और अगर वह लूट बन्द कर दें तो छोटे कर्मचारी की हिम्मत नहीं कि वह लूट सकें।

लगान माफी और खेत मजदूरों के सिलसिले में इस बजट में कोई नामोनिशान नहीं है। खेत मजदूर बेचारे सबसे दुखिया हैं। ढाई महीने पहले उसका कार्ड बनवाने की चर्चा चली। भूतपूर्व सरकार ने कबूल किया और उसकी वारिस सरकार से ढाई महीने के बाद भी कार्ड नहीं बना पायी। मैंने देखा कि १ महीने में बैलट पेपर छप जाते हैं और इस्तेमाल भी हो जाते हैं। जितना बैलट पेपर छपता है उतने कार्ड नहीं छपते हैं। उसके चौथाई से भी कम छपेंगे। आबादी के आठवें हिस्से के बराबर कार्ड छपना है। ढाई महीने बीत गये खेत मजदूरों को गल्ला नहीं मिला। गल्ला बंटता चला जा रहा है, लेकिन एक भी खेत मजदूर सस्ते गल्ले की दुकान से गल्ला नहीं पा रहा है चाहे आप अपने कागजों में कुछ भी लिखते चले जाओ कि हम इतना गल्ला बांट रहे हैं। वह सब फर्जी है, झूठ है। आप जब तक कार्ड नहीं देंगे और निश्चित तौर पर जो थोड़ा बहुत गल्ला देने का इरादा है उसको देने की कोशिश नहीं करेंगे तो उनको राहत मिल नहीं सकती। जब एतराज आये तो कहेंगे कि खेत मजदूरों को देंगे, लेकिन गल्ला वसूल करके यहां लायेंगे फिर वहां ले जायंगे तो यह नाली को पानी पिलाना है। खेत खाये व्यापारी और मारा गया किसान। आज भी कोई गल्ला व्यापारी पकड़ा नहीं गया। बेहतर है कि गल्ले के व्यापारी के काम को छीन लीजिये। अगर दोनों के साथ आप दुलार करेंगे, व्यापारी और किसान के साथ तो जो हाल कांग्रेस सरकार का हुआ है वही आपका भी होगा। २५० क्विंटल व्यापारी गल्ला रख सकता है। उसकी अब मौज है। अरहर पर कोई बैन नहीं लगाया जिससे सारी अरहर सूबे के बाहर चली गयी। मेरे जीवन में तीन बार ऐसे अवसर आये जब मैं अरहर की छीमी खाकर जिन्दा रहा हूं। उससे अरहर को दूसरे सूबे में आपने जाने दिया जिससे हमारा पेट पलता था। किसान के पास अरहर नहीं है और व्यापारी के घर में अरहर नहीं रह गयी है। जब कि उसे लाभ हो रहा है वह उसे खत्तियों में रखेगा तो ऐसी बात नहीं है। सारा का सारा गल्ला बाहर चला गया।

चीनी के बदले भी आप गल्ला नहीं ले पा रहे हैं। ७ लाख टन चीनी पैदा हुई और साढ़े ३ लाख की प्रदेश में खपत है। चीनी की हालत अजीब है। कितना गोलमाल किया गया है? मैं साफ-साफ कहता हूं कि चीनी का अकाल बनावटी है और मंत्रीवरी द्वारा ही यह चीनी का अकाल है। सरकार के ये सेक्रेटरी आज घूस ले रहे हैं। खूब कमा रहे हैं। किसी को चीनी दे रहे हैं और किसी को नहीं दे रहे हैं। इस चीनी में खूब लूट मची हुई है।

इस बजट में जन कल्याण की बातों को उड़ा दिया गया है। शिक्षा को सिकोड़ा गया है जिससे छात्र न बढ़ने पायें। पैसे वाले तथा मालदार लोग या ताकत वाले लोग हैं उनके बच्चे भरती हो पायेंगे। गरीब छात्रों की छंटनी होगी और वे स्कूलों में भरती नहीं हो पायेंगे।

एक बात झारखंडे राय जी ने कही कि अकाल का सवाल राजनीति से अलग रखना चाहिये। मेरा कहना है कि राजनीति का उद्देश्य ही है सभी समस्याओं को हल करना और किसी समस्या पर राजनीति की आड़ लेकर पर्दा डालना निश्चित रूप से मूर्खता की बात है। खाद्य समस्या हो अथवा पुलिस के अत्याचार की समस्या हो उसे राजनीति से परे बतलाना सरासर मूर्खता है।

इस बजट भाषण में कर्मचारियों की स्तुति की गयी है। मैं उनमें से एक-एक की निन्दा कर सकता हूं, मैं उनमें से एक-एक के कारनामों को जानता हूं, लेकिन माननीय रामस्वरूप वर्मा से मैं थोड़ा प्यार करता हूं इसलिये उस बात को नहीं कहता। मैं कहता हूं कि माननीय वर्मा जी, आपने यह गन्दी परम्परा डाली है। जिस काम के लिये वे नौकर रखे गये हैं अगर उसी काम को वे करते हैं तो कौन सी तारीफ की बात है? हां, उस काम के अलावा अगर कोई और काम भी करते तब आप तारीफ करते तो उचित होगा। सारा बजट किया हर विभाग के लोगों ने और तारीफ छप गयी इनकी। मैं समझता हूं कि फाइनेंस के सेक्रेटरी साहब के कारनामे अगर ठीक कर दिये जायं तो सिर्फ बिक्री-कर से आपका बजट २०–२५ करोड़ रुपये से भर जायगा और आप तुरन्त मालगुजारी माफ कर सकते हैं। लेकिन इनकी हरकतों के कारण बिक्री-कर की जितनी वसूली होनी चाहिये वह नहीं हो पा रही है।

श्री मुरलीधर (जिला वाराणसी)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, सर्वप्रथम मैं आपको जो आपने मुझे यह अवसर दिया है इसके लिये धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि मैं एक नया सदस्य हूं और बड़ी भावनायें लेकर इस विधान सभा में आया हूं। इस विधान सभा में जिस प्रकार के भाषण हो रहे हैं, एक नये सदस्य के नाते मैंने बड़े ध्यान से उनको सुना। बड़े-बड़े नामवर नेताओं के भाषण हुये बजट के सम्बन्ध में भी, प्रदेश की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति के बारे में भी, लेकिन मुझे यह कहना पड़ेगा कि जो आशायें प्रदेश की जनता की हैं उन पर तुषारापात हुआ है। हमारे विरोध पक्ष के नेताओं ने अनेक प्रकार के आरोप किये हैं हमारे संयुक्त विधायक दल के नेता पर, नयी सरकार पर, उसके कारनामों पर और बजट पर। सभी प्रकार से उन्होंने इसको निराशाजनक, क्रान्तिहीन, समाजवादविहीन, इस प्रकार की संज्ञायें दी हैं। लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि एक इतिहास प्रसिद्ध घटना हुई है पहली अप्रैल को। उसके सम्बन्ध में अगर हम सम्यक विचार करें तो हम देखेंगे कि एक महान् क्रान्ति हुई है। यह सच है कि वह क्रान्ति रक्तहीन हुई है, शान्तिमय हुई है और जो लोग क्रान्ति की बात करते हैं शायद उनको विदेशों में ही हुई क्रान्तियों का अनुभव है जहां पर पिछली सरकार के लोग गोली से उड़ाये गये हैं। लेकिन हमने इस शान्तिमय क्रान्ति में भूतपूर्व शासकों का भी स्वागत किया है और हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि प्रदेश की जनता की भलाई के लिये आप सहयोग दीजिये, हम आपका आदर करते हैं। शायद इसीलिये उनको लगता है कि यहां पर क्रान्ति नहीं हुई है।

(इस समय २ बज कर १४ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री श्रीपति मिश्र पीठासीन हुये।)

आज बीस वर्षों से इस प्रदेश में जो कांग्रेसी शासन रहा है उससे हम बहुत भयभीत थे और कांग्रेस वालों ने भी हमको भयभीत किया। चुनावों में प्रचार किया जाता था कि कांग्रेस को कोई अपदस्थ नहीं कर सकता। जनता के मनोबल को तोड़ कर बीस साल तक उन्होंने हमारी छाती पर शासन किया। आज हमको उससे मुक्ति मिली।

इसके पश्चात् हमने देखा कि असम्भव भी सम्भव हुआ है, नौ मत का एक मत हुआ है और इसको करने में जहां हमारे विरोधी दल के नेताओं ने सहयोग किया है, वहां भगवान् की शक्ति ने भी हमें मदद पहुंचाई है। जिस कार्य में मनुष्य की बुद्धि काम नहीं करती है, योजनाओं

[श्री मुरलीधर]

से काम नहीं होता है और वह काम पूरा हो जाता है तो उसमें भगवत इच्छा होती है। जनसंघ और समाजवादी दल के लोग एक दूसरे के परस्पर विरोधी हैं और कम्यूनिस्ट लोग ये सब मिल कर प्रदेश का कार्य करते हैं तो इसमें भगवान की ही इच्छा है। ऐसे दलों के लोग एक मत होकर शासन की गाड़ी खींच रहे हैं तो उसके लिए उनको बधाई देनी चाहिए, उसके लिए हर्ष करना चाहिए कि ये लोग सदियों के विरोध को छोड़कर कार्य करने लगे हैं और देश के कल्याण के लिए एक हो गए हैं।

अपने प्रदेश के विकास के लिए जो यज्ञ हमने प्रारम्भ किया है यह उसका प्रथम चरण है। हमारे चरण प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं और हम सिंह की गति से आगे बढ़ रहे हैं। इसको कोई रोक नहीं सकता है। इसको रोकने वाले भेड़िए, गीदड़ और लकड़बग्घे दूर हो जायेंगे। हमारे विरोधियों ने कहा कि यह सरकार सात-सात सिंहों के बीच में चल रही है। हम तो २२५ सिंह एक साथ चल रहे हैं। अपने प्रदेश की सेवा के लिए एक साथ संगठित होकर जो हमने यज्ञ प्रारम्भ किया है वह दिन प्रति दिन उन्नति की ओर अग्रसर होता जायगा। ऐसा हमारा विश्वास है। कांग्रेसी लोगों ने यह आरोप लगाया है कि हमारे इस दल में अनेक समाजवादी पोषक लोग हैं, लेकिन इस सरकार में समाजवाद का कोई लक्षण नहीं दिखाई देता है। हो सकता है कि यह सरकार समाजवादी न हो। लेकिन यह सच है कि यह सरकार समाज हितैषी है। समाज के लिए जो कार्य उचित है उसको वह करेगी। हम इसको पसन्द नहीं करते हैं कि हम बराबर समाजवाद की रट लगायें और वीभत्स चित्र उपस्थित करें जैसा कि चीन और रूस में हुआ है। जिन साथियों को समाजवाद का नशा हो वे भारत सरकार से पासपोर्ट लेकर चीन और रूस में जायें और वहां देखें और तब आकर बात करें।

हमारे इस दल में समाजवाद के सच्चे विश्लेषक हैं, इसकी व्याख्या करने वाले हैं, जिन्होंने वर्षों तक इसके लिए अपना दिमाग खपाया है उन्होंने यदि समाजवाद के नाम पर रोड़े नहीं अटकाए तो उनको दोष नहीं दिया जा सकता है। इस क्रान्तिमय समाज में जहां मान्यतायें बदल रही हैं वहां हम पुरानी धारणाओं को छोड़ सकते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि हम पुरानी भावनाओं को दूर करके आगे बढ़ें। हमारे दल के लिए कहा गया कि यह सात पतियों वाली है। आप तो कांग्रेस एक पति वाली होने पर भी भ्रष्ट हो चुकी है। हम सात नहीं बल्कि २७ पतियों के होते हुए धर्म की मर्यादा रखते हैं, यह सरकार धर्ममय है और इससे बड़ी आशायें हैं। हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ आवें और हम आप सब लोगों का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। यहां सब के लिए गुंजायश है। हम में से बहुत से ऐसे हैं जो देहात से आए हैं और देहात की पीड़ा लेकर आए हैं।

हमारी जितनी समस्याएं हैं उनमें से अन्न की समस्या सर्वोपरि है। पर असली समस्या जल की है। आज विधान सभा में ५१ तारांकित प्रश्न थे जिनमें से ४७ प्रश्न जल और सिंचाई से सम्बन्धित थे। आज सारी जनता और किसान एक ही रट लगा रहे हैं पानी, पानी, पानी। हमें पानी चाहिए और इस सरकार ने पानी के लिए और सिंचाई के लिए सर्वोपरि ध्यान दिया है। हमें उम्मीद है कि यह सरकार अन्य मदों से कटौती करके पानी की कमी को दूर करेगी और धरती की प्यास बुझाएगी। हम बीस वर्ष में ही नहीं बीस महीनों में वह करके दिखाएंगे, अपनी तपस्या से, मनोबल से, एकता से जिसकी प्रान्त के किसानों को उम्मीद है और जो आज तक पूरी नहीं हुई। हम आप का आवाहन करते हैं। अपना कीमती समय एक दूसरे की आलोचना करने में लगाने के बजाय आप में जो विद्वान हों, जो सोचने समझने वाले हों, वे अपने पहले के नेता, जिनकी मान्यता आज भी कम नहीं है उनका अनुसरण करें। माननीय चरणसिंह ने आवाहन किया है। उन्होंने जो मार्गदर्शन दिया है मैं उम्मीद करता हूं कि जो कांग्रेसी बंधु इस देश का हित चाहते हैं वे उनके साथ आवेंगे हम उनका भी स्वागत करते हैं। हम लोग मिल कर राष्ट्रीय यज्ञ में अपनी आहुति दें।

शर्मा जी ने कहा कि जनकांग्रेस उल्टी कांग्रेस है। उल्टी नहीं, यह कांग्रेस को उलटने वाली है। हम आप का सहयोग चाहते हैं। कांग्रेस को उलटिए, इसको दफा दीजिए। महात्मा गांधी, जिनका चित्र सामने है उन्होंने १९४८ में कहा था कि इस कांग्रेस को विसर्जित कीजिए। उस महात्मा का उपदेश मान कर, न जनसंघ में आइए, न जनकांग्रेस में ही आइए। महात्मा गांधी की इच्छा को पूर्ति कीजिए। आपको बड़ा पुण्य मिलेगा।

(व्यवधान)

जो बेईमान होंगे वह हमारे साथ आयेंगे ही नहीं और अगर आयेंगे भी तो हम उनको शुद्ध करेंगे। रावण और विभीषण के साथ वही मंदोदरी थी। रावण के साथ रह कर वह कुछ नहीं कर सकी। वह बेकार रहेगी, निकम्मी रहेगी, लेकिन विभीषण के साथ आकर मंदोदरी विभीषण की सेवा करेगी।

(व्यवधान)

अन्तःकरण जिसका पवित्र होगा उसका चरित्र निर्मल होगा। पंचभर्त्री पंचाली का प्रातः काल स्मरण होता है और बहुत से लोग जो अविवाहित रहते हैं उनके भ्रष्टाचार की कहानियां गांवों-गांवों में भरी पड़ी हैं। यह आचार विचार मन पर निर्भर करता है।

एक मित्र ने कहा कि हमने अलाभकर जोतों की मालगुजारी माफ करने का इसमें कोई प्राविधान नहीं रखा। मैं स्वयं किसान हूं। मालगुजारी माफ होगी तो देहात के किसानों की भलाई होगी। इसमें शक नहीं यदि, मालगुजारी माफ होती है तो उसका हम स्वागत करेंगे। किन्तु आज यह समस्या नहीं है। इस आधे सेर की बिक्री के समय में, एक रुपये-दो रुपये की की बीघा के हिसाब से जो मालगुजारी पड़ती है यह आज किसान को खलती नहीं। गांधी जी के आन्दोलन के समय में खलता था। लेकिन यह आज कोई समस्या नहीं है। आज समस्या है जल की।

एक सदस्य--

जिसके पास खाने को नहीं है वह दे कहां से ?

श्री मुरलीधर--

इसका हम प्रबन्ध कर रहे हैं। इसलिये हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि हम इन सब योजनाओं को छोड़कर सिंचाई की योजना पूरी करें और अन्न की अधिकाधिक पैदावार से देश को पाट दें। यह सारी समस्या एक डेढ़ साल में हल होने वाली है। मालगुजारी आज माफ हो, कल माफ हो, एक साल में हो–१० साल में माफ हो या न माफ हो, लेकिन इससे किसान को कोई नुकसान होने वाला नहीं है। इस से किसान को इतनी पीड़ा नहीं होगी।

श्री चन्द्रदेव (जिला देवरिया)--

आप देंगे क्या ? आप माफ माफ क्या करेंगे ? आपके बजट में इसके लिये गुंजाइश ही नहीं है।

श्री मुरलीधर--

मेरी धारणा यह है कि हमने जो वादे किये हैं, वे हम पूरा करना चाहते हैं और करेंगे भी, लेकिन हमने तो केवल वस्तुस्थिति की तरफ ओमान का ध्यान आकर्षित किया है। यह प्रश्न उतना ज्वलन्त नहीं है, जितनी बच्चों को जल की पिपासा। हमारी संयुक्त विधायक दल की सरकार अपना प्रत्येक वचन पूरा करेगी। पहले सबसे महत्वपूर्ण विषय सिंचाई पर हमारी सरकार ध्यान दे रही है, उसमें हम आपका सहयोग चाहते हैं, और उसमें आप हमारा सहयोग कीजिये।

श्री चन्द्रदेव—

आप गेहूं चावल के भाव तो बताइए ?

श्री मुरलीधर—

उसकी सारी जिम्मेदारी कांग्रेस के पिछले २० साल के भ्रष्ट प्रशासन पर है और उसकी जिम्मेदारी केन्द्र की सरकार और आपकी इन्दिरा गांधी की सरकार पर है, जिन्होंने भारतीय रुपए का अवमूल्यन किया है, और विदेशी गेहूं से हमारा गला और पेट खराब कर दिया है। आज हमारे विरोधी सदस्य उत्तेजित हो रहे हैं, वे धैर्य रखें और एक माननीय सदस्य की तरह माईक पर कहें। यदि यही उनकी आदत बनी रही तो वे इस सम्मानित सदन और महात्मा गांधी की मर्यादा को कलंकित करेंगे। मैंने पहले ही कहा मैं नया सदस्य हूं और आप मेरी बात शान्ति से सुनें। इस तरह की बातें यह सिद्ध करती हैं कि आप इस योग्य नहीं थे कि इस प्रदेश का शासन कर सकें, इसलिए अच्छा ही हुआ कि आप पदच्युत हो गए हैं और अब यह नई सरकार आपको अनुशासन सिखाएगी।

(लाल बत्ती होने पर)

श्रीमन्, हमें दो मिनट का समय और दे दें। अभी हमारे एक विरोधी सदस्य ने कहा कि कांग्रेस गंगा थी और हम ही गड्ढे थे। मेरा खयाल यह है कि कांग्रेस के नाम को गंगा के साथ जोड़कर गंगा की मर्यादा पूरी तरह से भंग कर दी गयी है। इस तरह से गंगा को बदनाम नहीं करना चाहिए। गंगा महान् पवित्र नदी है और कांग्रेस एक गन्दी पार्टी है। कांग्रेस की भीतरी गन्दगी से उसके सदस्य भी घबड़ाए हुए हैं और अपना दम घुटता महसूस कर रहे हैं, वे यहां पर बैठने के कर्तव्य के नाते चाहे जो कुछ कहें, लेकिन प्रत्येक सदस्य की बुद्धि में यह बात समा गयी है कि कांग्रेस नष्ट हो गयी है और उसे नष्ट होना चाहिए। इस नष्टगामी पार्टी की यदि आप गंगा से तुलना करते हैं तो इससे हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस लगती है। आशा है अब आप अपना कर्तव्य निश्चित करके हमारे साथ आएंगे और जिन्हें गंदगी और दुर्गन्ध प्यारी है वे जहां के तहां रहेंगे।

अब मैं एक शब्द अपने माननीय नेता चरणसिंह जी के विषय में कहूंगा जिनको गाली देने में हमारे विरोधी सदस्य हिचकते नहीं हैं। उनके पांडित्य, उनकी तपस्या उनका चरित्र, उनकी ईमानदारी के विषय में हमें प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। उनका सब से बड़ा त्याग यही है कि पचासों सालों तक जिस संस्था में सेवायें की हैं, उसका मोह त्याग कर, अपने सारे प्रलोभनों पर लात मार कर, जनता की सेवा के लिए जनता के बीच में आकर यह सिद्ध कर दिया है कि "यदा यदाहि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत" उसी तरह से आज चरणसिंह जी के रूप में हमारे लिए भगवान, किसानों के भगवान, इस देश की जनता के भगवान आ गए हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

आपका समय समाप्त।

*डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मन्त्री के बजट भाषण को पढ़कर मैं यह विचार कर रही थी कि ऐसी सरकार जिसकी कोई निश्चित आर्थिक नीति न हो उसके बजट में किन नीतियों को हम ढूंढें। मैंने इसे बड़े गौर से पढ़ा और देखने की कोशिश कि इसमें नयी सरकार किस प्रकार जनता को नया मार्ग दिखाने जा रही है और आगे आने वाले वर्षों के लिए कौन-सी नयी आर्थिक व्यवस्था करने जा रही है। लेकिन मुझे अफसोस है कि उसकी एक भी झलक इस बजट में नहीं दिखाई पड़ती है। सचमुच अगर देखा जाय तो यह एक सिद्धान्त रहित बजट पेश किया गया है। यह बात उचित भी है क्योंकि सात पार्टियों की मिली हुई सरकार जिसकी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अलग-अलग अर्थनीतियां हों, अलग-अलग आर्थिक सिद्धांत हों वह कभी भी आदर्शवादी आर्थिक नीति को अपने बजट में उपस्थित कर नहीं सकती थी। अफसोस की बात है कि हमारे वित्त मन्त्री समाजवादी विचारधारा के हैं लेकिन उन्होंने भी जब अपने बजट भाषण का आरम्भ किया तो सबसे बड़ी बात आलोचना के रूप में रखी कि यह गलत नियोजन का फल है कि आज प्रदेश की जनता आर्थिक कठिनाइयों से गुजर रही है लेकिन आगे चलकर सारी रूपरेखा सारे खर्चे की योजना उन्हीं योजनाबद्ध तरीके, जो २० सालों से चलती रही है, पर की जा रही है। कहीं इधर से उधर भी परिवर्तन नहीं किया गया है। जिस नियोजन के स्वरूप की निन्दा करते हैं, उसको गलत ठहराते हैं उसी स्वरूप में आज बजट पेश करते हैं और उसी तरीके से अनुदान लाते हैं। इससे स्पष्ट है कि या तो स्वयं सुलझे नहीं हैं या स्वयं आपको विश्वास नहीं है लेकिन समय के कारण आपने उसको मान लिया है।

आपने पहले ही पृष्ठ पर कहा है कि आज जो यह घाटे की वित्तीय व्यवस्था है वह भी एक कारण है हमारे प्रदेश की आर्थिक दुर्दशा का। किसी अन डेवलप्ड कंट्री में घाटे की ही अर्थ-व्यवस्था अपनायी जाती है और उसी के द्वारा विकास होता है, लेकिन हमारे देश की समस्याएं इतनी बड़ी और जटिल है उसमें जो हमारी प्लानिंग हैं हो सकता है कुछ उलझाव हों, लेकिन इसके कारण जो हमने मार्गदर्शन दिया था उसमें कोई खराबी हो ऐसी बात नहीं है, उसमें कमी है। इस बजट के ४ पृष्ठों तक पढ़ने पर ऐसा लगता है कि वित्त मन्त्री साहब अपने इस ढाई महीने की सरकार का लेखा जोखा दे रहे हैं कि सरकार ने क्या किया। अगर उस लेखे जोखे को भी देखा जाय तो उसमें भी बहुत सी बातें सत्य से परे कही गयी हैं। अधिक नहीं है, एक ही ले लो जाय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता। कहा गया है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बराबर महंगाई भत्ता राज्य कर्मचारियों का कर दिया गया है। मैं अधिक आंकड़ों में जाना नहीं चाहती लेकिन थोड़े से आंकड़े जो इस समय महंगाई भत्ते के हैं वह मैं आपके सामने उपस्थित करना चाहती हूं। इस समय जो सन्ट्रल गवर्नमेंट का डी० ए० स्केल है वह इस प्रकार है :—

वेतन की दर	सेन्टर में महंगाई की दर	उत्तर प्रदेश में म० भ०
रु०	रु०	रु०
७०—१०६	४७	३२
११०—१४६	७०	४८
१५०—२०६	९०	६१
२१०—३९९	११०	७५
४००—९९९	१२०	८०

अब आप बताइए कि आपकी पैरिटी कहां पर है? क्या आप साधारण से हिसाब को भी नहीं जानते हैं? इन आंकड़ों से बहुत साफ पता चलता है कि पैरिटी तो बहुत दूर है। ऐसी हालत में यह जो वादे किए गए थे, जो यहां पर आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं और जो लेखा जोखा दिया है, वह सत्य से परे हैं।

इसके पृष्ठ ४ पर वित्त मन्त्री जी ने कहा है कि छोटे व्यापारियों की असुविधा कम करने के उद्देश्य से कुछ चीजों पर बहुसूत्रीय बिक्री कर के स्थान पर एकसूत्रीय कर लगाने का विचार किया जा रहा है और साथ ही साथ मौजूदा सेल्स टैक्स ऐक्ट की कमियों को दूर करने के लिए एक नया बिल भी तैयार किया जा रहा है। इससे स्पष्ट है कि या तो नए रूप में आप कुछ वस्तुओं पर टैक्स लगायेंगे जिसके लिए इस समय आपके अन्दर नैतिक साहस नहीं है। इस समय चूंकि यह सरकार थोड़े समय के लिए आई है इसलिए उसको घोषणा नहीं कर सकते।

[डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी]

मैं यह भी बतलाना चाहती हूं कि जो बजट आपने प्रस्तुत किया है उसमें जो आंकड़े दिए गए हैं उनके अन्दर कितना धोखा है। आप भोली भाली जनता को बहुत दिनों तक धोखे में नहीं रख सकते हैं। जो अर्थशास्त्र का विद्यार्थी है और जिसको पब्लिक फाइनैन्स का थोड़ा सा भी ज्ञान है वह इस बात को समझ सकता है। मैं आपके सामने एक छोटा सा उदाहरण रखना चाहती हूं कि किस प्रकार से आपने उत्तर प्रदेश की जनता को धोखे में रखकर यह ५५ लाख रुपया बचाने की बात कही है। बजट का एक हिस्सा रेवेन्यू एक्सपेंडीचर होता है और एक पूंजी व्यय का लेखा होता है। जब हम इस पूरे बजट को देखते हैं तो पृष्ठ ६ पर आप कहते हैं कि पूंजी लेखे में २० करोड़ १७ लाख रुपए का घाटा होगा। राजस्व लेखे में ५५ लाख रुपए की बचत होगी। वहां पर ५५ लाख की बचत का हिसाब आप बताते हैं। तो इस हिसाब से आप पूंजी खाते में २० करोड़ १७ लाख रुपए का घाटा अनुमानित करते हैं जो रेवेन्यू एकाउन्ट में ५५ लाख रुपए की बचत पूंजी में सम्मिलित करने के बाद २० करोड़ १७ लाख का घाटा रह जाता है। आप अगर यह कहें कि केवल जो रेवेन्यू की तरफ से आय-व्यय है उसको अलग रखें और योजनागत जो खर्चा है उसको भी एक दम अलग रख दें तो यह बात जनता को गुमराह करने वाली है।

हमने २० वर्ष तक जनता का अप्रिय बनकर यदि टैक्स लगाया था तो केवल इसलिए लगाया था कि हम योजना को चलाना चाहते थे। यदि हमने भूमि-भवन कर लगाया था तो जनता को हमने बता दिया था कि हमको जरूरत है तीसरी पंचवर्षीय योजना को चलाने के लिए। अगर हमने भूमि पर अधिभार लगाया था चार आने का तो हमने जनता से कहा था कि हमको चीन और पाकिस्तान की लड़ाई का सामना करना है। जब वह लड़ाई खत्म हो गई तो उसको हमारी सरकार ने वापस ले लिया और उस अधिभार को समाप्त कर दिया। इस संयुक्त दल की सरकार ने जनता से १९ वादे किए थे। उसमें पहला वादा लगान को माफ करने का था वह आपने नहीं किया। आप कहते हैं कि उससे भी जरूरी काम आपके सामने हैं। इसलिए इसको कुछ समय के लिए रोक सकते हैं। यह बात सही है। अगर आपने इस बजट के अन्दर यह प्रावि-धान किया होता कि जो लैंड रेवेन्यू की अनइकानामिक होल्डिंग से आय होती है उसको कम करते हैं तो करीब-करीब २२ करोड़ का घाटा दिखाई पड़ता, लेकिन अब आप ५५ लाख की बचत दिखाते हैं तो वह दिखाना शून्य हो जाता है। यह बजट के आंकड़े यह बतलाते हैं कि इस हिसाब से उसको आप पूरा नहीं कर सके फिर हमारा जो गवर्नर का ऐड्रेस होता है वह साल भर सरकार की अर्थ नीतियों को बताने वाला होता है। गवर्नर के ऐड्रेस में साल भर सरकार क्या टैक्स लगाने जा रही है, किस प्रकार की वह अर्थ व्यवस्था करने जा रही है, किन-किन मदों पर विशेष रूप से खर्च करने जा रही है, इस की घोषणा करने वाला होता है। आप ने उस में ही अपना १९ सूत्री कार्यक्रम रखा, लेकिन उस के बाद ही आप कहते हैं कि चौथी योजना में जो घाटा होने वाला है उस के लिए आपको ७, ८ करोड़ रुपए के अन्य साधन जुटाने होंगे और उस के लिए आप कर्मचारियों का रिट्रेन्चमेंट करने जा रहे हैं। हमारी बहिनों को जिन के पति गरीबी के कारण किसी तरह से अपने बाल बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं और जिनको उस गरीबी के कारण ही नौकरी करनी पड़ रही है, उन साढ़े तीन हजार ए० डी० ओ० और ग्राम सेविकाओं को, जो समाज की सेवा का कार्य कर रही थीं, आज उन पर आप की यह रिट्रेन्चमेंट की तलवार लटक रही है और जब उस के विरुद्ध उन्होंने आवाज उठायी तो आप ने उन को लाठियों की मार दी जिस से उन के गर्भपात हुए, उन के हाथ पैर टूटे और वे अस्पताल में पड़ी हैं। आज वे आप के काउन्सिल हाउस के सामने पड़ी अनशन कर रही हैं और मांग कर रही हैं कि उन के ऊपर जो यह बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज हुआ है उस की न्यायिक जांच करायी जाय तो आप उसे भी सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। (व्यवधान)

आप झूठ कहते हैं कि यह लाठी चार्ज हुआ ही नहीं। आपने अपने १९ सूत्री कार्यक्रम में कहा था कि प्रदेश में हर गोलीकांड की आप न्यायिक जांच करायेंगे और उस के लिए एक स्थायी

आयोग की व्यवस्था की जायगी। इस में तो कोई पैसा नहीं खर्च होता। यहां तो जनता आप से न्याय की मांग कर रही है, हमारी गरीब बहनें न्याय की मांग कर रही हैं और आप उस मांग को ठुकरा रहे हैं। इसके बाद भी आपका वादा है कि आप की सरकार जनप्रिय सरकार है।

मैं कर्मचारियों के सम्बन्ध में कह रही थी। ८ दिसम्बर, १९६६ को यहां माननीय टम्बेश्वर प्रसाद जी ने एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव पेश किया था कर्मचारियों की स्ट्राइक के सम्बन्ध में और उन्होंने जो अपना भाषण उस सम्बन्ध में दिया था उस की दो, तीन पंक्तियों में आपको पढ़ कर सुनाना चाहती हूं। और टम्बेश्वर प्रसाद जी को याद दिलाना चाहती हूं कि आज वे उन कर्मचारियों के प्रति अपनी सहानुभूति का परिचय दें। उन्होंने कहा था और सुचेता जी को आगाह किया था कि "जिस समय तक आप इन सरकारी कर्मचारियों की मांगों को यानी उन को केन्द्र के बराबर महंगाई भत्ता दिया जाय—नहीं मानेंगी और इन मांगों को ले कर जब तक ऐसी परिस्थिति का निर्माण नहीं कर सकेंगी कि जिनके कारण उनके जीवन-यापन में रोज-रोज की असुविधायें उत्पन्न न हों, उस समय तक आप भले ही किसी भुलावे में हों, लेकिन आप इस प्रदेश का कार्य चला नहीं सकती"। आज भी वही बात है। अगर आप सोचते हैं कि कर्मचारियों के नेताओं को जेल में बन्द करके, उनको नौकरी से हटा कर, उनकी भूख को कुचल देंगे तो यह संभव नहीं है। मैं झारखंडे राय जी को याद दिलाना चाहती हूं कि जिन्होंने इसी कार्य-स्थगन प्रस्ताव पर बोलते हुए कहा कि "मोटी सी बात है कि जो जैसा काम करे उसे वैसा वेतन दिया जाय चाहे कोई केन्द्र का कर्मचारी हो या राज्य का। केन्द्र और राज्य के कर्मचारी का महंगाई भत्ता एक होना चाहिये, यह मामूली समझ की बात है"। कहां गयी आपकी मामूली समझ? झारखंडे राय जी, आप जरा अपने दिल पर हाथ रख कर देखें कि गद्दी पर बैठते ही आप यह सब भूल गये। आपकी सारी सहानुभूति हवा हो गयी और आज कर्मचारियों को आपकी ही कलम से बंद किया जा रहा है जबकि वह रोटी मांगते हैं।

इस बजट भाषण में माननीय मंत्री जी ने कहा कि कुछ चीजों के भाव कम होने जा रहे हैं। मैं पूछती हूं कि आपने किन चीजों के भाव कम करवा दिये? जिस समय इस प्रदेश की सरकार बदली थी, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जबकि हमारी पार्टी को छोड़ कर उधर कदम रखा तो पहले भाषण में यही कहा था कि चूंकि दूसरी सरकारों ने चीजों की कीमतें घटा दीं लेकिन गुप्ता जी की सरकार ने कीमतें नहीं घटायी हैं इसलिये मैं समझता हूं कि इससे कुछ राहत नहीं मिलने वाली है और वह दूसरी तरफ गये। आज बतायें कि उन्होंने कितनी कीमतें घटा दीं? गुप्ता जी की सरकार के जमाने में चीनी ४ रुपये सेर कभी नहीं बिकी थी। आज जबकि फसल बाजार में आनी चाहिये, ५५ रु० और ६० रुपये मन गेहूं मिल रहा है। तो बरसात में तो ये २ रुपये किलो देने वाले हैं और उस पर कहते हैं कि कुछ मंहगाई रोक दी है।

तो जिस तरह से आप २० करोड़ के घाटे को परा करने जा रहे हैं, जिस तरह से हुंडिया भुना रहे हैं और दूसरी मदों से खर्चा कर रहे हैं उससे यह प्रदेश दीवालिया होने जा रहा है। मैं आपके माध्यम से इस प्रदेश की जनता को बताना चाहती हूं कि इस सरकार की अर्थ नीति धोखे की है और इन्हें आस्था, विश्वास नहीं है समाजवादी मान्यताओं पर, इसीलिये हमारी जो योजनायें हैं जिनके द्वारा खून पसीना एक करके हमने २० साल में प्रदेश की आर्थिक स्थिति को खड़ा करने की कोशिश की थी उनको इन्होंने खत्म कर दिया। इन्होंने हमेशा निगेटिव ऐटीट्यूड रखा है। इन्होंने वादे तो किये कि हमने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिये, ऐग्रिकल्चर को बढ़ाने के लिये व्यवस्था इस में रखी है, लेकिन १९ सूत्री प्रोग्राम में दो कदम थे कि आप सिंचाई की दर में कमी करेंगे, अगर आप और कुछ न करते लैंड रेवेन्यु भी माफ नहीं करते हैं तो पानी की व्यवस्था ही ठीक कर देते और उसे सस्ता बना देते तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ सकता था। लेकिन आज अगर आपकी तरफ से मुख्य मंत्री भी कहें कि हम उस चीज को करेंगे तो भी हम विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि अगर करना होता तो बजट भाषण में उसकी व्याख्या होती, उसका समावेश होना चाहिये था। आपने तो केवल जनता को धोखे में डालने के लिये एक साइकालाजिकल ढंग से जनता को

[डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी]

बहकाने की कोशिश की, एक मनोवैज्ञानिक हवा पैदा करना चाहते थे कि हम ५५ लाख की बचत कर रहे हैं, वह आप कर नहीं सकते हैं। अगर कहीं भी कमी करना चाहेंगे तो कर नहीं सकते क्योंकि बजट घटता ही जायगा और जो सरप्लस दिखाया है वह घटता ही जायगा।

अन्त में यही कहना चाहती हूं कि सरकार को चलाना एक बड़ी जिम्मेदारी का काम है। थोथे स्लोगंस से देश और सरकारें नहीं चलती हैं। झूठे नारे राजनीतिक प्लेटफार्म पर सही उतर सकते हैं, लेकिन जब कुर्सी पर जिम्मेदारी से बैठते हैं, संविधान की प्रतिज्ञा लेकर बैठते हैं तो जनता को धोखा देने की कोशिश न करें।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री मंगलदेव)---

उपाध्यक्ष महोदय, दो दिनों के भाषण के बाद दोनों तरफ से रूपक काफी रहे और एक दूसरे की सही बातों का मानने की भी कोशिश की गयी, कुछ गलत साबित करने की भी कोशिश की गयी। जिस समय सरकार का विघटन हुआ और नयी सरकार बनने की आशा हुई वह दिन ऐसा था जिसको लोग सुना करते थे कि वह बेवकूफों का दिन होता है। अब यह किसकी बेवकूफी हुई, किसकी चतुराई हुई, इसमें मैं जाना नहीं चाहता। नयी सरकार की स्थापना हुई। नयी सरकार बनने में एक काम यह जरूर हुआ कि माननीय चरण सिंह जी व उनके साथी सरकार बनाने में सहायक हुये। कई दल मिल कर एक हो गये। पिछली जो सत्ताधारी पार्टी थी उसने जो बड़े-बड़े नकाब लगाये, विरोधी दल के काफी लोग टूट कर उसमें मिल गये, तो उससे ऐसा लगता था कहीं ऐसा न हो जाय कि एक एक करके हम लोग खत्म हो जायं। माननीय गेंदा सिंह जी जो बहुत दिनों तक हमारे नेता रहे हैं, उनकी उस वक्त सत्ताधारी पार्टी को कोई जरूरत नहीं थी, उनको निजी भी कोई जरूरत नहीं थी, कांग्रेस पार्टी काफी बहुमत में थी, वे टूट कर कांग्रेस में आये। उस वक्त लोक मर्यादा का उनको खयाल नहीं आया। गेंदा सिंह जी तो सदा ही सर्वंगरा और हरिजनों के नेता रहे हैं और मुझे विश्वास है आगे भी रहेंगे। तो जब उस समय सत्ताधारी पार्टी में खींचखांच शुरू हुई तो विरोधी दलों में एक डर व्याप्त हो गया और फिर सभी विरोधी दल एक साथ हो गये।

मान्यवर, प्रदेश की जनता काफी दिनों से यह इन्तजार कर रही थी और जनता की यह आवाज थी कि पिछली कांग्रेस सरकार बदले। हुआ भी यही और माननीय चरण सिंह जी को उन सब का नेतृत्व करना पड़ा। आज जो यह बात कही जाती है कि इस प्रकार की तोड़ फोड़ की घटनायें पीठ में छुरा भोंकने की भांति है या अराजकता पैदा करने वाली है, या बोझा देने वाली है, ठीक नहीं है।

मान्यवर, सारी बातें बजट में नहीं आ सकतीं, सारी समस्याओं का जिक्र बजट में नहीं हो सकता। संयुक्त विरोधी दल के लोग उन सारी समस्याओं के प्रति सजग हैं। केवल कागज में उनका उल्लेख कर देने से ही वे हल नहीं हो जाया करतीं। १९ सूत्री कार्यक्रम को चर्चा सदन में और सदन के बाहर बड़ी तेजी से हो रही है। मैं समझता हूं यह बहुत बड़ी गलती है। साढ़े ८ करोड़ जनता की सारी समस्यायें केवल १९ सूत्री कार्यक्रम से ही पूरी हो जायं, यह हो नहीं सकता। वह तो एक संकेत था, जितनी समस्यायें हैं उनकी गिनती कागजों में नहीं हो सकती। वे अपनी जगह पर हैं। किन्हीं कारणों से हो सकता है कि उनका संकेत नहीं हुआ हो। लेकिन जो समस्यायें हैं उनमें यह तो नहीं कि वे नहीं हैं। मुझे पिछले बजट के देखने का मौका मिला था। उसकी जानकारी है। चूंकि हम नये आदमी हैं, व्यक्तिगतरूप से ज्यादा तो नहीं है, काफी कोशिश की गई। जहां हमारे माननीय भूतपूर्व मंत्रियों और विद्वान साथियों को देखने में दो चार घंटे लगते थे उसे ही हम नये लोगों के देखने में ३५ घंटे लगे। तो उसमें क्या मिला? लोग कहते हैं कि योजना का इसमें संकेत नहीं हुआ। यह सही है कि बहुत से अनावश्यक कामों का संकेत नहीं हुआ। पिछली सरकार का तो यह मामला था नयी स्कीम डेढ़ो रुपया हमारे पास है। परन्तु संयुक्त विधायक दल सरकार की समस्या है

कि बिना जरूरत की स्कीमों को काटो, हमारे पास अन्य अनेक समस्यायें हैं। मैं अनेक उदाहरण दे सकता था लेकिन मैं एक ही उदाहरण दूंगा। हमारा प्रदेश और देश आर्थिक संकट में है और अनेक समस्यायें हैं। एक जगह ऐसा महकमा खोला गया था जो अनावश्यक था जिसमें अचार, चटनी और मुरब्बा बनाने की ही ट्रेनिंग दी जाती थी। इस पर भी काफी रकम खर्च हो रही थी। तो कहने का मतलब यह है कि इस तरह के कुछ काम खोले गये थे।

गल्ला खरीद की योजना पर बड़ी आलोचनायें हुई है और केवल आलोचनायें ही नहीं मुझे प्रसन्नता हुई जानकर कि बीसों वर्षों के बाद कांग्रेस के वयोवृद्ध लोग तिरंगा झंडा पब्लिक के बीच में कंधे पर रखे, जुलूस तो निकला और किन लोगों का जुलूस काफी था उनका जिनके पास जमीन नहीं थी, जो दो एकड़ के थे जो मजदूर थे, उसमें से आठ एकड़, दस एकड़ और साढ़े बारह एकड़, सिंचित और असिंचित ऐसे खेत वालों को अलग कर दिया जाय तो जुलूस नहीं निकल सकता था, थोड़े से लोग रह जाते। इसका बड़ा विरोध हुआ और जिन शब्दों का प्रयोग हो सकता था हुआ। जैसे कि यह एक दम डंडे की वसूली हो और यह अन्न जैसे कि कुछ लोगों के घर चला जायेगा। प्रदेश में अन्न का संकट है और मंहगाई की चर्चा कर रहे हैं। तो क्या यह मंहगाई रोकने का ही विकल्प नहीं था? आज कुछ लोग हल्ला ज्यादा किये हैं कि गल्ला नहीं है। गरीब आदमी हरगिज हल्ला नहीं किये हैं। बड़े-बड़े किसान, बड़े-बड़े तोंद वाले बड़े-बड़े बनियों ने हल्ला किया है। जो बड़े-बड़े बनियों के हाथ ज्यादा कीमतों पर गल्ला बेच रहे हैं। सरकार ने तो निर्णय ले लिया है कि ८५ रु० में वह गल्ला खरीदेगी और सौ रुपये क्विन्टल वह माकट में ला देंगे। इसमें तो कुछ परिवर्तन होने वाला नहीं है। ११५, १२० और १३० रु० क्विन्टल गल्ला खरीदा जा रहा है बनियों द्वारा। जो इस प्रकार गल्ला खरीदने वाले होते है वे महंगाई फैलाने वाले होते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि यह क्यों होता है? आज कहा जाता है कि घरों में गल्ला नहीं है लेकिन बड़े-बड़े महाजनों के घरों में गल्ला कहां से आ जायगा तो बरसात के दिनों में १२ छटांक का बिकेगा। बड़े-बड़े किसान और बनिया गरीबों के हाथ गल्ला बेचते है, भादों के महीने में मजदूरों के पास गल्ले का अभाव हो जाता है। सस्ते भाव पर गल्ला खरीद कर माघ के महीने में जब बदली होती है गल्ला बेचते हैं। इस समय गल्ला नहीं है, जहां है मौत का सौदा करने के लिये है। यह सरकार भुखमरी और मंहगाई को रोकने के लिये सजग है। यह सरकार उस नक्शे को यू० पी० में नहीं लाना चाहती है जैसा कि १९४३ में बंगाल के अन्दर अकाल पड़ा था और लगभग ३० लाख आदमी वहां भूख से मर गये थे। क्या वहां गल्ला नहीं था? क्या वहां चावल नहीं था? था लेकिन जमीन पर नहीं था, जमीन वाले मर रहे थे और वह तहखाने में नीचे था, यह बात जांच रिपोर्ट से मालूम हुई। आज गल्ला है और सरकार इसके प्रति सजग है। हो सकता है कि विरोध के बावजूद सरकार को गल्ला कम मिले, लेकिन इसमें तो हम चाहते थे कि आपका हमें बड़ा भारी सहयोग होगा और यह सही है कि बहुत से लोगों ने सहयोग दिया है और उस स्कीम को अच्छा कहा है। इस स्कीम के बारे में कुछ गलतियां थीं जिनको हमारे माननीय साथी मंत्री जी ने मंजूर किया जिनके बारे में समय-समय पर उनको ध्यान दिलाया गया। इसके माने यह हैं कि कोई हठधर्मी ऐसी नहीं रही है और हमेशा जनता की जो आवाज आवेगी और सही मालूम होगी, सरकार उसको मानने के लिये तैयार है।

मजदूर समस्या और किसान समस्या की चर्चा की गयी। बीस वर्षों तक सरकार कांग्रेस के हाथ में रही और २० वर्षों से उत्तर प्रदेश के किसान व मजदूर आपके साथ रहे, लेकिन उनकी समस्याओं को हल करने के लिये आपने क्या किया? आज दो दिन में जादू से कुछ होने वाला नहीं है। हम आपके साथी है, आप हमारा सहयोग कीजिये ताकि हम किसान, मजदूर और गरीबों की समस्या का हल निकाल सकें क्योंकि आपको २० वर्ष का अनुभव भी है।

हरिजनों की सेवा के बारे में माननीय चतुर्भुज शर्मा ने बात की और कहा कि कांग्रेस एक ऐसी संस्था रही और है जिसने तमाम हरिजनों के लिये बड़ा भारी काम किया। जो कुछ काम किया हो, उसका मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, जो कुछ काम किया हो वह सत्य है, उससे मैं

[श्री मंगलदेव]

इन्कार नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो काम सरकार २० वर्षों में नहीं कर सकी वह दो महीने के अन्दर ही जादू की छड़ी से नहीं हो सकता। बीस वर्षों से कांग्रेस पार्टी की सरकार यहां जमी हुई थी और उसे हरिजनों का समर्थन बराबर प्राप्त था। हरिजनों के लिये उसका सारा खजाना खुला हुआ था और सारा काम उसने किया, लेकिन क्या यह सही है कि प्रदेश के हरिजनों का गोबर से अनाज निकाल कर खाना खत्म हो गया ? क्या यह सही है कि अब वे सड़ा हुआ महुवा और चोटे नहीं खाते ? हरिजनों की हैसियत बहुत अच्छी हो सकती है लेकिन हरिजनों का नाम लेकर केवल घड़ियाली आंसू बहाने से कुछ होने वाला नहीं है।

इस हाउस में बराबर इस बात की चर्चा होती रही कि लोक सेवा आयोग में हरिजन और पिछड़ी जाति के किसी सदस्य को भेजा जाय, लेकिन इस लायक सरकार को कोई लायक आदमी बीस वर्ष तक नहीं मिल सका। क्या यह सही नहीं है कि माननीय चरण सिंह ने एक ऐसे सदस्य की नियुक्ति कर दी जिसकी बहुत दिनों से प्रदेश में मांग थी ? तो हरिजनों के काम के बारे में इस सरकार ने अब सोचना शुरू किया है। ऐसा नहीं है कि गांवों से लोग यहां नहीं आते हैं। वे सारी समस्याओं को समझते हैं। उनके लिये अलग से आप कोई समस्या खड़ी कर दें, ऐसी बात नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रियों के दौरे की बात कही गयी। एक भूतपूर्व मंत्री ने कहा कि यह जो छापामार दौरे होते हैं, ये बहुत गलत हैं। हो सकता है जांच करने का हमारा ढंग गलत हो लेकिन हमारी नीयत साफ है। माननीय भूतपूर्व मंत्री ने कुछ इंस्पेक्टर की संज्ञा दी। वह तो सरकारी पद है, एक ऊंचा पद है लेकिन इन मंत्रियों ने तो ८ करोड़ जनता के प्रति कसम खायी है कि वे उनके पहरेदार रहेंगे और चौकीदार की हैसियत से बहुत अच्छी तरह से जांच करने की क्षमता वे रखते हैं और इसी प्रकार से जांच होती रहेगी। जिन आंखों से सरकारी कर्मचारियों को दिखायी नहीं देता है, जिन आंखों से प्रबन्धकों को दिखायी नहीं देता है अगर मंत्रियों को दिखायी देता है तो इसलिये दिखायी देता है कि उन्होंने जनता की रक्षा की कसम खायी है और उन्होंने कसम खाई है कि वे सदा जनता के प्रति वफादार रहेंगे। उन्होंने कचहरी वाली झूंठी कसम नहीं खायी है। उन्हों ने तो आठ करोड़ जनता के जीवन की रक्षा और उसकी तरक्की की कसम खायी है। मैं आशा करता हूं कि आप इस बजट को और आने वाली ग्रान्टों को अपना समर्थन प्रदान करेंगे और अपने मूल्यवान सुझावों के द्वारा हमारी मदद करेंगे।

*श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—

उपाध्यक्ष महोदय, यह नानकांग्रेस गवर्नमेंट का पहला बजट है और मान्यवर, यह पहला मौका है जब संयुक्त समाजवादी दल के वित्त मंत्री ने इस बजट को पेश किया है। मुझे बड़ी आशा थी उनसे। जिस समाजवाद की चर्चा यह कांग्रेस सरकार करती थी और जिसके बारे में यह कहा जाता है कि वह समाजवाद को आगे नहीं बढ़ा सकी है, लेकिन समाजवादी वित्त मंत्री ने भी उसको आगे बढ़ाने के लिये कुछ नहीं किया। समाजवादी नीतियां तो दूर रहीं, समाजवादी मर्यादा, समाजवादी प्रवृत्तियां, समाजवादी दृष्टिकोण और समाजवादी दिशा की बात तो छोड़ दीजिये, समाजवाद शब्द को प्रयोग करने का भी साहस माननीय वित्त मंत्री को अपने बजट भाषण में नहीं हुआ। कारण उसका स्पष्ट है कि वे भानुमती के पिटारे के एक अंग हैं और उसमें जनसंघ का आधिपत्य है, उनके डर के मारे और अपनी कुर्सी से चिपके रहने के लिये उनको ऐसा करना पड़ा है और वित्त मंत्री कोई समाजवादी बजट प्रस्तुत नहीं कर सके हैं। यह बात मैं ही नहीं कहता हूं, डाक्टर लोहिया ने उनसे यही कहा कि तुमने इस बजट को प्रस्तुत क्यों किया, अगर मुख्य मंत्री करना चाहते थे तो उनको करना चाहिये था।

माननीय झारखंडे राय जी ने कहा कि इस गवर्नमेंट के आने से नये युग का निर्माण हुआ है, नये इतिहास का निर्माण हुआ है इस देश में और इस प्रदेश में। उन्होंने कहा कि २० साल के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कांग्रेस शासन को धराशायी कर दिया गया। आज जनता यह नहीं चाहती कि किसी एक दल की सरकार बने, वह मिली जुली सरकार चाहती है। मैं यह मानता हूं कि जनतंत्र में सरकारों का बदलना एक स्वस्थ परम्परा है, उससे जनतंत्र मजबूत होता है, लेकिन मुझे दुख है जिस तरह से ८-९ पार्टियों ने इसको बनाया है जो परस्पर विरोधी हैं जिनमें सिवाय कांग्रेस के प्रति घृणा के और कुछ भी कामन नहीं है। भला इस घृणा के आधार पर यह कब तक चलेगी? गुप्ता जी ने ठीक ही कहा था कि अगर सब पार्टियों के अस्तित्व को मिटा कर एक पार्टी बनती तो हम भी उसका स्वागत करते। एक नये युग का इतिहास बन रहा है और हम समझते थे कि कोई नई और अच्छी चीज पैदा होगी। लेकिन इसमें हमने देखा कि जो पोलिटिकल मारेलिटी थी, जो पोलिटिकल कैरेक्टर था, जो पोलिटिकल स्टैंडर्ड था, जो पोलिटिकल ईमानदारी था इन्टेग्रिटी थी वह बिलकुल स्मेश हो गई है। आज जिस ढंग से पोलिटिकल लोग रोज इधर से उधर जाते हैं वह एक सोचनीय बात है और इससे जनतंत्र मजबूत नहीं हो सकता। एक गीता का श्लोक है

'यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ।'

भगवान कृष्ण की बात भी कही गई, लेकिन दलों को इस तरह से छोड़ कर जाना, जिस दल के टिकट पर खड़े हों, जिन जनता के मतों से सफलता प्राप्त की जाय, जिस दल के पैसे से कामयाबी हासिल की जाय उस को छोड़ना इस तरह से जनता के साथ विश्वासघात है, उसकी पीठ में छुरा भोंकना है। क्या गीता यही सिखाती है? मेरे दोस्त ने मिसाल दी कि श्री गेंदा सिंह जी भी और उनके कई साथी कांग्रेस में शामिल हुये थे। सही बात है वह भी आये और माननीय नेकराम जी भी जो इन्डिपेन्डेन्ट चुन कर आये थे वह भी कांग्रेस में शामिल हुये जिस स्थिति में और एक आल इंडिया बहस होने के बाद, एक दल का फैसला होने के बाद कि हम समाजवाद को मजबूत बनाने के लिये कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं तब उस आदेश के अनुसार गेंदा सिंह जी कांग्रेस में शामिल हुये थे, लेकिन फिर भी मैं इस बात को मानने के लिये तैयार हूं कि बहुत सी स्वस्थ परम्पराओं की अवहेलना कांग्रेस पार्टी ने भी की है और अगर इस प्रवृत्ति को चेक न किया गया तो जनतंत्र का नाश तो हो ही जायगा, बल्कि देश की मजबूती और स्टैबिलिटी ही खत्म हो जायगी और एक कन्फ्यूजन, एक के आस और एक अनाकी पैदा हो जायगी जिसको कंट्रोल न किया जा सकेगा। चाहे गलती किसी की हो, लेकिन हम सब को एक कोड आफ कन्डक्ट मानना होगा पूरे देश के लिये, चाहे वह कन्वेन्शन से हो या किसी तरह से हो, इस बात को मानना पड़ेगा कि जो जिस दल के टिकट से चुनकर आये उसको यह तो अधिकार हो कि वह अपने राजनीतिक विचारों को बदल दे, लेकिन उस ईमानदारी से जिसका आदर्श आचार्य नरेन्द्र देव जी ने रखा था उस परम्परा को हमें अपने यहां स्थान देना होगा और उसी को आधार मानना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं किया गया तो इस देश में न समाजवाद होगा और न जनतंत्र ही रहेगा। (व्यवधान) जरा शांति से सुनें. जब राकेश जी बोल रहे थे तब मैं बड़ी शांति से सुन रहा था अब उधर के लोग भी शांति से सुनें।

माननीय झारखंडे राय जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को तो जनता ने हमेशा के लिये रिजेक्ट कर दिया है। जिसके दल के सिर्फ १४ सदस्य ही चुन कर आये हों वह अगर उस दल के लोगों से ऐसा कहें तो हंसी आती है, जिस दल के कि १९९ लोग चुन कर यहां आये हैं, वह उस दल को चुनौती देते हैं। मुझे दुख है कि आज अवसरवादिता और प्रलोभन में श्री झारखंडे राय जी यह भूल गये कि तमाम विरोधी दलों का टोटल १८८ होता था और चौधरी चरण सिंह जी ने पद की लोलुपता में आकर कांग्रेस के साथ विश्वास घात किया, उसकी पीठ में छरा भोंका और १६ आदमियों को लेकर उधर वह शामिल हो गये। अगर वह उधर शामिल न हुये होते तो उन की सरकार बनना तो क्या, माननीय झारखंडे राय जी को कुर्सी भी नसीब न हुई होती। (व्यवधान)

मैंने जब इस बजट भाषण को पढ़ा तो मुझे इस बात में कोई मुगालता नहीं था और मैंने उनकी नीतियों को जब इसमें ढूंढ़ा तो उसमें कोई कम्युनिस्ट दल की नीति, रिपब्लिकन्स की नीति,

[श्री नवल किशोर---]

सोशलिस्टों की नीति कहीं कुछ नहीं मिला, क युनिस्ट पार्टी के २८ मेम्बर्स में से एक मिनिस्टर और एक डिप्टी मिनिस्टर हैं, एस० एस० पी० के नुमाइन्दे मिनिस्ट्री में हैं, पी० एस० पी० के नुमाइन्दे हैं, लेकिन जब मैंने इसमें नीतियां ढूंढ़ी तो उसमें किसी की नीति की झलक नहीं थी केवल जनसंघ की नीति की उसमें कुछ झलक दिखाई दी। माननीय वर्मा जी का बजट भाषण हम लोगों ने सुना और उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ वरडिक्ट देना शुरू किया कि उसने २० साल के शासन में कुछ नहीं किया ।

मैं एक बात कहना चाहता हूं अपने नौजवान दोस्त माननीय राकेश से कि जो पार्टी या जो नौजवान राष्ट्रीय इतिहास को मिटाया करते हैं वे कभी नया इतिहास बनाया नहीं करते हैं। मुझे इस बात का अफसोस नहीं होता अगर माननीय झारखंडेराय ने यह बात कही होती । मुझे अफसोस है कि माननीय चरण सिंह की सरकार के बजट में कांग्रेस की नीतियों के बारे में कहा जाता है कि वह अनगॅल थीं। मान्यवर, जिनका स्टेचर कांग्रेस के अन्दर बैठ कर बना हो, जिन्होंने कांग्रेस मंत्रिमंडल के एक सीनियर साथी के नाते कांग्रेस की नीतियों का निर्माण किया हो, खास तौर से कृषि, भूमि सुधार के सम्बन्ध में जिस व्यक्ति का हाथ रहा हो, उसके नेतृत्व की सरकार अगर कंडेम करती है तो घुमा फिरा कर माननीय चरण सिंह की सरकार का कन्डेमनेशन है और उनके ऊपर एक आक्षेप किया जा रहा है। मैं इस बात को भी माने लेता हूं जैसा वर्मा जी ने कहा कि ढाई महीने में जादू नहीं कर सकते हैं, मगर जो आप की हरकतें हैं वह इस बात का संकेत है कि किस दिशा की तरफ आप चलना चाहते हैं। उसका जिक्र मैं बाद में करूंगा।

माननीय झारखंडे राय ने कहा कि खाद्यान्न की समस्या एक भयंकर समस्या है, नेशनल समस्या है और उसको तेजी से हल करना चाहिये। मैं उनके इस कथन का स्वागत करता हूं, मगर उनके मुख्य मंत्री ने क्या किया ? जिस समय माननीय गुप्ता जी मुख्य मंत्री थे, उस समय विरोधी पक्ष में ८, ९ पार्टियां थीं उन्होंने सब के नेताओं को दावत दी कि हमको प्रोक्योरमेंट करना पड़ेगा, उसके सिद्धान्त को मानना पड़ेगा और आइये और हम साथ बैठ कर विचार करें और ऐसी नीति अपनायें जो किसानों के लिये कम से कम कष्टदायक हो। क्या माननीय चरण सिंह ने इस बात की कोई शराफत, कोई ऐटीकेट या डीसेंसी और डेकोरम दिखाया, जब कि केवल एक ही पार्टी विरोध में है, कि उसके नेता या कांग्रेस के अध्यक्ष, माननीय कमलापति त्रिपाठी जी को, जो सदन के मेम्बर हैं, उनको बुला कर किसी समय उन्होंने प्रोक्योरमेंट के बारे में बातचीत की होती ? कौमन कर्टेसी है कि अगर कोई चिट्ठी लिखे तो उसका जवाब दिया जाय । मुझे दुख है कि जो चिट्ठी माननीय गुप्ता जी ने चौधरी साहब को भेजी, उसका उन्होंने जवाब तक नहीं दिया। आप इस तरह कहते हैं कि राष्ट्रीय समस्या है और उसके समाधान में हम विश्वास दिलाते हैं कि कांग्रेस कंधे से कंधा मिला कर चलने को तैयार है, मगर जो ऐलीमेंट्री शराफत है, तहजीब है, उसको पद के जोम में छोड़ना नहीं चाहिये। माननीय झारखंडे राय जी ने कहा कि लाखों एकड़ जमीन पड़ी हुई है उसका वितरण नहीं किया कांग्रेस सरकार ने, हजारों एकड़ का फार्म बिड़ला का है। मान्यवर, मैं थोड़ी देर को मान लेता हूं कि हमने उस जमीन को नहीं बांटा, गलती की, बिड़ला जी का फार्म हमारे यहां बना, गलती न होते हुये भी दलील के तौर पर गलती मानता हूं, लेकिन माननीय झारखंडे राय और वर्मा जी बतायें कि उन्होंने अपने बजट भाषण में इस बात का संकेत किया है कि लाखों एकड़ जमीन का बंटवारा किया जायगा और किस आधार पर किया जायगा---हमने नहीं किया, ठीक है, लेकिन जब आप जानते हैं कि पता नहीं कितने दिन हमारी सरकार टिकेगी तो आपको तो उस बारे में कुछ करना चाहिये था, अपने विचार प्रकट किये होते ।

मान्यवर, पूंजीवाद की बात की जाती है । मैं पूछना चाहता हूं कि केरल के अन्दर माननीय नम्बूदरीपाद किस पार्टी के नुमाइन्दे हैं। उन्होंने दावत दी है बिड़ला जी को कि वह केरल में आकर इंडस्ट्रियलाइजेशन करें। मुझे इसमें कोई अफसोस नहीं है, मैं यह सिद्धान्त मानता हूं

कि यदि हो सके तो नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण करना चाहिये। लेकिन अगर हम उसको नहीं कर सके तो मैं जानना चाहता हूं कि राष्ट्रीयकरण की तरफ कोई कदम आपने बजट के अन्दर उठाया है। अगर नहीं उठाया तो यह साबित करता है कि आप की बातें जब आप इधर थे थोथी थीं, आप क ते कुछ हैं और करते कुछ और हैं। मान्यवर, इस सरकार के जो अचीवमेंट हैं। .....

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

अब शुरू हुये हैं।

श्री नवल किशोर--

मान्यवर, माननीय उग्रसेन जी उनमें से हैं जो इधर क रहे न उधर के रहे। मान्यवर, जब मैं उनके एचीवमेंट की बात कहता हूं तो सबसे पहला उनका एचीवमेंट यह हुआ चरण सिंह जी की मोहब्बत और २० साल के ताल्लुकात में जब ३ तारीख को उन्होंने यह सरकार संभाली तो ५ तारीख को मेरे कुछ कागजात शिक्षा मंत्री की हैसियत से नहीं, सिटीजन्स कौंसिल के चेयरमैन की हैसियत से एक रिक्शे पर अन्डर सेक्रेटरी की पर्मिशन से गेट पास सहित खुले रिक्शे पर जा रहे थे। दो माननीय सदस्य इसी हाउस के थे उन्होंने उसको रोका और एक अजीब कांड बना दिया गया। उन कागजात को रोका गया। मुझे पता चला तो मैंने चौधरी साहब से कहा कि जो यह अशोभनीय घटना हुयी है उसके लिये मुझे तकलीफ है। मैंने कहा कि आप उन कागजात को अपने दफ्तर में मंगवा लीजिये और देख लीजिये कि एक फाइल भी सरकारी इसके अन्दर हो तो मैं बड़ी इज्जत के साथ अपनी मेम्बरी से सुबुकदोश हो जाऊंगा, वर्ना आप अनकंडीशनल एपोलाजी मांग लें। कागजात सील किये गये, ताले पर उन मेम्बरों की भी सील लगी, अखबारों में बारदात छापी गई और तरुण भारत में भी छापा गया कि सी० आई० डी० की जांच हो रही है। मुझे पता चला है कि सी० आई डी० ने लिखा है कि इसके अन्दर कोई सरकारी कागज और सरकारी फायल नहीं है। लेकिन माननीय मुख्य मंत्री ने इतनी भी डिसेंसी और कामन कर्टसी नहीं बरती कि कम से कम एक एपोलाजी उसके लिये मांग लेते। ६ तारीख को सरकार बनी लेकिन झारखंडे राय जो भी उस समय जब वह मिनिस्टर नहीं थे बड़े कूद रहे थे। (व्यवधान)।

श्री उग्रसेन--

उपाध्यक्ष महोदय, जब हम उधर बैठते थे तो उस समय भी नवल किशोर जी के साथ हमारी मोहब्बत और गर्मी हो जाती थी। मैं अपने लायक दोस्तों से कहूंगा कि वे लोग उनको सुनें क्योंकि अब उनको भी हल्ला करने का हक है। हम जब उधर थे तो हमने भी काफी बलवा मचाया था।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे शान्तिपूर्वक माननीय नवलकिशोर जी को सुनें और विचारों का आदान-प्रदान इस तरह से न करें।

श्री नवल किशोर--

माननीय उग्रसेन जी ने कहा मुझे बड़ा गुस्सा आ गया, तो मुझे एक शेर याद आ गया --

"उनको आता है मेरे प्यार पर गुस्सा,
मुझे उनके गुस्से पर प्यार आता है।"

६ तारीख को जब यह सरकार बनी तो ७ तारीख को जी० पी० ओ० पार्क में इम्पलाईज की एक मीटिंग हुई जिसमें मिनिस्टर्स की स्पीचेज हुईं और पायनियर में छपा था "मिनिस्टर्स बिहेव्ड लाइक डेलिक्वेंट चिल्डरन"। उसमें कहा गया कि न कांग्रेस सरकार हटती न एस०

[श्री नवल किशोर]

बी० डी० की सरकार आती, अगर राज्य कर्मचारियों ने ऐतिहासिक और अनपैरेलेल्ड एजिटेशन न किया होता। सैटिन साहब ने फरमाया, न तुम हमारे नौकर हो, न हम तुम्हारे मास्टर हैं और तुमने देशभक्ति का बहुत बड़ा काम किया है। माननीय झारखंडे राय जी ने कहा कि मिस्टर सुकुल विल गो डाउन इन हिस्ट्री ऐज ए लिजेन्डरी फीगर। अंत में उन्होंने कहा :

He could never forget the thrilling scene of the mass court arrest programme of the employees in Lucknow which made many a top Leaders anxious to see who Mr. Sukul and Mr. Ghosh were.

लेकिन आज वही लिजेन्डरी नेता आपकी सरकार के द्वारा जेल में बन्द हैं जिनकी रिहाई की मांग एक सच्चे समाजवादी मिस्टर चन्द्रबली सिंह ने की है अगर आपके कानों में जूं रेंग जाय।

यही नहीं, वाराणसी के अन्दर साम्प्रदायिक दंगा हुआ, गोलीकांड हुआ। समाजवादी दल की बहुत दिनों से मांग थी और आपके १९ प्वांइट प्रोग्राम में भी यह मांग है कि हर फायरिंग के बाद इंक्वायरी होनी चाहिये, मगर आपने कोई जांच नहीं कराई और आपके समाजवादी नेता गोपालनारायण सक्सेना जी ने इसी बात पर इस्तीफा दे दिया है। उसके बाद कालागढ़ का कांड हुआ। तमाम दलों ने मांग की, कम्युनिस्ट पार्टी ने मांग की, उग्रसेन जी जो उधर बैठे हुये हैं, अब चाहे इस समय उनकी बोली बन्द हो जाय, उन्होंने मांग की कि जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिये। मगर चौधरी साहब ने नहीं माना। स्त्रियों के ऊपर जो कुछ हुआ उसको मैं रिपीट नहीं करूंगा, मेरी एक बहन ने बहुत काफी कह दिया है। उसके बारे में इश्तहार छपे हैं।

यही नहीं, एम्पलाईज की स्ट्राइक हुयी। मैं उन लोगों में से हूं जो इस बात को मानते हुये कि एम्पलाईज की मांगों के साथ सहानुभूति होनी चाहिये, एक भाई ने कहा कि हमने १० करोड़ रुपये दिये, आपने क्या दिया। आप तो उस समय मौजूद थे। पी० आर० सी० की रिपोर्ट मानने का मतलब था कि १८–१९ करोड़ रुपये पिछली सरकार ने दिये। अच्छा होता चौधरी साहब कहते कि हमने आपको १० करोड़ रुपये दिये, इस से ज्यादा नहीं दे सकते हैं। बहस तब शुरू हुयी जब आपने कहा कि हमने सेन्ट्रल गवर्नमेंट के साथ पैरिटी दे दी है। इस जिद को छोड़ कर निगोशियेशन्स का द्वार अपनाइये और जिस वन मैन कमीशन के आधार पर आपने दिया है उसको रेफर कीजिये। मेरी मांग यह है कि जो कमीशन बनाया गया था उसकी रिपोर्ट को प्रकाशित कीजिये।

श्री उग्रसेन—

आपने क्यों नहीं प्रकाशित किया था ?

श्री नवल किशोर—

जिस समय गुप्ता जी की सरकार बनी उन्होंने इस बात का कमिटमेंट किया कि जो उसकी रिपोर्ट होगी उसको वह और उनकी सरकार मानेंगी। मगर गुप्ता जी पहले ही चले गये। मगर आपने हमारी बात को भी झूठा किया, अपनी बात को तो किया ही।

मेरे दोस्त झारखंडे राय जी ने कहा कि हम एकोनामी करना चाहते हैं। मैं उनकी इस घोषणा का स्वागत करता हूं और यकीन दिला ता हूं कि वे हर सही कदम जो एकोनामी की तरफ बढ़ायेंगे उसका हम स्वागत करेंगे। मगर एकोनामी के माने रिट्रेंचमेंट नहीं होता। गुप्ता जी ने ही नहीं, बराबर कई मु य मंत्रियों ने ऐलान किया कि हम एकोनामी करेंगे, रिट्रेंचमेंट नहीं करेंगे। (लाल बत्ती होने पर) कुछ समय और दे दीजिये। दस मिनट और दे दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—

आप ७ मिनट और बोल लीजिये।

श्री नवल किशोर—

मान्यवर, उग्रसेन जी बहुत शोर मचाते थे, कमिटमेंट किया कि रिट्रेंचमेंट नहीं होगा। यह वेलफियर स्टेट की स्पिरिट के खिलाफ है कि बजाय इसके कि इम्पलाईमेंट बढ़ायें, आप उसको काट रहे हैं। आप डिस्ट्रिक्ट इंफारमेंशन आफिसर्स को भी काट रहे हैं। इसके पीछे आपका मोटिव अच्छा नहीं है। यह एक पोलिटिकल वेन्डेटा है।

मान्यवर, जब मैं प्रोक्योरमेंट पर आता हूं। बड़ा शोर मचाया जा रहा है कि कांग्रेस ने इसका विरोध किया। इस से बड़ा और कोई फ्राड नहीं कर सकता है। कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध नहीं किया है। सिद्धान्ततः हम इसको मानते हैं और आज भी मानते हैं कि देश की ऐसी स्थिति है कि आपको यह करना पड़ेगा। चाहे आपको यह पसन्द आये या न आये। जो सुझाव दिये गये, उनमें से बहूतों को माना गया। इसके लिये हमें खुशी है। जिन्होंने विरोध किया उनके लिये आपने कुछ नहीं कहा और कांग्रेस को बदनाम किया गया। तलवार साहब और पीताम्बर जी ने ज्वाइंट स्टेटमेंट निकाला कि प्रोक्योरमेंट का हम विरोध करते हैं, हम इसको सही नहीं मानते हैं। इससे स्केयरसिटी पैद होगी। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि हम एक्सपेरीमेंट करना चाहते हैं इसलिये हम उसको एक मौका देना चाहते हैं। सी० पी० आई० और एस० एस० पी० ने इसका विरोध किया और गोरखपुर में कहा कि हम इसका विरोध करेंग। कोई पार्टी ऐसी नहीं थी जिसने प्रोक्योरमेंट का विरोध नहीं किया हो। हमने सिद्धान्त में भी विरोध नहीं किया। लेकिन जिन्होंने बिरोध किया उनसे आप कुछ नहीं कहते हैं।

माननीय झारखंडे राय जी खाद्य मंत्री हैं, वह और माननीय उग्रसेन जी बड़ा शोर मचाया करते थे कि हमारे यहां स्टेट ट्रेडिंग होनी चाहिये। मैं कहता था कि हम इसके सिद्धान्त को मानते हैं, लेकिन इसमें कुछ कठिनाइयां हैं। लेकिन आपने तो सिद्धान्त को भी नहीं माना। आपने तो बात करना ही छोड़ दिया। समाजवाद की बात भी बन्द हो गई। पता नहीं आज आप किस वाद पर पहुंच गये हैं।

मान्यवर, आज सूखा ४१ जिलों में हैं। माननीय उग्रसेन जी देश के नेता हैं, समाजवादी हैं और मुझे उनसे मुहब्बत भी है। लेकिन आज उनकी आग बुझ गई है। और केवल राख ही राख रह गई है। वह कहा करते थे कि इस क्षेत्र को अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित कीजिये, उस क्षेत्र को घोषित कीजिये। लेकिन अब मिर्जापुर से आता है कि २०० मर गये, ५०० मर गये इस पर भी उनकी बोलती बन्द हो गई है। वह कुर्सी से चिपक गये हैं। जो असर हमको २० साल में हुआ वह इनको ढाई महीने में ही हो गया (व्यवधान)।

मान्यवर, एक बात और इन्होंने की कि आनरेरी मजिस्ट्रेटों को खत्म कर दिया और इसलिये खत्म कर दिया कि वे कांग्रेस के बनाये हुये थे अगर वे भ्रष्टाचारी थे तो उनको इंप्रूव करना चाहिये था। लोग रोज सदन में कहते हैं कि पुलिस बड़ी भ्रष्टाचारी है तो उसको आप खत्म कर दीजिये। इंस्टीट्यूशन को भ्रष्ट होने पर लिक्वीडेट नहीं किया जाता है बल्कि उसको इंप्रूव किया जाता है।

मान्यवर, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट के तीन इनग्रेडियेंट्स होते हैं। एक तो मोनोलिथिक कैबिनेट होनी चाहिये। दूसरी यह कि होमोजिनिटिक इन थिंकिंग होनी चाहिये और तीसरे कलेक्टिव रिस्पौंसिविलिटी होनी चाहिये। लेकिन यहां हालत यह है कि माननीय विकल जी कहते हैं कि लैंड रेवन्यू शनै: शनै: माफ होगी, माननीय उदित नारायण जी कहते हैं कि माफ नहीं होगी। दो मंत्रियों ने बयान दिया कि लैंड रेवेन्यू माफ हो रही है अगली कैबिनेट मीटिंग में। लेकिन चौधरी साहब ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। चौधरी साहब ने कहा कि अनप्रोडक्टिव पोस्ट्स को खत्म कर रहे हैं और एक ने कहा कि खत्म नहीं की जायेंगी। हमारे भाई प्रताप सिंह जी को घूमने का बड़ा शौक है। उन्होंने कह दिया कि हमारे यहां चीन की चार डिवीजनें घुस आई हैं। चौधरी साहब ने कहा कि नहीं आई हैं। अभी एस० एस० पी० की मीटिंग हुई। डाक्टर लोहिया ने किन शब्दों में कहा, वह सोचिये। माननीय

[श्री नवलकिशोर]

शराफत हुसैन ने चौधरी साहब को एक चिट्ठी लिखी कि वह संयुक्त विधायक दल से क्यों अलग हो रहे हैं, उसमें किस तरह से जातिवाद\के और दूसरे लांछन थे, आप स्वयं पढ़ लीजिये, चन्द्रशेखर जी ।

मान्यवर, उन्होंने टूर्स किये । अच्छी बात है । मुझे कोई आपत्ति नहीं है । मंत्री लोग टूर करें । जानकारी होती है । एडमिनिस्ट्रेशन में सतर्कता आती है । लेकिन अगर इसलिये टूर किया जाय कि आदमियों को तोड़ा जाय तो यह मुनासिब बात नहीं है । मुजफ्फरनगर में, राजेन्द्रदत्त जी मौजूद हैं, चौधरी चरण सिंह ने कहा कि मैं मुजफ्फरनगर को तोड़ने के लिये आया था । मेरा काम यही था । कहीं म्युनिसिपैलिटी में घुस गये । जो कांड बदायूं में हुआ, कानपुर में हुआ, क्या यह उचित बात है ? भ्रष्टाचार मिटाना चाहते हैं, तो हम साथ हैं लेकिन भ्रष्टाचार के नाम पर लोगों को डराइये धमकाइये नहीं । जिस तरह से ट्रांसफर और सस्पेंशंस किये जाते हैं आपने ऐडमिनिस्ट्रेशन में एक डर पैदा कर दिया है । आप जो कदम उठाना चाहते हैं मजबूती के साथ उठाइये, लेकिन उसमें पोलिटिकल मेंडेटा होना गलत है । आप कहते हैं कि कांग्रेस के मंत्रियों की जांच करायेंगे । मैं दावत देता हूं आप जांच करवाइये, लेकिन यह ट्रेडीशंस पर भी रिक्वायल करेंगे । मैं अपना भाषण एक शेर पढ़ कर खत्म करूंगा---

'नहीं जिनको पहचान है, खारो गुल की,
चमन हो गया आज उनके हवाले ।"

श्री राज बहादुर द्विवेदी (जिला फैजाबाद)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल से बजट पर चर्चा चल रही है । हमारे माननीय नेता विरोधी दल और कई विरोधी दल के सदस्यों ने समाजवाद की बड़ी चर्चा की कि इस बजट भाषण में समाजवाद की चर्चा तक नहीं है । अभी-अभी माननीय नवलकिशोर जी ने भी इसकी चर्चा की है, लेकिन मैं माननीय नवल किशोर जी से जानना चाहता हूं कि इसके पहले जब कांग्रेस मंत्रिमंडल ने अपना बजट पेश किया था जब मैं उन्हींके साथ बैठता था तो उस समय भी मैंने अपने भाषण में कहा था कि माननीय बहुगुणा जी के बजट भाषण में कहीं भी समाजवाद शब्द की चर्चा नहीं थी । आज माननीय नवल किशोर जी रोना रो रहे हैं कि यह बजट समाजवादी मंत्री ने पेश किया है लेकिन इसमें समाजवाद की चर्चा तक नहीं है । यह संविद की सरकार है । समाजवाद इसका कोई लक्ष्य नहीं है । एक सामान्य कार्यक्रम बनाया है । लेकिन मैं उन मित्रों से पूछना चाहता हूं कि जो बार-बार अपने भाषण में समाजवाद की चर्चा किया करते हैं कि उनके मंत्री ने जब बजट प्रस्तुत किया था तो उसमें समाजवाद की चर्चा क्यों नहीं आयी । मैं मानता हूं कि यह समाजवादी बजट नहीं है । इसको मैं जनकल्याणकारी बजट की संज्ञा देता हूं । इसमें कुछ विशेषतायें हैं । सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत दिनों के बाद पहली बार माननीय वित्त मंत्री जिसको मैं बधाई दूंगा बचत का बजट पेश किया है । इससे फिजूलखर्ची रुकेगी ।

दूसरी बड़ी इसकी विशेषता है कि आज तक जनता प्रति वर्ष, जब बजट पेश करने की बात आती थी, डरा करती थी और भयभीत होकर देखा करती थी कि देखो कौन सा नया टैक्स इस बार आने वाला है । लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि इस बार इस प्रदेश की साढ़े आठ करोड़ जनता के लिये कोई नया कर प्रस्तावित नहीं किया गया है । इसकी दूसरी विशेषता यह है कि इस प्रदेश की ८० फीसदी जनता जो गांवों में रहती है किसान है, जिनका पेशा कृषि है, उनकी स्थिति में सुधार किया गया है । उनकी स्थिति में जब तक सुधार नहीं होगा, प्रदेश की स्थिति ठीक नहीं होगी । इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है सरकार ने इन किसानों को सुखी बनाने के लिये सबसे ज्यादा पैसा दिया है ।

इसमें एक और बहुत बड़ी बात है वह यह है कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिये इस प्रदेश में जो नयी व्यवस्था की गई है उससे इस प्रदेश की जनता में न केवल आशा का संचार हुआ है बल्कि उसकी सरकार में आस्था जम गई है । यह बजट समाजवादी नहीं है, इसे जो आप

कहते हैं उसे मैं भी मानता हूं और स्वीकार करता हूं कि यह बजट समाजवादी नहीं है, किन्तु यह बजट जनकल्याणकारी अवश्य है। यह मैं दावे के साथ कहता हूं और इस पर प्रदेश की जनता को पूरा विश्वास है। नवल किशोर जी कहते हैं कि चौधरी साहब ने और उनके कुछ साथियों ने विश्वासघात किया है और विश्वासघात करके कांग्रेस शासन को पतन किया है। मैं मानता हूं कि मैंने विश्वासघात किया है, मैं इस आरोप को बुरा नहीं मानता हूं, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है, किन्तु प्रश्न यह है कि मैंने विश्वासघात किसके साथ किया है। मैंने विश्वासघात कांग्रेस के कुछ चन्द स्वार्थियों के साथ किया है, जिन्होंने प्रदेश की ८ करोड़ जनता के साथ २० वर्ष तक विश्वासघात किया है। इतिहास इसका साक्षी होगा कि मैंने यह विश्वासघात का कार्य किया है या क्रांति का काम किया है।

(व्यवधान)

मेरे इस कार्य की इतिहास में प्रशंसा की जायेगी कि मैंने जनता की भावनाओं का समुचित आदर किया है।

अनेक सदस्य—

तो फिर दुबारा एलेक्शन लड़कर देख लीजिये।

(व्यवधान)

श्री राज बहादुर द्विवेदी—

मैं चाहता हूं कि मर्यादा की रक्षा कीजिये, नवलकिशोर जी ने यही कहा है। मैं मानता हूं कि मैंने विश्वासघात किया है, लेकिन इसका फैसला कौन करेगा ?

अनेक सदस्य—

जनता, जनता।

श्री राज बहादुर द्विवेदी—

नहीं, मैं बता रहा हूं, इसका फैसला जनता करेगी और....

श्री राम मूर्ति अंचल (जिला शाहजहांपुर)—

तो फिर एलेक्शन कराकर देख लीजिये, इस्तीफे देकर मैदान में आइये, हिम्मत हो तो आइये। मैं आपको चुनौती दे रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री राज बहादुर द्विवेदी—

अच्छा अब आप शान्ति रहिये, बैठ जाइये, जो सच्चाई कह रहा हूं, उसे बुरा क्यों मान रहे हो ?

श्री राम मूर्ति अंचल—

आपने हमारी पार्टी का रुपया लिया है, उस रुपये से आप जीतकर आए हैं, आप इस्तीफा दीजिये, तब चाहे जहां जाइये।

(व्यवधान)

श्री उग्रसेन—

इस बजट को ५ दिन चलना है, ५ दिन तक आप अपने विचारों को रखें। जैसे हमने शान्ति से नवलकिशोर जी को सुना वैसे आप हम लोगों की भी बात सुनिये।

(व्यवधान)

श्री राम मूर्ति 'अंचल'—

मैं आप से सुन सकता हूं। लेकिन इन से नहीं। सूप बोले तो बोले छलनी क्या बोले जिसमें बहत्तर छेद हैं; छलनी को हम क्या सुनें?

श्री उपाध्यक्ष—

शान्तिपूर्वक आप लोग इस विवाद को चलने दीजिये। राजबहादुर जी, आप जो कहें वह अध्यक्ष को सम्बोधित करके कहें, आपस में बातचीत न करें।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जरा आप भी इस पर गौर करें। थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक तथ्य है। माननीय उग्रसेन जी जितना चाहें कांग्रेस पर आक्रमण करें और हम लोगों की आलोचना करें, लेकिन वह लोग जो कांग्रेस टिकट पर कांग्रेस के प्रतिज्ञा-पत्र पर लड़कर आये हैं, कांग्रेस के रुपये पर चुने गये हैं जब वे विश्वासघात करके इस तरह से बोलते हैं तो उनको हम सुनने के लिये कैसे तैयार हो सकते हैं?

(शेम शेम)

श्री त्रिवेणी (जिला आजमगढ़)—

एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठें। श्री राजबहादुर जी, आप बोलिये।

श्री राजबहादुर द्विवेदी—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से आपके माध्यम से प्रस्ताव रखता हूं कि यदि हमने विश्वासघात किया है....

(अत्यधिक शोर)

श्री उग्रसेन—

मालूम होता है उन कुर्सियों में गर्मी ज्यादा है; जो वहां पहुंच जाता है, वही सबसे ज्यादा शोर करता है।

श्री त्रिवेणी—

आप मेरी वैधानिक आपत्ति सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठिये।

(श्री रामप्रसाद देशमुख के खड़े होने पर 'बैठो-बैठो' की आवाजें।)

अनेक सदस्य—

हम इसे नहीं बोलने देंगे।

(शोर, अधिक शोर)

श्री राज बहादुर द्विवेदी—

मैं आपके माध्यम से प्रस्ताव करता हूं।

(अत्यधिक शोर)

श्री उग्रसेन---

आप माननीय नेता विरोधी दल से आग्रह करें कि वह अपने लोगों से कहें कि वह इनको सुनें।

श्री उपाध्यक्ष---

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जब एक सदस्य बोल रहे हों तो इस तरह से ऐसी अव्यवस्था न करें और ऐसा वातावरण न बनायें जिससे एक दूसरे की बात समझने में आपस में विचार विनिमय करने में अड़चन पैदा हो।

(शोर)

मेरा आप से नम्र निवेदन है कि आप सहयोग देंगे और शान्तिपूर्वक सदन की कार्यवाही चलने में मदद करेंगे।

श्री राज बहादुर द्विवेदी---

मैं यह निवेदन कर रहा था कि यदि हमने विश्वासघात किया है तो इसकी परीक्षा जनता के बीच हो जानी चाहिये।

(व्यवधान)

श्री त्रिवेणी---

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं माननीय सदस्य से यह पूछना चाहता हूं कि क्या हमारे इन बन्धु ने कांग्रेस टिकट के लिये कमलापति त्रिपाठी जी के पैर को नहीं छुआ था।

श्री उपाध्यक्ष---

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री राज बहादुर द्विवेदी---

इस सदन के नेता माननीय चरण सिंह, जो जनकांग्रेस के नेता हैं वे और विरोधी दल के कांग्रेस के नेता श्री चन्द्रभानु गुप्त दोनों अपना-अपना त्यागपत्र दे दें और जनता के न्यायालय में चले जायं और चाहें जिस क्षेत्र से जिससे गुप्ता जी चाहें उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ लें तो उनको मालूम हो जायगा और जनता बतला देगी कि किसने विश्वासघात किया है। मैं इस तरफ जाना नहीं चाहता था, लेकिन माननीय नवलकिशोर जी ने इस विवाद को छेड़कर मुझे उस तरफ ले जाने का प्रयत्न किया है। कांग्रेस तो एक पवित्र मन्दिर की तरह है जहां पर लोग पूजा करने के लिये जाते हैं, लेकिन उसके तथा कथित पुजारी पतित हैं और भ्रष्ट हैं और इस सारे देश को भ्रष्ट कर रहे हैं। भक्तों के लिये विवश होकर कोई और चारा न रह गया सिवा इसके कि वे किसी दूसरे मन्दिर में जाकर अपने श्रद्धा के सुमन चढ़ावें। (व्यवधान)

*श्री रामलाल (जिला फैजाबाद)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे सरकार ने जो बजट पेश किया है उस पर बोलने का समय दिया। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि मैं एक प्रतिनिधि के रूप में बोल रहा हूं, ईमानदारी से चुन कर आया हूं तभी यहां बोलने का अधिकारी हूं। विधान सभा में खड़ा हूं और पूर्ण रूप से बोलने के लिये अधिकृत हूं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय सदस्यगण से निवेदन है कि आपस में इस तरह बातचीत करके वातावरण में गरमी न पैदा करें। धीरे-धीरे बोलने दें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राधेश्याम कपूर (जिला लखनऊ)---

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। अभी माननीय सदस्य ने कहा कि वे ईमानदारी से चुन कर आये हैं। मैं जानना चाहता हूं कि यहां बेईमानी से चुन कर कौन आया है।

श्री रामलाल---

मान्यवर, बहुत से उपदेश तरह-तरह के आये कि बजट पर भाषण नहीं होते या इसी तरह की और बातें कही गयीं, लेकिन देखा यह जाता है कि हर व्यक्ति जो इस तरह का उपदेश देता है अन्त में बहकता चला जाता है और वह स्वयं बजट पर भाषण नहीं देता। मैं मानता हूं कि बजट पर कुछ माननीय सदस्यों ने बड़े अच्छे ढंग से अपने विचार प्रकट किये हैं जिनमें हमारी महिला बहन सब से आगे हैं। बहुत सी बातें बजट के बारे में कहने की थीं जो कि कही जा चुकी हैं। यद्यपि मैं मानता हूं कि बजट को यदि सही तौर पर समझा जाय तो वह केवल सरकारी कर्मचारियों के वेतन का बजट है और कुछ योजनाओं के बारे में कुछ पैसे का बटवारा किया गया है। फिर इस पर क्या बहस की जाय? कौन से प्रश्न खड़े किये जायं अथवा कैसी अपेक्षा की जाय, कुछ कहा नहीं जा सकता। बजट में है ही क्या जो उस पर बात की जाय? हां, मुझे कुछ प्रश्न नीति के अवश्य ऐसे हैं कि जिन पर विचार करना है। कुछ लोगों ने यह आवाज उठायी है कि यह जो कुछ हुआ है वह कांग्रेस के कुशासन का परिणाम है।

(इस समय ३ बज कर ५८ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

यदि आप केवल कुछ नारों की आड़ लेकर यह सोचें कि आप जनता का समर्थन प्राप्त कर सकेंगे, प्रदेश का प्रशासन चला सकेंगे या प्रदेश की व्यवस्था कर सकेंगे और प्रदेश को विकासशील बना सकेंगे तो यह असंभव बात है। आप को कड़ाई के आधार पर काम चलाना होगा, सचाई का आधार लेना होगा और वही सही रास्ता होगा सामाजिक विकास का। केवल लम्बे-लम्बे नारों के बल पर सरकारें नहीं चलतीं। आप जिम्मेदारी के पदों पर हैं।

मैं मानता हूं कि हमारे खाद्य मंत्री जी ने बड़े जोर से इसी आवाज को उठाया था। बीस वर्षों में देश समाजवाद की ओर बढ़ा या नहीं, यह एक बड़ा मौलिक प्रश्न है। अगर आप सोश्यो-इकोनामिक की आंखें लेकर देखेंगे तो पता लगा सकेंगे अन्यथा पता नहीं लगा सकेंगे। २० वर्षों में जितनी योजनायें बड़ी बड़ी चली हैं, चाहे स्टील का प्रोजेक्ट हो, मशीनों या टूल्स की परियोजनाएं हों या दूसरी बड़ी योजनाएं हों वह सब बुनियाद को मजबूत करने वाली हैं। वह सब "की" इंडस्ट्रीज, बेसिक इंडस्ट्रीज सब राजकीय स्तर पर चलायी गयी हैं। आज राष्ट्रीयकरण की बातें हम करते हैं कि जो नयी योजनाएं हैं वह राष्ट्रीय स्तर पर चलायी जायं, इस प्रकार से राष्ट्रीयकरण की बुनियाद डाली जा रही है। इस देश की सरकार ने २० साल तक केन्द्र में और प्रदेशों में ऐसी बुनियाद डाली है कि पूंजीपतियों के हाथों में इंडस्ट्रीज न पहुंच पायें और राष्ट्रीय स्तर पर चलायी जायं। अब अगर इसे कोई समझने की चेष्टा न करे और यों ही केवल नारे लगाये जायं तो इससे कुछ सिद्धि प्राप्त होने वाली नहीं है और देश का काम भी आगे बढ़ने वाला नहीं है। इन योजनाओं का परिणाम ऐसा नहीं है कि वह आंखों से ओझल हो सकता हो।

हमें स्मरण है, १५-२० साल पहले लोहा किसान खरीदता था तो मिल जाता था २० रुपये के भाव से और उस पर कंट्रोल था और दूसरे राज्यों में भी नियंत्रण था। आज देश भर में लोहा इफरात से मिलता है। वह काफी ही नहीं मिलेगा बल्कि उचित दामों पर भी मिलेगा। इसी तरह से दूसरी चीजों की बात है। हमारी परिस्थितियों के आधार पर ही हमारी विकासशील परियोजनाएं बन सकती थीं। आप देखें कि जब अंग्रेज यहां से गये सन् ४६ में तो केवल साढ़े पांच लाख टन का उत्पादन स्टील का छोड़ गये थे, लेकिन आज १६ गुना स्पात का उत्पादन हो गया है और राष्ट्रीय स्तर पर वह उद्योग चल रहे हैं जिनका परिणाम आपके सामने है। कितनी ही चीजें जो हम बाहर से मंगाते थे वह सब यहां ही तैयार होने लगी हैं।

एक बात सबसे आगे आती है कि कंज्यूमर गुड्स का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ है। यह सही है कि इस ओर कितनी ही बुनियादी योजनाएं चलायी गयी हैं और सारे देश का रेवेन्यु उधर ढकेलना है जिससे ग्रामीणों का एक्सप्लायटेशन बन्द हो सके। अगर उनको अच्छी तरह से चला लें तो जितनी भी उपभोग सम्बन्धी योजनाएं हैं, उद्योग-धंधे हैं उनको चलाने में हम समर्थ हो सकेंगे। आज परिस्थिति यह जरूर है कि हम इस आधार पर खड़े हो सकते हैं। बल्कि आपको बताऊं कि १५ साल पहले अगर सिंचाई के लिए ५ हार्स पावर का इंजिन खरीदने जाते तो बाजार में मिलता नहीं था, यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। आर्डर प्लेस करने के बाद ४-४ बार तलाश करने पर भी साढ़े सात हार्स पावर का इंजिन नहीं मिल सका। आज स्थिति यह है कि आपके यहां यह सारी चीजें मिल जाती हैं। लघु सिंचाई की इन चीजों को आप गांव-गांव में ले कर वहां सिंचाई की व्यवस्था कर सकते हैं। आप लोग स्वयं जानते हैं कि कितने टेक्नीकल इन्सटीट्यूशन्स खोले गये हैं। आज गांव में भी आपको टेक्निकल लोग मिल सकते हैं। ५-६ हार्स पावर्स के इंजिन लगा कर आज सिंचाई का उचित प्रबन्ध कर सकते हैं। मुझे आशा थी कि हमारे समाजवादी मित्र जो सदैव राष्ट्रीयकरण की बात करते हैं, लघु सिंचाई की ओर कुछ कदम उठायेंगे। लेकिन इस ओर कोई चर्चा नहीं है।

श्रीमन्, कुछ कर्मचारियों को निकालने की योजना बनायी गयी है। कुछ करों को माफ किया है। यह सब आप किसानों की कुर्बानी पर कर रहे हैं। आपने महिला मंगल योजना को समाप्त किया, यह बड़ा गलत काम किया है। हमारे समाज का आधा भाग आज निकम्मा और बेकार है। उस ओर आपका ध्यान नहीं गया है। अमेरिका में काफी ऐसी स्टेट्स हैं जहां केवल महिलायें ही शिक्षा का कार्य करती हैं बृजनाथ सिंह जी वहां गये थे, उन्होंने बताया था कि वहां जब यह कहते थे कि हमारे यहां पुरुष शिक्षा का कार्य करते हैं तो हंसी होती थी और कहते थे कि क्या पुरुष पढ़ा सकता है। महिलाओं की उपयोगिता को न समझकर, यदि आपने महिलाओं के लिये बनायी गयी इस योजना को बन्द किया तो इसके लिये देश आपको क्षमा नहीं करेगा। अगर उनकी रोटी रोजी छीनी जाती है, एक ऐसी योजना को जिससे कि समाज में सोशियोलाजीकल चेंज होने वाला है, आपने बन्द किया तो मैं समझता हूं कि यह आपकी बौद्धिक दिवालियेपन का नमूना होगा। अगर आपने यह किया तो आपको कोई पूछेगा तक नहीं।

मान्यवर, कहा गया कि पहले ही अगर लघु सिंचाई योजना का कार्य शुरू किया जाता तो कुछ काम हो जाता। मैं पूछना चाहता हूं कि पहले लघु सिंचाई योजना का आधार क्या था। हमारे पास कुंवा था, उससे ही लोग सिंचाई का कार्य करते थे। आप परिस्थितियों की उपेक्षा कर केवल यही कहना चाहते हैं कि कांग्रेस बुरी है कांग्रेस में कुछ नहीं है। अगर यही बात है तो आप शौक से कांग्रेस को बुरा कहिये, उससे कुछ होने वाला नहीं है।

आपने जो प्रोक्योरमेंट की स्कीम चलायी है उसमें बहुत सी खामियां हैं। आपने यहां कहा कि जो खेत बोया गया है उसी पर लेवी लगेगी, बन्जर या पड़ती जमीन पर लेवी नहीं लगेगी। मगर गांवों में हो उसके विपरीत रहा है। जो जमीन ऊसर और बंजर लिखी हुई है, जहां कोई उपज हुई ही नहीं है, आपके कर्मचारी उन किसानों से भी गल्ला वसूल कर रहे हैं। अगर आपका यह खयाल है कि ७-८ परसेंट को खत्म करके कोई हानि नहीं होगी, आपकी यह सरकार चलती रहेगी, तो मैं कहना चाहता हूं कि यह कोई प्रजातांत्रिक ढंग नहीं है। यह तो एक ऐसा ढंग है जिसे एक फासिस्ट ढंग कहा जा सकता है। श्रीमन्, यह कोई ऐसा ढंग नहीं कहा जा सकता है जिसमें प्रजातंत्र की आस्था हो, इस पर विचारिये।

राज्य व्यापार की बात कम्युनिस्ट सदस्य बहुधा कहा करते थे परन्तु इसके लिये इस बजट में केवल चौसठ हजार की थोड़ी सी धनराशि रक्खी गई है। पता नहीं उससे क्या प्रयोग करना चाहते हैं, या यों ही चौंसठ हजार रुपये इधर उधर कर देना चाहते हैं। इस सम्बन्ध में ठोस योजना बनानी चाहिये तभी स्टेट ट्रेडिंग की योजना आगे बढ़ सकती है। मैं आपसे इसी सिलसिले में सोशल सर्विस के सम्बन्ध में जो कटौती की गई है कहना चाहता हूं। मेरा मतलब सोशल

[श्री राम लाल]

वेलफेयर प्रोग्राम से है। आज बीसवें साल जब हम देखते हैं कि सोशल वेलफेयर या सोशल सिक्योरिटी के प्रोग्राम में दिन प्रतिदिन और वर्ष प्रतिवर्ष आगे बढ़ना चाहिये, परन्तु उसमें वर्ष प्रतिवर्ष कटौती होती जा रही है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सारे समाज को सुविधायें मिलनी चाहियें जो कि शिक्षा, चिकित्सा, बच्चों का पोषण है, यह सब उसी प्रोग्राम के अंग हैं। हरिजनों को जो शिक्षा सुविधायें मिलनी चाहियें थीं उनमें भी आप कटौती करने जा रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि आप कौन से समाजवादी या कल्याणकारी राज्य की कल्पना करके बैठे हैं। यह तो केवल कार्यकारी बजट है। आपने किया क्या? आपने तो गरीबों की नौकरियां ले लीं बस यही आपने एक काम दिखाया है। आप सोशल वेलफेयर या सेक्योरिटी के प्रोग्राम को कट कर रहे हैं। यह कौन सी बुद्धिमानी का काम है यह हमारी समझ में नहीं आता है।

श्री अध्यक्ष—

इस लाल संकेत को भी आप ले लीजिये।

श्री राम लाल—

श्रीमन्, दो तीन मिनट और दे दीजिये। मुझे आपसे निवेदन करना है कि जो पुलिस का बजट है उसमें काफी इजाफा हो रहा है। ज्यों २ दवा होती जाती है त्यों त्यों मर्ज बढ़ता ही जाता है। पुलिस का बजट और यह शक्ति सामर्थ्य इस सरकार के हाथ में देने का अर्थ वही है कि इसका दुरुपयोग हो रहा है। ऐसे आदमियों के हाथ में तलवार दे देना बड़ी खतरनाक चीज है, लेकिन उस पर भी पुलिस को तलवार दे देना और भी खतरनाक है।

कालागढ़ और बनारस के कांड जिस तरह हुए हैं, उससे ये क्या मुस्तहक हैं कि पुलिस का यह बजट पास किया जाय। अगर इसका उपयोग यही है कि जनता को त्रस्त किया जाय, स्त्रियों पर प्रहार किया जाय तो इसको कतई स्वीकार नहीं करना चाहिये। आप कहते हैं कि कालागढ़ में कुछ नहीं हुआ, यह तो यही बात है कि—"इस सादगी पर कौन न मर जाय ऐ खुदा, लड़ते हैं मगर हाथ में हथियार भी नहीं"। सैकड़ों मरे, घायल हुए और आपके हाथ में हथियार ही नहीं था। ये सब अजीबोगरीब बातें हैं। मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि यह बजट कतई न पास किया जाय।

गल्ला वसूली के बारे में पूर्ति मंत्री ने बड़े जोरदार शब्दों में बातें कहीं। लेकिन किसान जिस मजबूरी से गल्ला तैयार करता है उसे आप मुफ्त में लेना चाहते हैं, यह बहुत दिनों तक चलने वाला नहीं है। आज किसान जागेगा और फिर आप यह नहीं कह सकते कि आप यहां बैठे ही रहेंगे। आप भी नहीं बैठ सकते हैं और हम भी नहीं बैठ सकते हैं। गांव ने ली है अंगड़ाई और आप मुफ्त में किसानों का गल्ला जो लेना चाहते हैं, नहीं ले सकेंगे। यह अजीब बात है कि ८५ रुपये क्विंटल के हिसाब से तो आप गल्ला लेंगे और उसे १०० रु० के हिसाब से बेचेंगे यानी आप किसानों से मुफ्त में गल्ला लेकर उसे बनियों को और शहर के रहने वाले अच्छी हैसियत वालों को देंगे। आपको मालूम होना चाहिये कि किसानों के घरों में जो गल्ला है वह गांव भर का साझीदारी का सम्मिलित गल्ला है, मजदूरों का गल्ला है और उसी पर गांव की सारी अर्थ व्यवस्था चलती है। अगर आप भूमि का पुनर्विभाजन कर दें और उसका बटवारा हो जाय तब तो इस तरह की बात कुछ सम्भव हो सकती है अन्यथा यह प्रेनरी और गोदाम जो भूमिहीनों से भी सम्बन्धित है, उसका खात्मा हो जायगा और इस तरह से आप ८० प्रतिशत से अधिक लोगों का पोषण न करके शहरों में रहने वाले २० प्रतिशत लोगों का पोषण करने जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

अब कार्य-स्थगन प्रस्ताव और नियम ५१-५२ की कुछ सूचनायें जो मेरे पास आयी हैं, पहले मैं उनको लूंगा और उसके बाद यदि समय बचेगा तब इस पर विवाद जारी रहेगा।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--

मेरे पास जो एक काम रोको प्रस्ताव आया है वह माननीय अश्वनीकुमार चतुर्वेदी "राकेश" का है। इसको मैंने अस्वीकृत कर दिया है।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)--

श्रीमन्, इसको आप अवश्य मान लें।

श्री अध्यक्ष--

जो कुछ भी मैं करूंगा अपने विवेक के आधार पर करूंगा, इसके लिये किसी सिफारिश की जरूरत नहीं है।

माननीय राकेश जी, इंटरमीडिएट बोर्ड के परीक्षाफल के बारे में आपने जो यह प्रश्न उठाया है, इस तरह का प्रश्न प्रश्नों के द्वारा उठाया जा सकता है, इस दृष्टि से इसको मैंने अस्वीकृत कर दिया है।

श्री अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' (जिला मिर्जापुर)--

श्रीमन्, एक मिनट का मुझे मौका दें।

श्री अध्यक्ष--

माननीय राकेश जी, एक बात मैं बतला दूं कि मेरी इच्छा रहती है कि जब कोई माननीय सदस्य कोई प्रश्न उठावें तो जितना ज्यादा हो सके उनको अवसर दूं, लेकिन यह परम्परा ऐसी हो जायगी जो निभ नहीं सकेगी। अगर कोई माननीय सदस्य कार्य-स्थगन प्रस्ताव या नियम ५१-५२ का प्रश्न उठावें और उसे मैं अस्वीकृत कर दूं, फिर वह उसका औचित्य कहने लगें, गालिबन आप भी वही चाहते हैं, तो इस तरह से बड़ी कठिनाई हो जायगी।

श्री अश्वनीकुमार चतुर्वेदी 'राकेश'--

श्रीमन्, मैं यह चाहता हूं कि इंटरमीडिएट बोर्ड का परीक्षाफल निकल चुका है। किसी भी मुल्क में ९० प्रतिशत से कम लड़के सफल नहीं होते जब कि यहां ४६ प्रतिशत ही रिजल्ट हुआ है.....

श्री अध्यक्ष--

तो इसके लिये आप अल्पसूचित प्रश्न कर लें।

श्री अश्वनी कुमार चतुर्वेदी "राकेश"--

श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि कम से कम आप इसको नियम ५१ के अन्दर ही ले लें।

श्री अध्यक्ष--

माननीय शिक्षा मंत्री जी से आप बात कर लें। अगर वे इंटरमीडियट बोर्ड ऐक्ट के बारे में और परीक्षाफल के बारे में कोई बयान देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। लेकिन उनसे मैं इस सम्बन्ध में इस समय बात नहीं कर सकता। यदि उनको कुछ कहना हो तो कह लें, हो सकता है कि इसका महत्व अपेक्षाकृत कम हो।

श्री अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश'--

सम्भव है कि अपेक्षाकृत महत्व कम हो, लेकिन २५ प्रतिशत लोग अंग्रेजी में फेल हुए हैं।

श्री अध्यक्ष—

इसके लिये आप सवाल कर सकते हैं। शिक्षा मंत्री जी अगर कोई वक्तव्य देना चाहते हैं तो मैं उसका समर्थन करूंगा। बेहतर यह होगा कि आप उनसे बात कर लें। शिक्षा मंत्री को इसके लिये मैं बाध्य नहीं कर सकता कि वे बयान दें ही। यदि वे बयान देने के लिये तैयार हों तो ठीक है, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

खरीफ की बोवाई के लिये बीज के अभाव के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास कामरोको के अतिरिक्त नियम ५१ में तीन सुझाव आए हैं, जिनमें से मैंने एक स्वीकृत किया है माननीय गेंदासिंह जी का, जो इस प्रकार है :—

"मैं अध्यक्ष महोदय, की अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम ५१ के अन्तर्गत माननीय कृषि मन्त्री का ध्यान निम्नलिखित लोक महत्व के अविलम्बनीय महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। आशा है कि अध्यक्ष महोदय इसकी अनुमति प्रदान करेंगे। खरीफ की बोआई का समय बीत रहा है। गत वर्ष सूखे के कारण खरीफ का बीज लाखों किसानों के घरों में नहीं है और न तो सरकार की ओर से अब तक पर्याप्त बीज की व्यवस्था ही हो पाई है। ऐसी परिस्थिति में प्रदेश के अभावग्रस्त क्षेत्रों में लाखों एकड़ भूमि बीज के अभाव में बोये बिना रह जाने की आशंका से किसानों में व्याप्त बेचैनी से उत्पन्न गम्भीर परिस्थिति की ओर हम माननीय कृषि मन्त्री का ध्यान आकर्षित करते हैं।"

माननीय कृषि मन्त्री, उचित तो यह है कि इस पर अभी बयान दे दें।

न्याय मन्त्री (श्री श्यामलाल यादव)—

अगर कुछ समय दे दिया जाय तो अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष—

नियमों में सायंकाल ४ बजे ये प्रश्न लेने के लिए परिवर्तन करने का अभिप्राय यह था कि १० से ११ बजे ये सूचनायें मेरे पास आजायें। अगर मैं किसी को स्वीकार करता हूं तो उसे तभी सरकार के पास भेज देता हूं। उस से ४ बजे तक का समय सूचना का संकलन होने में इस्तेमाल होना चाहिए। खैर, कल ४ बजे वक्तव्य दे दें।

श्री श्यामलाल यादव—

ठीक है, कल ४ बजे हो जायगा।

नियम ५१ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ अन्य सूचनाएं

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

नियम ५१ में मैंने भी एक सूचना दी थी, उसे मन्त्री जी को भेज दें।

श्री अध्यक्ष—

संयोग से जो आप चाहते हैं मैं उसके आदेश दे चुका हूं। मैंने आपकी सूचना माननीय राजस्व मन्त्री जी के विशेष ध्यान हेतु प्रेषित कर दी है।

(डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी के खड़े होने पर)

मैं एक से ज्यादा सूचना स्वीकार नहीं कर सकता। आपकी सूचना मैंने आवश्यक कार्यवाही के लिए सम्बन्धित मन्त्री के पास प्रेषित कर दी है।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)—

कल से महिलायें अनशन कर रही हैं, ४८ घंटे हो गए। मेरा दुर्भाग्य है कि उसका आपने महत्व नहीं समझा।

श्री अध्यक्ष—

महत्व मैंने समझा। लेकिन मैं एक दिन में एक ही सूचना को स्वीकार कर सकता हूं। उसे आवश्यक कार्यवाही के हेतु मैंने मन्त्री जी को प्रेषित कर दिया है।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—

स्त्रियों का ४८ घंटे का तो बहुत लम्बा हो गया.....

श्री अध्यक्ष—

आप स्त्रियों के प्रति कोई उदारता नहीं दिखा रहे हैं। उनमें सहनशक्ति अधिक होती है।

श्री बीरेश्वर त्यागी (जिला मेरठ)—

मैंने भी एक दिया था।

श्री अध्यक्ष—

मैं यह समझा कि माननीय सदस्य बजट पर बोलने के लिए खड़े हुए हैं। मैं समझता हूं कि शायद ऐसा ही था, न ?

श्री बीरेश्वर त्यागी—

श्रीमन्, मेरा प्रस्ताव बहुत महत्वपूर्ण था, हजारों आदमी बेकार हैं।

श्री अध्यक्ष—

त्यागी जी मैं तो समझ रहा था कि वह मामला तो समाप्त हो गया। अब बजट पर बहस आरम्भ हो गयी है और उसी के लिए लोग खड़े हुए हैं। आप चाहें तो इस परिस्थिति से लाभ उठा सकते हैं और अपने विषय पर बोल सकते हैं।

(श्री बीरेश्वर त्यागी खड़े नहीं हुए।)

१९६७–६८ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (क्रमागत)

श्री त्रिवेणी (जिला आजमगढ़)—

अध्यक्ष महोदय.....

एक सदस्य—

श्रीमन्, जो पुराने सदस्य हैं उनका नाम तो आप जानते हैं, उनको बोलने का मौका मिल जाता है, लेकिन दुर्भाग्य से जो नए सदस्य हैं उनको अवसर नहीं मिल पाता।

श्री अध्यक्ष—

मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं। इस सदन के ४२४ सदस्य हैं। ५ दिन बजट पर सदन में वाद-विवाद होगा, जिनमें मन्त्रिगण भी बोलेंगे, माननीय नेता विरोधी दल बोल चुके हैं और बोलेंगे। मेरे लिए यह सम्भव नहीं है कि मैं सारे माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर दे सकूं और कभी सम्भव नहीं हुआ है। कुछ सदस्यों को प्रयास करने के बावजूद भी अवसर न मिल पाएगा। मैं उनसे क्षमा चाहूंगा अगर किन्हीं माननीय सदस्य को मैं अवसर न दे पाऊं। जिस कठिनाई की ओर मेरा ध्यान दिलाया गया है, वह आंशिक रूप से ठीक भी है, उसके लिए मैं आपके सहयोग का आवाहन करता हूं, लेकिन प्रश्नों के समय ही आपने देखा होगा कि मैंने

[श्री अध्यक्ष]

ऐसे कई माननीय सदस्यों को बुलाया जिनका नाम मैं नहीं जानता था। इसलिए आप विश्वास करें उस कारण से ऐसा नहीं हो सकता कि मैं किसी माननीय सदस्य का आवाहन न करूं।

श्री त्रिवेणी—

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मन्त्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उसके सम्बन्ध में मैं आपके माध्यम से अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूं और यह कहना चाहता हूं कि समाजवाद का नारा लगाने वाले हमारे साथी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उसमें समाजवाद का नाम तक नहीं है। दूसरी बात यह है कि यह बजट न तो किसानों का है, और न मजदूरों का है, तथा न तो उसका सम्बन्ध खेतिहर मजदूरों से ही है। कहा गया है कि इसमें सिंचाई की व्यवस्था खास तौर से है लेकिन उसकी भी समुचित व्यवस्था इसमें नहीं है। एक वर्ष में एक या दो से ज्यादा ट्यूबवेल भी एक जिले में नहीं आता है। सिंचाई के लिए किसानों में हाहाकार मचा हुआ है।

तीसरी बात यह है कि इस सरकार से यह बड़ी आशा थी कि साढ़े छः एकड़ तक जमीन की लगान माफ कर दी जायगी और १०वीं क्लास तक के विद्यार्थियों की फीस माफ कर दी जायगी। गवर्नर के भाषण के समय यही नारा इन लोगों की तरफ से लगाया गया था और १९ सूत्री कार्यक्रम की बहुत दुहाई दी गयी और कहा गया कि उस पर ही सरकार को खत्म कर दिया गया। लेकिन आज तक एक भी कार्य पूरा नहीं किया गया है। अगर बजट के द्वारा एक भी कार्य पूरा किया जाता तो हमें कुछ सन्तोष हो सकता था, लेकिन इस बजट को देखने से मालूम होता है कि यह बजट केवल कागज की एक किताब बनाकर उस पर कुछ लिख दिया गया है, इसमें न तो किसानों का संतुलन है, न मजदूरों का संतुलन है और मैं कह सकता हूं कि न व्यापारियों का ही इस में कोई संतुलन है। इससे किसी तरह से जनता का और प्रदेश का भला न होगा, बल्कि यह प्रदेश के लिए और घातक साबित होगा। जो नारे इस सरकार के लोग कुर्सी पर बैठने से पहले लगाते थे उन को अब भूल गए हैं, वह नारा लगाते थे कि यह बड़ा निकम्मा शासन है, ३ पांव का राशन है, मुझको रोजी रोटी दो वर्ना कुर्सी छोड़ दो। आज स्वास्थ्य मन्त्री जी यहां नहीं हैं, परसों वह बड़े जोर से आवाज लगा रहे थे और दावा कर रहे थे कि हमारा बजट समाजवादी होगा और शुद्ध समाजवाद का पूरा संतुलन उसमें होगा। मैं वित्त मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जब इस में किसान का, मजदूर का और किसी भी वर्ग का हित नहीं है तो फिर इस बजट से जनता की भलाई कैसे हो सकती है? पहले नारा लगाया गया कि इस समय किसान को दो चीजों की खास जरूरत है अगर वे दो चीजें पूरी हो जायें तो कृषि उत्पादन में वे मेहनत से काम करेंगे और इस तरह से उपज बढ़ जायगी। इसमें कुल २० करोड़ रुपया लघु ट्यूबवेल्स व लघु सिंचाई योजनाओं के लिए रखा गया है जबकि बिहार प्रदेश हमारी सरहद पर है आबादी यहां से कम है तथा भूमि भी कम है पर स्माल ट्यूबवेल और लघु सिंचाई योजनाओं के लिए ४० करोड़ रुपया रखा गया है। जहां की ८५ प्रतिशत जनता खेती पर निर्भर है वहां पर लघु सिंचाई कार्य के लिए २० करोड़ रुपया बहुत ही कम है।

आप तो श्रीमन्, इन्टरमीडिएट बोर्ड और माध्यमिक परिषद् के विशेषज्ञ हैं और वहां की सब बातें जानते हैं यहां पर विद्यार्थियों की तादाद सब से अधिक है और उनका अनुपात अधिक है, यहां के गरीब विद्यार्थी हैं जिन के लिए कि नारा लगाया गया तथा बहुत लोगों ने आवाज उठाई माध्यमिक शिक्षक परिषद् से भी आवाज आई मैनेजर असोसियेशन से भी आवाज आई कि दसवीं कक्षा तक की फीस माफ की जाय, लेकिन इस बजट में उसका कोई संकेत नहीं है।

हमारे यहां सबसे गरीब वर्ग हरिजनों का है और पिछड़े वर्ग लोगों का है जिनमें वाकई बहुत गरीबी आज तक है, उनके लिए भी इस बजट में कोई प्राविधान नहीं है। मालूम होता है कि हरिजन कल्याण विभाग ही इस बजट से निकाल दिया गया है और उन का कोई जिक्र

इसमें नहीं है। न इसमें सवा ६ एकड़ तक के लगान की छूट का ही कोई जिक्र है। १९ सूत्री कार्यक्रम में भी समाजवादी लोग समाजवाद का नारा लगाते हैं और रोज बयान देते हैं कि हम यह करेंगे, लेकिन बजट में कुछ भी तो नहीं है।

मैं आपके द्वारा माननीय मन्त्री जी का और सिंचाई मन्त्री जी का ध्यान आजमगढ़ जनपद की तरफ दिलाऊंगा। पिछले साल जब यहां कांग्रेस सरकार थी तो ९६० नलकूप लगाये और बजट उन के लिए था। उन में से ३५० में बोरिंग हो चुकी है, लेकिन वे बिजली न मिलने से बेकार पड़े हैं। २,००० नलकूपों के लिए लोन बांटा जा चुका है पिछले बजट में, लेकिन बोरिंग का काम बिजली न मिलने से नहीं हो रहा है। कहा जाता है कि सरकार सिंचाई की समुचित व्यवस्था कर रही है, लेकिन जो किसान नलकूप लगाए भी हैं उन को बिजली नहीं दी जाती। मैं विशेष रूप से वित्त मन्त्री जी का ध्यान इस तरफ आकृष्ट करूंगा। जबकि विद्युत् मन्त्री एक तरफ कहते हैं कि बिजली और माइनर इर्रीगेशन के लिए सुविधा दे रहे हैं। एक तरफ जब कांग्रेस सरकार थी तो ४ फर्लांग तक भी खम्भे लाइन दिए जाते थे ५ हार्स पावर तक के लिए, लेकिन आज १ फर्लांग पर भी ५ हार्स पावर के लिए बिजली नहीं दी जा रही है। आजमगढ़ जनपद सब से गरीब है वहां कुछ इलाके ऐसे हैं जहां आज तक सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां एक नलकूप नहीं लगा है। वहां भी लैवी वसूल हो रही है जब कि खाद्य मन्त्री, जो आजमगढ़ गए थे तो उन्होंने कहा था कि ऐसे इलाके से लैवी वसूल नहीं की जाय जहां कि किसान गल्ला पैदा नहीं कर सके हैं। लालगंज तहसील, फूलपुर का दक्षिणी हिस्सा तीन वर्ष से लगातार सूखे से तबाह हो चुका है। यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि अगर उन इलाकों की हालत मिर्जापुर से खराब न हो तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। और अगर खराब हालत है तो यह सरकार इस्तीफा दे दे। कई बार मैंने कहा कि ये इलाके पानी के बगैर मर रहे हैं, ३, ४ हजार एकड़ के गांव हैं जहां एक भी कुआं नहीं है। लेकिन वहां भी सरकार लैवी वसूल कर रही है। डाक्टर सीता राम जब वहां गए थे तो उन्होंने जो रिपोर्ट दी है वह रिपोर्ट माननीय माल मन्त्री कहते थे कि जनहित में नहीं है। वह तो मुख्य मंत्री ने कहा कि यह रिपोर्ट सदन के सामने पेश की जाय। मैं बताना चाहता हूं कि मिर्जापुर के कुछ इलाके इतने खराब हैं उससे भी खराब इलाके हमारे आजमगढ़ जनपद में हैं, जिनके मैंने नाम लिए।

मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर इस सरकार में ईमानदारी है और किसानों और मजदूरों की भलाई करने की ताकत है तो माननीय मुख्य मन्त्री स्वयं देख लें कि कीचड़ से पानी निकाल कर आदमी पानी पी रहा है। बरेली का सड़ा हुआ चोटा किसानों को बाजार में नहीं मिल रहा है। वहां का मजदूर वर्ग जो बैल दायं चलाते हैं उन के गोबर में से अन्न निकाल कर खा कर अपनी जिन्दगी बसर कर रहे हैं। उस इलाके की तरफ विशेष आप ध्यान दें। मुझे कोई एतराज नहीं है कि पहाड़ी इलाकों का विकास हो। वह होना चाहिए सुरक्षा की दृष्टि से। लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो गरीबी है, गुरबत है उस को भी नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता है। लेकिन इस बजट में पहाड़ी इलाकों का तो जिक्र है पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के बारे में जिक्र नहीं आया है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि ५, ७ जिले ऐसे हैं जहां आज भी धूल उड़ रही है, जहां के लोग सड़ा हुआ चोटा पाते हैं। कृषि के विशेषज्ञों का कहना है वह चोटा ऊसर गलाने के लिए डाला जाता है। तो क्या सरकार इन्सान गलाने के लिए चोटा बिक वा रही है? मैं पूछना चाहता हूं कि अगर वह इलाका इस दुख में है तो सरकार क्या कदम उसका दुख दूर करने के लिए उठा रही है? यह बजट बिल्कुल मजाक सा बना हुआ है। न समाजवादी व्यवस्था इसमें है और न किसी और तरह की व्यवस्था इसमें है। न इसमें कोई संतुलन है। अधिकारियों ने इसे बना कर दे दिया है और वित्त मन्त्री जो अपने को बड़ा समाजवादी कहते थे इसे यहां ले आए हैं। मेरे जो साथी अभी बोल रहे थे, उनके ही जैसे लोगों के लिए इकबाल का एक शेर याद आ जाता है:

"गद्दारिये वतन की सेला सिर्फ साइकिल
ईमां ही बेचना है तो सस्ता न कीजिये।"

[श्री त्रिवेणी]

इस हाउस की जो परम्परा रही है वह वही है जो आचार्य जी ने डाली जो कि हमारे राजनीतिक गुरु थे। आचार्य जी ने असेम्बली से इस्तीफा दिया था। पन्त जी और बड़े-बड़े नेताओं ने यह निवेदन किया उनसे कि इस्तीफा मत दीजिए। उन्होंने कहा कि हाउस की मर्यादा भंग हो जायगी। उसी फैजाबाद जिले से उन्होंने चुनाव लड़ा और बाबा राघवदास से वह हार गये। लेकिन आज ऐसे लोग हैं जो उल्टी सीख दे रहे हैं, उल्टी बात कर रहे हैं। जिस सिम्बल से वह चुनाव लड़े थे उसके साथ, और जनता के साथ धोखा कर रहे हैं, गद्दारी कर रहे हैं। अगर उस सिम्बल की, स्वाभिमान की, हाउस की मर्यादा की उनको रक्षा करनी है तो उनको हमारी चुनौती है कि वे इस्तीफा दे कर मैदान में आयें और फिर से इलेक्शन लड़ कर हाउस में बैठें। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का विरोध करता हूं क्योंकि यह जनहित में नहीं है।

*श्री हुकमसिंह (जिला आगरा)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बजट मजदूरों किसानों का बजट है, गरीब जनता का बजट है जिन्होंने इस संयुक्त विधायक दल की सरकार को यहां स्थापित किया है और उन्हीं के उत्थान के लिए यह बजट यहां लाया गया है। जब कांग्रेस सरकार से उनकी आशायें ध्वस्त हो गयीं तब उन्होंने कांग्रेस को अपदस्थ करने के लिए कदम उठाया और संयुक्त विधायक दल की सरकार को मौका दिया और यह जो बजट आज पेश है इसमें जनता की खुशियां उछल रही हैं। मुझे मौका मिला है लोगों से बातचीत करने का। इक्के वाले और तांगे वाले यह कहते सुने गए कि हम आशा लगाए हुए हैं कि बजट के पास होते ही भाव नीचे गिरेंगे। अगर किसी भी प्रकार संयुक्त विधायक दल की सरकार गिरी तो इस प्रदेश का भला नहीं होगा और गरीब जनता इसको एक मिनट के लिए भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं होगी। इसकी वजह है कि बीस साल में पूंजीपति ऊपर उठते गए और गरीब-गरीब बनता गया। एक तरफ अमीर का पहाड़ बना और दूसरी तरफ गरीब का पाताल बना। संयुक्त विधायक दल की सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं बड़े-बड़े पूंजीपतियों को दबाने के लिए और गरीबों को आशायें बंधी हैं। आज बीस साल के बाद जनता यह मानती है कि कोई शासन है। आज जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, चाहे वे पूंजीपति हों या पिछली सरकार के पालतू रहे हों, चाहे ब्लैक मार्केटियर हों, सब घबराये हुए हैं। इस प्रदेश में चन्द्रभानु जी गुप्त पूंजीपतियों के सब से बड़े एजेन्ट हैं जिन्होंने पिछली सरकार को कायम करने के लिए कई लोगों को खरीदा। इतना ही नहीं, मुझे सूचना मिली है कि एस० बी० डी० की सरकार को गिराने के लिए कानपुर के पूंजीपतियों ने दो करोड़ रुपया देने का वायदा किया है।

(व्यवधान)

श्रीमन्, एक बात और कहना चाहता हूं कि बाबू नवलकिशोर जी ने जो एक सूचना दी वह बहुत गलत थी। उन्होंने कहा कि सी० आई० डी० की खुफिया रिपोर्ट है कि उनका जं में कोई ऐसी फाइल नहीं है। इस प्रकार की बात उन्हें नहीं कहनी चाहिए थी। क्या उन्होंने उस रिपोर्ट को पढ़ा है? सी० आई० डी० जो रिपोर्ट देगी वह इन बेंचों को देगी, उन बेंचों को नहीं देगी।

श्री नवलकिशोर---

आन ए प्वाइंट आफ आर्डर। मेरा प्रश्न व्यवस्था का यह है कि मैं आपसे केवल इतना प्रोटेक्शन चाहता हूं कि माननीय सदस्य कम से कम मैंने जो कुछ कहा है उसको तोड़ मरोड़ कर न कहें वरना जो चार्ज वह मेरे ऊपर लगा रहे हैं वह उनके ऊपर आयद हो जायगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैंने केवल इतनी बात कही कि माननीय मुख्य मन्त्री जी में इतनी कर्टेसी नहीं आयी कि जब उन्होंने बयान भी दे दिया और रिपोर्ट के बाद कन्विन्स्ड हैं कि उसमें कोई चीज नहीं थी तो कम से कम फार्मल एपालोजी मांगते।

श्री अध्यक्ष—

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं, यह तो सेल्फ एक्सप्लेनेशन हुआ।

श्री हुकमसिंह—

पिछली सरकार के कारनामों में जो घपले हुए उनको आज प्रकाश में लाने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं इसलिए बड़े-बड़े ब्लैकमार्केटियर्स ने और बड़े-बड़े भ्रष्टाचारी अफसरों ने एक षड़यन्त्र बनाये हुये है कि इस सरकार को गिराया जाय। लेकिन मैं इस प्रदेश की जनता को और इस हाउस को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त विधायक दल की सरकार इतने मजबूत पैरों पर खड़ी है कि इसको कोई गिरा नहीं सकता। यहां पर बाबू चन्द्रभानु गुप्त जिस वक्त चीफ मिनिस्टर थे तो उनके दामाद ने मेरे जिले आगरे में जो घपले किए वे बहुत बड़े घपले हैं। उनकी जांच होनी जरूरी है, यह मैं इस सरकार से कहना चाहूंगा। इसलिए कि वे मुख्य मन्त्री के दामाद थे और अफसर उनको बहुत बड़ा समझते थे।

श्री अध्यक्ष—

जो व्यक्ति यहां पर मौजूद नहीं हैं, उनका नाम लेकर कोई जिक्र न करें।

श्री हुकमसिंह—

श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि.....

श्री नवलकिशोर—

मान्यवर, जो मनुष्य बाल-ब्रह्मचारी है, उसका क्या कोई दामाद हो सकता है? इसकी व्यवस्था दे दें?

श्री अध्यक्ष—

इस पर किसी बाल-ब्रह्मचारी की व्यवस्था होती तो ज्यादा अच्छा होता।

श्री हुकमसिंह—

उद्योग विभाग द्वारा जो लाइसेन्स दिये गये और जो कन्ट्रोल की दुकानें खोली गयीं उनमें बहुत बड़ा घपला किया गया है। इतना ही नहीं उनमें सारे उनके रिश्तेदार ही होते थे। सही बात यह है कि २० साल के बाद किसानों की हुकूमत इस प्रदेश में आई है। सेठों की हुकूमत २० साल बाद खत्म हुई है। आज जनता ने एहसास किया और इस सेठों की सरकार को खत्म कर दिया।

श्रीमन्, जहां तक इस सरकार का सवाल है, उससे मुझे शिकायत है। मैं माननीय वित्त मन्त्री जी और मुख्य मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि इस प्रदेश में चम्बल घाटी के नाम से एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। इस क्षेत्र में पुलिस का और डाकुओं का दोहरा शासन है। एक तरफ तो डाकुओं की फौज यहां पर घूमती है और दूसरी तरफ पी० ए० सी० तैनात है। हमारी केन्द्रीय सरकार ने यहां की जनता को राहत देने के लिए कुछ कदम उठाए हैं। माननीय विनोबा भावे ने जो मुल्क के एक बहुत बड़े महात्मा हैं उन्होंने कुछ डाकुओं को प्रयत्न करके सरकार के सामने पेश कराया है। लेकिन इससे यहां की समस्या हल नहीं होती है। आजादी मिलने के बाद चम्बल घाटी की जनता आशा लगाए हुए थी कि अब जनता की सरकार आयेगी और और वह हमारी समस्याओं को हल करेगी। लेकिन २० साल तक इस प्रदेश में सेठों की सरकार कायम रही और उसने यहां की जनता की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। उसको सिवाय

[श्री हुकुमसिंह]

अपना धंधा करने और ब्लैक मार्केटिंग करने से ही फुर्सत नहीं थी। लेकिन आज जब यह सरकार आई तो जनता की आशा बढ़ी। आगरा में फतेहाबाद और बाह का इलाका ऐसा है जहां आज भी हिन्दुस्तान के मशहूर डाकू रहते हैं। वहां की जनता इनसे बहुत दुखी है और उसको आशा थी कि सेठों की सरकार के जाने के बाद अब यह सरकार कुछ न कुछ अवश्य करेगी। लेकिन उसकी सारी आशायें ध्वस्त हो गई। कारण यह है कि जब तक इस क्षेत्र में आवागमन का प्रबन्ध नहीं किया जायगा ट्यूबवेल नहीं लगाए जायेंगे, शिक्षा का प्रबन्ध नहीं किया जायगा तब तक यहां की समस्या हल नहीं हो सकती है। एक नहीं चाहे हजार विनोबा भावे आ जायं दोहरा शासन खत्म करके जनता को डाकुओं और पुलिस के जुल्म से बचाया जाय यहां पर करोड़ों रुपया खर्च करके इसका बाकायदा विकास और प्लानिंग किया जाय इस क्षेत्र में जहां सौ डेढ़ सौ फीट गहरा पानी है। इस क्षेत्र में जहां यमुना चम्बल के खारों में आज तक किसी मन्त्री को जाने की हिम्मत नहीं हुई, वहां की जनता की बराबर अवहेलना की गयी है। उस क्षेत्र की जनता ने भारी बहुमत से कांग्रेस के सेठों को हरा कर, १५ हजार वोटों से बाबू चन्द्रभानु गुप्त के सेठ बन्सल को हराया, १५ हजार वोट से हराने के बाद मुझे वहां की जनता ने इस लिए वोट दिया था कि सेठों को हरा कर किसान मजदूरों की सरकार कायम होगी और इस क्षेत्र के लिए विशेष ध्यान दिया जायगा, लेकिन मेरे ऊपर भारी बोझ पड़ा जब इस क्षेत्र की जनता ने कहा, कि इस क्षेत्र के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया, बीस साल तक चम्बल घाटी क्षेत्र की अवहेलना की गयी। जिस उत्थान के लिए भारत सरकार की आंखें लगी हुई हैं, बड़े बड़े महात्मा जहां जाते हैं, मैं उस क्षेत्र की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि किसी न किसी प्रकार उस क्षेत्र की जनता का ध्यान रखा जाय। वहां पर सड़कों और दूसरी सुविधाओं का प्रबन्ध किया जाय।

मैं फिर से इस प्रदेश के किसान बजट का भारी समर्थन करता हूं और हृदय से स्वागत करता हूं। अब इन सेठों की सरकार आने वाली नहीं है। किसान मजदूरों की सरकार रहेगी।

श्री अध्यक्ष—

अब हम उठते हैं कल ११ बजे तक।

(इसके बाद सदन ४ बजकर ५८ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
२० जून, १९६७।

नत्थी 'क'

(देखिये तारा० प्र० ११ का उत्तर पीछे पृष्ठ २२२ पर)

नत्थी किया गया व्यौरा

जिला आगरा तहसील किरावली में तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित स्थानों का विद्युतीकरण हो चुका है। फतेहपुर सीकरी, गुड़ की मंडी, कोरई किरावली, पूरामना, अछनेरा, माहौर तथा बरौदा।

रीमा, बहरावली, आथूपुर, जैनगर, तथा बीरा आदि गांवों का भी विद्युतीकरण के हेतु सर्वेक्षण किया गया, परन्तु आर्थिक दृष्टि से इनका विद्युतीकरण उपयुक्त नहीं पाया गया।

प्रेमचन्द अग्रवाल

नत्थी "ख"

(देखिये पीछे पृष्ठ २४३ पर)

उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय अल्पकालिक व्यवस्था संशोधन विधेयक, १९६७

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २२, १९६३

उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, १९६३ का संशोधन करने के लिए,

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के अट्ठारहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:

संक्षिप्त नाम

१—यह अधिनियम, उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, १९६७ कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २२, १९६३ की धारा ३ का संशोधन

२—उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, १९६३ की धारा ३ में अंक तथा शब्द "३० जून, १९६७" के स्थान पर अंक तथा शब्द "३० जून, १९६८" रख दिये जायें।"

उद्देश्य और कारण

टाउन एरिया कमेटी रेवती, जिला बलिया का निर्वाचन राज्य के अन्य स्थानीय निकायों के सामान्य निर्वाचन के साथ ही साथ नवम्बर, १९६४ में हुआ था। इस टाउन एरिया कमेटी के कुछ वार्डों का निर्वाचन-फल, रिट-याचिका पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा रोक दिया गया था। इसलिए, टाउन एरिया कमेटी, रेवती के कार्यकाल को, जो ३१ दिसम्बर, १९६४ को समाप्त होने वाला था, समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, १९६३ के उपबन्धों के अधीन ३१ दिसम्बर, १९६६ तक बढ़ा दिया गया। चूंकि, उच्च न्यायालय द्वारा रिट का निस्तारण नहीं किया गया, इसलिये उत्तर प्रदेश स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, १९६६ द्वारा कार्यकाल को और आगे ३० जून, १९६७ तक बढ़ा दिया गया।

२—उच्च न्यायालय ने रिट याचिका पर अभी तक अन्तिम निर्णय नहीं दिया है और इसके द्वारा दिया गया स्थगन आदेश अभी तक प्रवृत्त है। अतएव, उक्त अधिनियम के उपबन्धों का उचित रूप से, संशोधन करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है। जिससे कि सरकार इस कमेटी के कार्यकाल को एक वर्ष के लिए और बढ़ा सके।

तदनुसार, यह विधेयक पुरः स्थापित किया जाता है।

बरमेश्वर पाण्डे,
स्वायत्त शासन मन्त्री।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी० एस० यू० पी० ए० पी० ४० एल० ए०—१९६७—८४६।